सोवियत संघ

१०० प्रश्न और उनके उत्तर

C NO - 3283
६५१३.
V58
152L7

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

Y58 3283
152L7

USSR: 100 questions and Answers.

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

V58
152L7
3283

SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR
(LIBRARY)
JANGAMAWADIMATH, VARANASI

Please return this volume on or before the date last stamped
Overdue volume will be charged 1/- per day.

सोवियत भूमि पुस्तिका
१९७७

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

Y58 3283
152L7

USSR: 100 questions
and Answars.

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

१०० प्रश्न और उनके उत्तर

1917-1977

सोवियत भूमि पुस्तिका
१९७७

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

USSR : 100 Questions And Answers
Hindi
1977
Price : 50 Paise

V58
152L7

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 3283

आर. जी. ओकुलोव द्वारा सोवियत संघ के भारतस्थित दूतावास के सूचना विभाग के लिए २५ बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-१ से प्रकाशित तथा मर्करी प्रिंटर्स, ६०२ चर्खेवालान, दिल्ली में मुद्रित ।

मूल्य : ५० पैसे

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री
नोवोस्ती प्रेस एजेंसी के सौजन्य से

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विषय-सूची

१. सोवियत राज्य, कम्युनिस्ट पार्टी
और ट्रेड यूनियन ८

२. अर्थशास्त्र, नियोजन, रोजगार ३२

३. प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान ५३

४. जीवन स्तर ६५

५. समाज और नागरिक अधिकार ७६

६. शिक्षा और कला १००

७. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग १०८

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जो आधे यूरोप और एक-तिहाई एशिया में, कुल मिला कर धरातल के एक-छठे स्थल भाग में फैला है। यह देशांतर के १७२ से अधिक अंशों में व्याप्त है तथा उत्तरी गोलार्ध की लगभग पूरी चौड़ाई को आच्छादित किये हुए है। इसके पूर्व और पश्चिम के सुदूरतम छोर एक-दूसरे से इतनी दूरी पर हैं कि जब एक छोर पर प्रातःकाल सूर्योदय होता रहता है तो दूसरे छोर पर सायंकाल सूर्यास्त होता रहता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को इस देश के पूरे फैलाव के आर-पार यात्रा करने में एक सप्ताह से अधिक लग जाता है।

उत्तर का शाश्वत आर्कटिक हिमक्षेत्र दक्षिण के ट्रांसकॉकेशियाई उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है तथा उमस से भरा तुर्कमेनियाई मरुक्षेत्र जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक फैला साइबेरियाई ताइगा से बिल्कुल भिन्न है। पामीर और तिएन शान पर्वतशिखर बादलों के पार तक चली जाती हैं तो उक्राइन और कजाख्स्तान में चौरस मैदान बिछे हैं। देश के भूदृश्य और जलवायु की विविधता सचमुच अपरिसीम है। जिस समय मध्य एशियाई वादियों में मई का सूर्य वायु को ३० डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देता है, सुदूर उत्तर में ठंड इतनी कठोर पड़ती रहती है कि धातु शीशे की तरह भंगुर हो जाती है और मशीनें टूट-फूट जाती हैं।

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जिसे अक्सर अभी भी रूस पुकारा जाता है। लेकिन यह सर्वथा सही नहीं है। रूस अथवा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र उन पंद्रह समान संघीय जनतंत्रों में से मात्र एक, गोकि सबसे बड़ा है, जो सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अंतर्गत हैं।

सोवियत संघ के २६ करोड़ नागरिक १३० भाषाएं बोलते हैं और उनके पास पांच भिन्न-भिन्न वर्णमालाएं हैं। लेकिन इससे उन्हें एक-दूसरे को पूरी तरह समझने में, कठिनतम उत्तरदायित्व को संयुक्त रूप में निभाने तथा देश की संपदा का उत्पादन करने और नयी, सोवियत संस्कृति का विकास करने में कोई विघ्न नहीं पड़ता।

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जिसने साठ साल पहले एक समाजवादी समाज का निर्माण करने के अभूतपूर्व पथ पर कदम बढ़ाये थे। और उस समय वह प्राविधिक और आर्थिक दृष्टि से उद्योग संपन्न पूंजीवादी देशों से पचास या सौ साल पीछे था। उसकी तीन-चौथाई जनसंख्या लिख या पढ़ भी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विषय-सूची

१. सोवियत राज्य, कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन ८

२. अर्थशास्त्र, नियोजन, रोज़गार ३२

३. प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान ५३

४. जीवन स्तर ६५

५. समाज और नागरिक अधिकार ७६

६. शिक्षा और कला १००

७. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग १०८

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जो आधे यूरोप और एक-तिहाई एशिया में, कुल मिला कर धरातल के एक-छठे स्थल भाग में फैला है। यह देशांतर के १७२ से अधिक अंशों में व्याप्त है तथा उत्तरी गोलार्ध की लगभग पूरी चौड़ाई को आच्छादित किये हुए है। इसके पूर्व और पश्चिम के सुदूरतम छोर एक-दूसरे से इतनी दूरी पर हैं कि जब एक छोर पर प्रातःकाल सूर्योदय होता रहता है तो दूसरे छोर पर सायंकाल सूर्यास्त होता रहता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को इस देश के पूरे फैलाव के आर-पार यात्रा करने में एक सप्ताह से अधिक लग जाता है।

उत्तर का शाश्वत आर्कटिक हिमक्षेत्र दक्षिण के ट्रांसकॉकेशियाई उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है तथा उमस से भरा तुर्कमेनियाई मरुक्षेत्र जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक फैला साइबेरियाई ताइगा से बिल्कुल भिन्न है। पामीर और तिएन शान पर्वतशिखर बादलों के पार तक चली जाती हैं तो उक्राइन और कजाख्स्तान में चौरस मैदान बिछे हैं। देश के भूदृश्य और जलवायु की विविधता सचमुच अपरिसीम है। जिस समय मध्य एशियाई वादियों में मई का सूर्य वायु को ३० डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देता है, सुदूर उत्तर में ठंड इतनी कठोर पड़ती रहती है कि धातु शीशे की तरह भंगुर हो जाती है और मशीनें टूट-फूट जाती हैं।

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जिसे अक्सर अभी भी रूस पुकारा जाता है। लेकिन यह सर्वथा सही नहीं है। रूस अथवा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र उन पंद्रह समान संघीय जनतंत्रों में से मात्र एक, गोकि सबसे बड़ा है, जो सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के अंतर्गत हैं।

सोवियत संघ के २६ करोड़ नागरिक १३० भाषाएं बोलते हैं और उनके पास पांच भिन्न-भिन्न वर्णमालाएं हैं। लेकिन इससे उन्हें एक-दूसरे को पूरी तरह समझने में, कठिनतम उत्तरदायित्व को संयुक्त रूप में निभाने तथा देश की संपदा का उत्पादन करने और नयी, सोवियत संस्कृति का विकास करने में कोई विघ्न नहीं पड़ता।

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जिसने साठ साल पहले एक समाजवादी समाज का निर्माण करने के अभूतपूर्व पथ पर कदम बढ़ाये थे। और उस समय वह प्राविधिक और आर्थिक दृष्टि से उद्योग संपन्न पूंजीवादी देशों से पचास या सौ साल पीछे था। उसकी तीन-चौथाई जनसंख्या लिख या पढ़ भी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नहीं सकती थी। इसी के साथ देश की घोर आर्थिक तबाही, अकाल और गरीबी को जोड़ दीजिए—जो प्रथम विश्व युद्ध और गृह युद्ध के भीषण कुपरिणाम थे। और फिर संसार में मजदूरों और किसानों के इस प्रथम राज्य का शैशवावस्था में ही गला घोंट देने पर तुली पूंजीवादी शक्तियों की शत्रुतापूर्ण घेरेबंदी।

उस देश के जनगण को जो विदेशियों को एक रहस्यपूर्ण सुषुप्त दैत्य प्रतीत होता था, इन सारी चीजों तथा और भी काफी कुछ चीजों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। साठ साल पहले उस समय ऐसे बहुत ही थोड़े से विदेशी थे जो यह विश्वास करते थे कि यह सामाजिक "प्रयोग" सफल हो सकता है।

लेनिन की पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनता ने अब तक के एक अनखोजे पथ पर कदम बढ़ा दिये। उसने सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए एक विकसित समाजवादी समाज का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली। उनकी सफलताओं तथा गलतियों ने जिनसे पथ के किसी भी अन्वेषी के लिए बच सकना असंभव है, ऐसा ऐतिहासिक अनुभव प्रस्तुत किया जो आज अन्य जनगण के लिए उपयोगी है।

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जहां आज मोटे तौर पर संसार का एक-पंचमांश औद्योगिक उत्पादन होता है। वह आज निम्नलिखित में दुनिया में अग्रणी है :

— इस्पात और तेल,

— ट्रैक्टर और खनिज उर्वरक,

— राष्ट्रीय अर्थतंत्र में पूंजीगत निवेश और गृह निर्माण,

— उत्पादन और जीवनमान की सुस्थिर वृद्धि दरें।

सोवियत संघ वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का नेता बन गया है। उसके पास संसार के अन्य किसी भी देश से ज्यादा अनुसंधानकर्ता और इंजीनियर हैं।

सोवियत संघ ने अंतरिक्ष युग की अगवानी की। संसार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ में बनाया गया। उसके अंतरिक्ष राकेटों ने पहले-पहल पृथ्वी के गुरुत्व को पार किया तथा अंतर्ग्रहीय उड़ान पथों पर यात्रा की। यूरी गगारिन अंतरिक्ष में उड़ने वाला प्रथम पार्थिव मानव था।

सोवियत जन अधिकाधिक पूर्ण रूप में समाजवाद के लाभों का उपभोग कर रहे हैं। देश ने बहुत पहले ही आर्थिक संकटों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का खात्मा कर दिया था। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों की कीमतें तथा किराये और भाड़े स्थिर हैं तथा आमतौर पर संसार में कहीं की भी तुलना में निम्नतम हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह पुस्तक एक ऐसे देश के बारे में है जो अपने उदय के बाद से सदा ही भिन्न समाज व्यवस्थाओं वाले राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहजीवन तथा सभी राष्ट्रों के बीच समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापक सहयोग की नीति को लगन के साथ और अथक रूप में अनुसरण करता रहा है और निरस्त्रीकरण के लिए जोरदार ढंग से काम कर रहा है।

सोवियत संघ को द्वितीय विश्व युद्ध की असली मार सहनी पड़ी और उसने फासिज्म को शिकस्त देने में निर्णायक योगदान किया। जन-धन की अपार क्षति उठा कर युद्ध में विजय प्राप्त की गयी थी। अर्थतंत्र के क्षेत्रों में हुई क्षति को पूरी करने तथा उत्पादन के युद्ध-पूर्व स्तर को बहाल करने के लिए देश को अपार यत्न करना पड़ा।

सोवियत संघ को लेकर विदेशों में बेशुमार सवाल पूछे जाते हैं। इनमें वे भी सवाल शामिल हैं जो राजकीय कार्य से या पर्यटन के लिए विदेश यात्रा करने वाले सोवियत नागरिकों से पूछे जाते हैं, तथा वे सवाल भी जो हमारी पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों के पाठकों द्वारा नोवोस्ती प्रेस एजेंसी को भेजे जाते हैं। सवालों के इस अंबार में से हमने उन सौ सवालों को चुना है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते रहे हैं तथा सोवियत गृह और विदेश नीति की साफ समझदारी पेश करने के लिए जिनका उत्तर देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

यह पुस्तक सांगोपांग होने का दावा नहीं करती। दरअसल हम यह आशा करते हैं कि यह अपने पाठकों के साथ हमारे संवाद की शुरूआत होगी और हम अपने बाद के अंकों में उनके और आगे सवालों का सहर्ष उत्तर देना चाहेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

१. सोवियत राज्य, कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनें

समाजवाद ने पिछले ६० वर्षों में जनता को क्या दिया है ?

इस सवाल के लिए लंबी बहस अपेक्षित है और इस पुस्तक के अन्य भागों में हमने इस पर अधिक विस्तार से प्रकाश डाला है। किंतु संक्षेप में समाजवाद की उपलब्धियों का निचोड़ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

पुराने जमाने में लोग जिसका केवल स्वप्न देख सकते थे, समाजवाद ने उसे हकीकत में बदल दिया हैं :

— इसने सोवियत जनता को अपने देश का सच्चा, सामूहिक स्वामी बना दिया है;

— इसने उन्हें हर प्रकार के शोषण से मुक्त कर दिया है;

— इसने वर्गगत, नस्लगत, राष्ट्रीय और अन्य विशेषाधिकारों का खात्मा कर दिया है तथा यथार्थ सामाजिक समानता सुनिश्चित कर दी है;

— इसने एक सर्वथा नयी किस्म के जनवाद की रचना कर दी है जिसने प्रत्येक नागरिक को कारखानों, नगरों और वस्तुतः पूरे समाज के संचालन में भाग लेने का अवसर प्रदान कर दिया है;

— इसने सोवियत नागरिकों को अपनी विशेषता के अनुरूप रोजगार का वास्तविक अवसर प्रदान कर दिया है तथा बेरोजगारी और गरीबी का खात्मा कर दिया है;

— इसने शिक्षा तथा विश्व संस्कृति की उच्चतम उपलब्धियों को सर्वसुलभ बना दिया है;

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

—इसने समूची आबादी की सेवा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क चिकित्सा सेवा की स्थापना की है;

—इसने एक जनतांत्रिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की है तथा सोवियत नागरिकों को आधुनिक, कम भाड़े के आवास मुहैया किये हैं;

—इसने व्यक्ति के समस्त विकास को अपना मूल कर्त्तव्य घोषित किया है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह नीतियों का सोद्देश्य और सुसंगत अनुसरण करता रहा है;

—इसने सशक्त अर्थतंत्र स्थापित कर लिया है, रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर दिया है, तथा सोवियत नागरिकों को कल की चिंता से मुक्त कर दिया है और भविष्य के प्रति उनमें आशा का संचार कर दिया है।

—इसने राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग की नीति का प्रचलन किया, तथा वह सदा इस नीति का सुसंगत और अथक रूप में अनुसरण करता रहा है।

आप अपने राज्य को समूची जनता का राज्य कहते हैं। यह सर्वहारा के अधिनायकत्व से किस माने में भिन्न है?

सबसे पहले तो हम "सर्वहारा के अधिनायकत्व" की अवधारणा की व्याख्या कर देना चाहेंगे। राजनीतिक विज्ञान का यह सूत्र मजदूर वर्ग द्वारा राजसत्ता के बरते जाने का सूचक है। समाजवादी समाज एकदम नहीं स्थापित हो जाता। पूंजीवाद के समाजवाद में क्रांतिकारी रूपान्तरण का एक संक्रमण काल होता है। उस काल की राजसत्ता को मार्क्सवाद-लेनिनवाद में सर्वहारा का क्रांतिकारी अधिनायकत्व पुकारा जाता है।

दूसरे शब्दों में, सर्वहारा का अधिनायकत्व मजदूर वर्ग का ऐसा शासन है जो कृषक वर्ग के साथ मैत्री कायम कर के, तथा आमतौर पर मेहनतकशों की शिरकत से, एक नये समाज का, शोषण से मुक्त समाज का निर्माण करता है।

इस शासन के उद्देश्य और कार्य क्या हैं?

सर्वहारा वर्ग जिस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह रचनात्मक है। अतः उसके शासन का मुख्य उद्देश्य भी रचनात्मक है। यह उद्देश्य है एक नये, समाजवादी अर्थतंत्र का निर्माण करना, विरोधात्मक वर्गों का उन्मूलन करना और मानव द्वारा अपने साथी मानवों के शोषण के स्रोतों को समाप्त करना, तथा सांस्कृतिक क्रांति संपन्न करना।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रूस में मजदूरों की सरकार को यथासंभव पूरी गति से अर्थतंत्र का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, विद्यमान राज्य-यंत्र को नष्ट करना पड़ा और नये की स्थापना करनी पड़ी। पुराने समाज के उन शत्रु तत्वों को जो सोवियत सत्ता की संस्थाओं के विरोधी थे अर्थात् उनको, जो बिना कमायी आमदनी पर जीते थे, जैसे भाड़ाखोर, पूंजीपति, जमींदार आदि, मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये लोग आबादी के दो या तीन प्रतिशत से ज्यादा न थे। किंतु अन्य ६८ प्रतिशत—विशालतम बहुमत! —के लिए पहली बार राज्य के संचालन में भाग लेने की वास्तविक संभावना पैदा हो गयी। ज़ार द्वारा रचित राज्य दूमा में ४०० से अधिक सदस्यों में मात्र एक दर्जन के लगभग मजदूर और नही के बराबर किसान थे। बाकी जमींदार, पादरी, पूंजीपति वर्ग के सदस्य और तिजारती थे। विजयी समाजवादी क्रांति के बाद सभी स्तरों पर राजसत्ता के नये निकायों—सोवियतों (या परिषदों अथवा पंचायतों) का संचालन मजदूर और किसान करने लगे और उन्होंने आबादी के विशालतम बहुमत को पुरअसर जनवाद प्रदान किया।

किंतु पहले के पूंजीपतियों, इंजीनियरों और सेना के अफसरों को देश के जीवन में भाग लेने पर पाबंदी नहीं लगायी गयी। उन्हें काम दिया गया और उनमें से बहुतेरों ने सोवियत सरकार के साथ सहयोग किया। मसलन, १६१६ में ऐसे लगभग ३५,००० जनरल और अफसर लाल सेना की सक्रिय सेवा में थे जो पहले ज़ार की सेना में रह चुके थे।

इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब मजदूर वर्ग ने शोषकों से सत्ता छीनने के उद्देश्य से क्रांतिकारी हिंसा का प्रयोग किया है। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। क्रांति के दुश्मनों से उसकी रक्षा करने के लिए बल का प्रयोग जारी रखना आवश्यक है। १८७१ के पेरिस कम्यून पर विचार कीजिये जो इतिहास में सर्वहारा के अधिनायकत्व का पहला राज्य था। प्रतिक्रांतिकारी पूंजीपति वर्ग ने सर्वहारा के विरुद्ध गृहयुद्ध छेड़ दिया और खून की नदी बहाकर कम्यून को समाप्त कर दिया।

रूस में ही सोवियत सत्ता के प्रथम वर्षों में क्रांतिकारी सुधारों के विरुद्ध चलाये गये अनगिनत कुचक्रों और विद्रोहों और फिर स्वयं गृहयुद्ध को भी याद कीजिए—जो सब के सब रूसी और विश्व के पूंजीपति वर्ग द्वारा प्रेरित थे। १६१८ में जर्मनी की तथा १६१६ में हंगरी और लात्विया में सर्वहारा क्रांतियों के निर्मम दमन को लीजिए। पूंजीपति वर्ग के प्रतिकूल क्रांतिकारी अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी सत्ता की पूरी शक्ति का सदा उपयोग नहीं करते, और यही उनके सर्वनाश का कारण बनता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रूसी सर्वहारा वर्ग ने भी पराजित शोषक वर्गों के साथ नरमी का बर्ताव किया। मसलन, १९१७ की अक्तूबर क्रांति के बाद पूंजीवादी पार्टियों को किसी ने भंग नहीं किया। और सोवियत सरकार पूंजीपति वर्ग की तोड़फोड़ की कार्रवाइयों और श्वेत आतंक (लेनिन की हत्या की कोशिश और कुछ प्रमुख सोवियत नेताओं की हत्या) से ही जवाबी उपाय करने को बाध्य हुई। लेनिन ने कहा था कि अगर किसी देश में पूंजीपति वर्ग समझदारी से पेश आता है तो वहां सर्वहारा सरकार का काम आसान होगा तथा सर्वहारा वर्ग को बल-प्रयोग का सहारा नहीं लेना होगा।

लेनिन ने १९१८ में जिस विकसित समाजवादी समाज का वर्णन किया था, आज सोवियत संघ में उसका निर्माण हो चुका है। इसे ऐसे समाज के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें समाज के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में समाजवाद की जड़ें मजबूत हो गयी हों।

समाजवाद के निर्माण के साथ-साथ सर्वहारा के अधिनायकत्व का समाज धीरे-धीरे संपूर्ण जनता के राज्य में, संपूर्ण जनता के ऐसे राजनीतिक संगठन में बदल जाता है जिसमें मजदूर वर्ग नेतृत्वकारी भूमिका अदा करता है। जैसे-जैसे शोषक वर्गों का उन्मूलन होता जाता है, उनके विरोध का दमन करने का कार्य फालतू होता जाता है, तथा समाजवादी राज्य के मुख्य कार्य, अर्थतंत्र का संगठन और संचालन करने तथा शिक्षा और सांस्कृतिक प्रगति को आगे बढ़ाने के कार्य हर संभव तरीके से विकसित होने लगते हैं। संपूर्ण जनता की राजसत्ता और सर्वहारा के अधिनायकत्व में यही प्रधान अंतर है।

जनवादी केन्द्रीयता क्या है ?
क्या जनवाद के साथ केन्द्रीयता का मेल संभव है ?

जनवादी केन्द्रीयता सोवियत राज्य की संरचना और संचालन का प्रमुख सिद्धांत है। इसका अभिप्राय यह है कि :

— सत्ता के सारे निकाय, उच्चतम से लेकर निम्नतम तक, निर्वाचित होते हैं;

— वे अपने निर्वाचकों और अपने ऊपर के निकायों को नियमित रिपोर्ट देते हैं;

— अल्पमत बहुमत का अनुसरण करता है;

— ऊपर के निकायों के फैसलों को नीचे के निकायों के लिए मानना अनिवार्य होता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एक साथ मिलकर ये आवश्यक शर्तें इस बात की गारंटी कर देती हैं कि जनवाद को, अर्थात बहुमत—मेहनतकश जन—की कारगर राजनीतिक सत्ता तथा शासन की प्रक्रिया में उनकी पेशकदमी और भागीदारी को व्यवहार में उतारा जाये, वह दैनंदिन जीवन की एक वास्तविकता हो।

हमारा विश्वास है कि केन्द्रीयता जनवाद की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ज्यादा सही यह कहना होगा कि ये परस्पर परिपूरक हैं। जनवादी केन्द्रीयता का अर्थ है फैसलों का मसविदा तैयार करने के दौर में अधिक से अधिक व्यापक और खुली बहस। इस प्रकार की बहस के बाद अंततः बहुमत के लिए बहुमत द्वारा फैसले लिए जाते हैं, और सभी के लिए उनको मानना अनिवार्य होता है। बहुमत की इच्छा का उल्लंघन जनवाद का उल्लंघन है। इस प्रक्रिया का राज्यीय आर्थिक विकास योजनाओं (जो कानून की तरह लागू होती हैं) और अन्य कानूनों दोनों के मामले में पालन किया जाता है।

जनवादी केन्द्रीयता का सिद्धांत सोवियत प्रणाली को सुदृढ़ कर के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक एक अखंड इकाई बना देता है।

सोवियत संघ में प्रचलित प्रवृत्ति सरकार का केन्द्रीकरण है या विकेन्द्रीकरण ?

क्या दोनों का विरोधी होना आवश्यक है ? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की बनावट ऐसी है कि उनकी प्रवृत्ति वस्तुतः एक-दूसरे की ओर बढ़ते जाने की है। एक ओर समाज के सामाजिक ज़ीवन के केंद्रीकृत प्रशासन में अनवरत सुधार हो रहा है, दूसरी ओर जैसे-जैसे अधिकाधिक मेहनतकश देश के राजनीतिक जीवन में अधिकाधिक भाग लेते हैं, सत्ता के निचले निकायों का क्षेत्राधिकार और पहल सतत बढ़ता जाता है।

समाजवादी राज्य के हितों के लिए, जिसका मुख्य लक्ष्य है जनता के लिए जीवनमान के बढ़ते रहने की सुनिश्चित व्यवस्था करना, यह अपेक्षित है कि शक्तियों और संसाधनों का संकेंद्रण हो जिससे उनका अधिक से अधिक कुशल उपयोग हो सके। आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के पैमाने के बढ़ने के साथ-साथ केंद्रीकृत प्रशासन की भूमिका बढ़ती जाती है। आर्थिक प्रबन्ध में प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संपादन के लिए तथा अनुभागीय और क्षेत्रीय विकास संबंधी और दीर्घकालिक योजनाओं का चालू नियोजन के साथ समन्वय करने के लिए केंद्रीकरण आवश्यक है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किंतु केंद्रीकृत प्रबंध इस विषय का एक पहलू मात्र है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस में केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है: "आर्थिक प्रबंध के सुधार में एक अन्य, अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है *प्रबंध के सांगठनिक ढांचे और तरीकों में सुधार*। हमें जनवादी केंद्रीयता के दोनों सिद्धांतों को एक साथ सुदृढ़ करना है। एक ओर, केंद्रीयता को विकसित कर के विभागीय और संकुचित प्रवृत्तियों को रोकने के लिए दीवार खड़ी की जानी चाहिए। दूसरी ओर, जनवादी सिद्धांतों और स्थानीय पहलकदमी को बढ़ावा देना तथा प्रबंध की ऊपरी श्रेणियों को छोटे-छोटे मामलों से राहत देना और निर्णय लेने के कार्य में गति और लचीलापन लाना आवश्यक है।"

स्थानीय शासन जनवादी सिद्धांतों के विकास का खासतौर पर अच्छा उदाहरण पेश करता है। हाल में स्थानीय सोवियतों की शक्तियां काफी बढ़ायी गयी हैं। उन्हें स्थानीय आबादी की सेवा करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों और संगठनों तथा समस्त राज्यीय आवास प्रबन्ध का दायित्व सौंप दिया गया है। वे अपने क्षेत्र के संयंत्रों और कारखानों के कार्य के नियोजन और तालमेल में भाग लेती हैं।

ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाने वाला व्यापक और बहुमुखी कार्य इसका अन्य उदाहरण है। उनकी शिरकत के बगैर योजनाओं, वेतन, उत्पादन कोटे या आय-वितरण से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं निबटाया जाता। विविध सार्वजनिक संगठन समाज के प्रबन्ध में नागरिकों की भागीदारी की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली हैं। ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर, जिनकी सदस्य संख्या ११.३ करोड़ से अधिक है, वे देश की लगभग संपूर्ण बालिग आबादी को अपने भीतर समेट लेते हैं।

मैंने सुना है कि सोवियत संघ के एक नये संविधान के लिए कार्य चल रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान संविधान में कौन से परिवर्तन किये जाने वाले हैं और क्यों?

एक नये संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका है। मसविदा तैयार करने का काम एक आयोग ने किया जिसका नेतृत्व सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेझनेव कर रहे थे।

प्रारूप को जून के आरंभ में प्रकाशित किया गया और राष्ट्रव्यापी पैमाने पर बहस के बाद उसे पारित किया जा चुका है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मौजूदा संविधान १९३६ में स्वीकृत किया गया था। यह सोवियत संघ में समाजवाद की विजय को परिलक्षित करता है तथा उसे कानूनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसके लिए उसने उसके बुनियादी सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया है।

किंतु जीवन आगे बढ़ रहा है। पिछले चालीस वर्षों में सोवियत समाज कहीं अधिक परिपक्व हो गया है।

समाजवादी अर्थतन्त्र की नींव डालने की जगह अब हमारे पास एक विकसित और तकनीकी दृष्टि से सुसज्जित समाजवादी आर्थिक व्यवस्था मौजूद है।

एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया चल रही है जिससे नगर और ग्रामांचल के बीच, मजदूर वर्ग और भूमि पर काम करने वालों के बीच के अन्तर काफी कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या का जो हिस्सा बौद्धिक कार्य करता है, उसका अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। शारीरिक कार्य उत्तरोत्तर मस्तिष्क के कार्य के गुण प्राप्त करते जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अब लम्बा डग भरा गया है। अब देश की सत्रह साल की आयु में सार्विक दसवर्षीय माध्यमिक शिक्षा लागू हो चुकी है।

इन तमाम वर्षों में सभी वर्ग और सामाजिक समूह परस्पर बहुत समीप आये हैं, तथा सोवियत समाज सामाजिक दृष्टि से अधिकाधिक एकरूप होता जा रहा है।

करोड़ों नर-नारी समाज के मामलों के रोजमर्रे के प्रबन्ध में तथा निर्णय लेने के कार्य में सम्मिलित किये जाते हैं।

विकसित समाजवादी समाज का निर्माण किया जा चुका है तथा कम्युनिज्म के निर्माण से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

संविधान का प्रारूप इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है और साथ ही यह पहले के सोवियत संविधानों और समाजवाद के अन्य देशों के संविधानों के मुख्य विचारों का निचोड़ प्रस्तुत करता है।

लियोनिद ब्रेझनेव ने लक्षित किया : "...इस प्रारूप में जो कुछ नया है, वह वस्तुतः समाजवादी जनवाद को विस्तृत और गहन बनाए जाने का ही प्रतिफल है।" सबसे बढ़कर वह सोवियतों के गठन और कार्य के जनवादी सिद्धान्तों का और आगे विकास है। उसमें सोवियतों और जनता के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। प्रारूप देश के जीवन में ट्रेड यूनियनों, तरुण कम्युनिस्ट लीग तथा अन्य जन संगठनों और उत्पादन के कार्य-सामूहिकों द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को व्यापक रूप में प्रतिबिंबित करता है।

वर्तमान संविधान में नागरिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान काफी विस्तृत

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किये गये हैं। नागरिकों की समानता के सामान्य सिद्धांत की घोषणा की गयी है, तथा मानव जीवन की बुनियादों को ही प्रभावित करने वाले विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक अधिकारों (मसलन, काम, विश्वास और अवकाश, स्वास्थ्य संरक्षण के अधिकार) से संबंधित प्रावधान विकसित और विस्तृत किये गये है। सोवियत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्ववर्ती संविधान की अपेक्षा अधिक विस्तारपूर्वक परिभाषित किया गया है।

संविधान के प्रारूप में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने तथा अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के कर्त्तव्य पर जोर दिया गया है। सोवियत राज्य के हितों की हिफाजत करने, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम रखने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होने, प्रकृति की रक्षा करने और उसकी संपदा की रखवाली करने तथा सांस्कृतिक मूल्यों को बचा कर रखने के कर्त्तव्यों को संवैधानिक प्रावधानों के रूप में सूत्रबद्ध किया गया है।

बच्चों को शिक्षित करना तथा उन्हें लालन-पालन करके समाजवादी समाज का एक सुयोग्य सदस्य बनाना प्रारूप में सोवियत नागरिकों का एक कर्त्तव्य घोषित किया गया है।

प्रारूप में "सामाजिक विकास और संस्कृति" पर एक अध्याय है जिसमें यह लक्षित किया गया है कि राज्य शिक्षा, विज्ञान और कला के विकास की तथा जनता के कार्य और रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार की चिंता करता है।

संविधान के प्रारूप में समाजवादी कानून और अमन का और भी मजबूत किया जाना स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है।

सोवियत संघ के संघात्मक ढांचे के बुनियादी पहलुओं को, जिसकी समीचीनता व्यवहार में पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है, बरकरार रखा गया है।

प्रारूप सोवियत राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के विकास के एक नये चरण को परिलक्षित करता है वह लक्षित करता है कि सोवियत संघ का अर्थतन्त्र ऐसा एक अखंड राष्ट्रीय आर्थिक समुच्चय बन गया है जो देश के सामाजिक उत्पादन, वितरण और विनिमय के सभी तत्वों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। प्रारूप उद्यमों और उत्पादन संघों की आर्थिक स्वतन्त्रता और पहल के साथ नियोजित केन्द्रीकृत प्रबंध के समन्वय जैसे समाजवादी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत का भी अनुमोदन करता है।

यह संविधान का पहला प्रारूप है जिसमें "विदेश नीति" संबंधी एक अध्याय सम्मिलित है। उसमें कहा गया है कि सोवियत राज्य शांति की नीति का अविचल पालन करता है तथा वह राष्ट्रों की सुरक्षा और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की हिमायत करता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या आप कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि किसी सोवियत के चुनाव में केवल एक उम्मीदवार क्यों होता है ?

कानून द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और कानून चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की कोई सीमा नहीं निर्धारित करता। हां, यह एक स्थापित व्यवहार, एक परम्परा अवश्य है।

पूंजीवादी देशों में भी वास्तव में एक चुनाव क्षेत्र में आमतौर पर एक पार्टी का एक उम्मीदवार ही खड़ा होता है। सामान्यत: किसी एक सीट के लिए उतने ही उम्मीदवार होते हैं जितनी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां। लेकिन हमारी एक ही पार्टी है—कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए जहां वह कोई उम्मीदवार मनोनीत करती है वहां उस सीट के लिए एक ही उम्मीदवार होता है :

यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि पूंजीवादी देशों में निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। जी हां, हो सकते है। मगर हमारे यहां भी निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, हालांकि उन्हें निर्दलीय नाम से पुकारा नहीं जाता। यहां भी यह आवश्यक नहीं कि कोई उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी का सदस्य ही हो। उम्मीदवार निर्वाचन जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किये जाते हैं। आमतौर पर किसी चुनाव अभियान के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियनें, तरुण कम्युनिस्ट लीग और अन्य सार्वजनिक संगठन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि किस निर्वाचन जिले में कोई उम्मीदवार खड़ा होगा और उस जिले का उम्मीदवार कौन होगा। और जहां उम्मीदवार पार्टी का सदस्य नहीं होता, वहां उसे बिना किसी चूक के कम्युनिस्टों का समर्थन प्राप्त होता है। मसलन १९७५ में स्थानीय सोवियतों के चुनाव में बीस लाख से अधिक सदस्य चुने गये। उनमें से आधे से कम कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे।

अपनी पुस्तिकाओं में आप यह दावा करते हैं कि सोवियत संघ में राज्य का शासन मजदूर और किसान चलाते हैं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप कुलवक्ती संसद सदस्यों की भूमिका से इन्कार करते हैं ?

सोवियत प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा बहुमत नि:संदेह मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधि है। ये प्रतिनिधि अपने संसदीय कर्त्तव्य अपने सामान्य कार्य के अलावा पूरा करते हैं और वह भी बिना किसी वेतन के।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह व्यवस्था हमारे लिए अनुकूलतम है। क्यों? इसलिए कि हमारे विचार से यह शासन में तथा समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में जनवादी सिद्धांतों के परिपालन की सबसे अच्छी तरह से गारंटी करती है। मतदाता इस बात पर अपनी नजर रख लेते हैं कि शासन के लिए उन्होंने जिस प्रतिनिधि को चुना है, वह क्या कार्य करता है, चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने उसे जो जनादेश दिया है जिसकी कि उसको तामील करनी है, वह किस प्रकार पूरा करता है।

राजसत्ता के निकायों के जनवाद की दृष्टि से यह कम आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधि (संसद-सदस्य) वास्तव में मेहनतकशों के, बहुमत के सच्चे प्रतिनिधि हों।

लेकिन जब हम मिसाल के बतौर पूंजीवादी देशों के कुलवक्ती संसद-सदस्यों पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि वे आमतौर पर मेहनतकश आबादी से ज्यादा अमीर वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं।

हम ऐसी व्यवस्था को जनवादी नहीं मानते।

यहां यह पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा संसद-सदस्य जो पेशेवर और कुलवक्ती तौर पर संसद-सदस्य न हो, महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषयों पर पेशेवर-तौर पर कैसे फैसले ले सकता है। अगर वह बेंच पर या खेतों में अपना बहुत-सा समय खर्च करता है तो क्या वह यथेष्ट जानकारी या अनुभव प्राप्त कर सकेगा?

यह सवाल युक्तिसंगत है। मगर मुद्दा यह है कि उम्मीदवार का चयन करते समय नामांकन करने वाली संस्थाएं राजनीतिक और नैतिक क्षेत्रों में और काम में उनके गुणों का सावधानी से जायजा लेती हैं तथा इस बात को मद्देनजर रखती हैं कि मनोनीत व्यक्ति को पार्टी, ट्रेड यूनियनों और निचले स्तर की सोवियतों में क्या अनुभव प्राप्त है, उसमें संगठन की कैसी योग्यता है, आदि, आदि। फलत: आम तौर पर वे ही लोग उम्मीदवार और प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें उनके निर्वाचक बारीकी से पड़ताल करने के बाद स्वीकार कर लेते हैं और इस वजह से जिनसे यह आशा की जा सकती है कि वे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों का निबटारा करने में पूरी तरह सक्षम होंगे।

इसके अलावा प्रतिनिधियों के पास इस बात के लिए प्रचुर सुअवसर रहता है कि वे सरकारी विभागों में वकीलों, अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी-विदों आदि विशेषज्ञों से परामर्श कर सकें, और इस कारण मान लीजिए किसी कानून का मसविदा तैयार करना है तो वे जरूरी तथ्य या सलाह पा सकते हैं।

संसदीय कार्य करते समय प्रतिनिधियों को काम से छूट दे दी जाती है लेकिन उन्हें उसके लिए वेतन नहीं गंवाना पड़ता, और वे यातायात के सभी साधनों का नि:शुल्क उपयोग कर सकते हैं। उन्हें कानून के तहत विशेष छूट भी प्राप्त होती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आप लिखते हैं कि अगर कोई प्रतिनिधि
चुनाव के दौरान किये गये वायदे तोड़ता है
तो निर्वाचक उसे वापस बुला सकते हैं
और उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
क्या इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिनिधि चुन लिये जाने पर
वह स्वत: राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं बन जाता
और इस कारण वह निर्वाचकों से स्वतंत्र
नहीं बन जाता ?

हम अंशत: इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। यह बिल्कुल सही है कि किसी सोवियत का सदस्य बन जाने के बाद वह अपने निर्वाचकों से स्वतंत्र नहीं बन जाता। वह उनकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं कर सकता।

प्रतिनिधित्व की हमारी प्रणाली इस विचार को स्वीकार नहीं करती कि अगर कोई प्रतिनिधि यह सोचता है कि निर्वाचकों की राय राष्ट्रीय हितों से टकराती है तो वह उनकी राय की उपेक्षा कर सके।

हमारा विचार है कि प्रतिनिधि को निर्वाचकों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। निर्वाचक मंडल की सामूहिक राय उनकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और मांगों को अभिव्यक्त करती है। निर्वाचक सत्ता के किसी निकाय (किसी सोवियत) में अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि वह उनकी इच्छाओं और उनकी हिदायतों का पालन कर सके, और वह सच्चे अर्थों में जनवादी प्रतिनिधित्व पर आधारित जनवादी शासन की प्रणाली में ऐसा करने को बाध्य है।

समाजवादी जनवाद का सारतत्व यह है कि राज्य के शासन में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को शरीक करना और इसके लिए अलबत्ता यह जरूरी है कि उन्हें न सिर्फ सत्ता के किसी निकाय के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त हो बल्कि शासन के कार्यों के संपादन में उनके साथ सक्रिय सहयोग करने का अधिकार तथा उनके कार्यकलाप पर नियंत्रण करने की शक्ति भी प्राप्त हो।

हर साल सारे प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के समक्ष इस बात की रिपोर्ट पेश करते हैं कि अपनी राजकीय भूमिका में वे क्या करते रहे हैं तथा चुनाव के समय अपने निर्वाचकों से उन्हें जो हिदायतें मिली हैं उन्हें उन्होंने किस तरह निभाया है। अगर कोई प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता और अपने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कर्त्तव्यों को इस प्रकार निभा नहीं पाता जैसे उसे करना चाहिए, तो निर्वाचकों को उसे वापस बुला लेने तथा नया चुनाव कराने का अधिकार है। ऐसी घटनाएं अक्सर नहीं होतीं मगर होती अवश्य हैं। पिछले दस वर्षों में (सभी स्तरों की सोवियत के लिए चुने गये दो करोड़ प्रतिनिधियों में से) कोई ४,००० प्रतिनिधि वापस बुलाए गए हैं।

**क्या संसद के दोनों सदनों,
संघ की सोवियत और
कौमियतों की सोवियत में
कोई अन्तर है?
दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है?**

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की दो सदनों की प्रणाली का मूल कारण देश की संघीय प्रणाली और उसकी बहुराष्ट्रीय आबादी में निहित है। संघ की सोवियत संपूर्ण सोवियत जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, तथा कौमियतों की सोवियत, देश की विविध कौमियतों के हितों का।

इसी कारण प्रतिनिधित्व के अनुपात भिन्न-भिन्न हैं। संघ की सोवियत में सामान्यतः प्रति ३,००,००० की आबादी पर एक प्रतिनिधि है; कौमियतों की सोवियत में हर कौमी जनतन्त्र के ३२ प्रतिनिधि हैं, चाहे उसका जितना बड़ा या आबादी जितनी अधिक हो। इस प्रकार १३.५ करोड़ आबादी वाले विशाल रूसी संघ और मात्र १५ लाख आबादी वाले छोटे से एस्तोनिया में प्रत्येक के प्रतिनिधियों की संख्या समान है। यही नियम स्वायत्त जनतन्त्रों, स्वायत्त प्रदेशों और कौमी क्षेत्रों के साथ लागू होता है। जिनके प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः सात, पांच और एक है। पिछले जून १९७४ के चुनाव में चुने गये सर्वोच्च सोवियत के १५१७ सदस्यों में से ७६७ संघ की सोवियत के सदस्य निर्वाचित हुए तथा ७५०, कौमियत्तों की सोवियत के सदस्य।

अन्यथा दोनों सदन सर्वथा समान रूप में संगठित हैं तथा एक ही नमूने पर कार्य करते हैं: दोनों को सार्विक, प्रत्यक्ष और समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा एक ही समय और पूर्णतः चुनाव होता है। प्रत्येक सदन पूरे काल के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है तथा अस्थायी और स्थायी आयोगों का गठन करता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दोनों सदन संयुक्त रूप से सर्वोच्च सोवियत का एक अध्यक्षमंडल चुनते हैं तथा सरकार के उच्चतम निकायों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार वे मंत्रिपरिषद गठित करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित करते हैं, तथा महादंडाधिकारी (प्रोक्योरेटरजनरल) की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होते हैं जो उन्हें किसी भी समय भंग या बर्खास्त कर सकता है।

जन प्रतिनिधित्व की सोवियत प्रणाली में संसद का प्रवर और अवर या उच्च और निम्न सदनों में कोई विभाजन नहीं है। दोनों ही सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, तथा उनमें से प्रत्येक के निर्णय समान रूप में लागू होते हैं। दोनों को ही कानूनों की पहल करने की समान शक्तियां हैं। सोवियत संघ के संविधान के अनुसार कोई भी कानून दोनों सदनों में प्रत्येक के साधारण बहुमत से पारित हो जाने पर स्वीकृत माना जाता है।

नियमतः दोनों सदनों के अधिवेशन एक ही साथ आरंभ और समाप्त होते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी बैठकें भी एक ही समय होती हैं। प्रत्येक स्वयं अपनी कार्यसूची और कार्यविधि मंजूर करता है। विषयों पर संयुक्त या अलग-अलग बैठकों में विचार किया जा सकता है। कानून, अध्यादेश और अन्य निर्णय एक ही तरह लिये जाते हैं जिसमें अधिकतर बहसें अलग-अलग होती हैं और फैसले संयुक्त बैठकों में लिए जाते हैं।

दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संविधान में विशेष समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है। विवाद का विषय एक विशेष संराधन आयोग को सुपुर्द किया जाता है जिसे दोनों सदन साम्य के आधार पर गठित करते हैं। लेकिन अगर यह निकाय समझौते पर न पहुंच पाये या अगर उसका फैसला किसी एक सदन को संतुष्ट न कर पाए तो प्रश्नाधीन मामले को पुनः विचार-विमर्श के लिए सदनों को सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर इस बार कोई समझौता नहीं हो पाता तो सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष-मंडल, संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए, सर्वोच्च सोवियत को भंग कर देता है तथा नये चुनाव का निर्णय कर लेता है। इस प्रकार कोई भी सदन दूसरे पर अपनी मर्जी नहीं लाद सकता।

इस सांगठनिक ढांचे की बदौलत सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत देश के सम्पूर्ण हितों तथा विविध संघीय और स्वायत्त जनतंत्रों, स्वायत्त प्रदेशों और राष्ट्रीय क्षेत्रों के विशिष्ट हितों, दोनों को दृष्टि में रखते हुये कानूनों, आर्थिक कार्यक्रमों, बजटों और अन्य निर्णयों पर विचार कर सकती है और उन्हें स्वीकृत कर सकती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की बैठकें एक बार में कतिपय दिनों तक ही क्यों चलती हैं जबकि पूंजीवादी देशों में उनके अधिवेशन महीनों तक चलते हैं ?

विदेशियों की कभी-कभी यह धारणा होती है कि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की जिम्मेदारियां सीधी-सादी हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिए अत्यल्प समय अपेक्षित होता है, कि प्रतिनिधि साल में दो बार मास्को आते हैं, वैधानिक अधिनियमों का अनुमोदन करते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं, और यहीं उनकी संसदीय गतिविधियों की इतिश्री हो जाती है।

निःसंदेह, यह असली तस्वीर कतई नहीं है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत साल में दो सत्र या अधिवेशन आयोजित करती है, और हर अधिवेशन कतिपय दिनों तक चलता है। किंतु प्रत्येक अधिवेशन के पहले विचार-विमर्श और पारण के लिए प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की खातिर कानून का मसविदा तैयार करने का लंबा और श्रमसाध्य कार्य चलता है।

इस आरंभिक कार्य में क्या बातें शामिल होती हैं ?

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के १,५१७ सदस्यों में से लगभग १,००० अर्थात दो-तिहाई सदस्य संघ की सोवियत और कौमियतों की सोवियत के २८ स्थायी आयोगों के सदस्य हैं। ये आयोग सर्वोच्च सोवियत के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले सभी प्रश्नों का अध्ययन करने वाले कार्यकारी निकाय होते हैं। स्थायी आयोग कानूनों के मसविदे तैयार करने में भाग लेते हैं, सोवियत संसद द्वारा पहले स्वीकृत कानूनों पर अमल की देख-रेख करते हैं, सरकारी मंत्रियों की रिपोर्टों की छान-बीन करते हैं, आदि-आदि।

मसलन १९७६ के गर्मियों के तीन महीनों (जून-अगस्त) में जब अनेक देशों के संसद-सदस्य छुट्टी पर रवाना हो गये, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के आगामी अधिवेशन की तैयारी में क्रेमलिन में स्थायी आयोगों के सदस्यों की छह बैठकें हुईं।

स्थायी आयोगों ने अज़रबैजान में पर्यावरण-रक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कास्पियन सागर के पानी की रक्षा करना भी शामिल है, उठाये गये कदमों का अध्ययन किया। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के तकरीबन ८० सदस्यों ने इस कार्य में भाग लिया। इनमें तेलकर्मी इस्राफिल गुसेइनोव और रागिल इब्राहिमोव

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तथा ज्यार्जिया की विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष येवगेनी खाराद्ज़े भी शामिल थे। उन्होंने विचाराधीन इलाके का दौरा किया, संकलित सामग्री का सावधानी से अध्ययन किया, तथा अपनी पड़ताल के नतीजे प्रकृति परिरक्षण आयोग को सुपुर्द किये। जब बाद में सर्वोच्च सोवियत, सरकार तथा संबद्ध मंत्रालयों और विभागों ने इस विषय पर विचार किया तो उस दौरान इन प्रतिनिधियों के सुझावों और सिफारिशों को उचित रूप में ध्यान मे रखा गया।

इसके अलावा सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ऐसे प्रश्नों के अध्ययन के लिए विशेष आयोगों की नियुक्ति करती है जो स्थायी आयोगों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते।

मैंने आपका स्थानीय सोवियतों से संबंधित एक परिपत्र पढ़ा है किंतु उसमें मुझे अपनी रुचि के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। वे, मिसाल के लिए, ब्रिटेन या फ्रांस की नगर परिषदों से किस मायने में भिन्न होती हैं ?

पूंजीवादी देशों के विपरीत हमारे यहां नियुक्त अधिकारियों से बने सरकारी निकायों तथा इन अधिकारियों की देख-रेख में स्थानीय विषयों का निवटारा करने वाले स्वशासी निकायों के रूप में कोई विभाजन नहीं है। स्थानीय स्वशासन पर "प्रशासनिक अभिभावकत्व" का विचार मात्र का सोवियत राज्य प्रणाली से कोई नाता नहीं हैं।

न ही ऐसे कोई उच्चतर और स्थानीय प्राधिकरण हैं जिनके हितों में टकराव होता हो। सभी स्थानीय कार्यकारी निकाय सोवियतों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा वे जो कुछ करते हैं उसके लिए सोवियतों के प्रति जवाबदेह होते हैं।

स्थानीय सोवियतें औद्योगिक और कृषि उत्पादन, सार्वजनिक शिक्षा, सांस्कृतिक प्रश्नों, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, व्यापार, खानपान और अन्य सेवाओं, नगर सुधार, गृह निर्माण, नगर अर्थतंत्र तथा अमन-कानून की रक्षा से संबंधित व्यावहारिक मामलों को निबटाती हैं और उन पर फैसले लेती हैं।

नगर परिषदों के विपरीत सोवियतों पर उनके क्षेत्र की भूमि का पूरा प्रभार होता है (जमीन का कोई खानगी मालिक नहीं है), तथा उनके कार्यकलाप समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित कर लेते हैं। सोवियतें पूंजीवादी देशों की नगर परिषदों से अपने विन्यास की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। सोवियतों के

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अधिकांश सदस्य मजदूर और किसान होते है। चौथाई से अधिक प्रतिनिधि तीस साल से कम आयु के हैं।

स्थानीय प्रशासन का बहुत-सा ब्यौरेवार काम स्थानीय सोवियतों की स्थायी समितियां करती हैं, और ये समितियां अपने कार्यों और उनकी विधियों को लगातार सुधारती जा रही हैं। वे प्रतिनिधियों के कार्यकलाप के एक प्रमुख रूप की परिचायक हैं। कुल मिलाकर स्थानीय सोवियतों की स्थायी समितियों में लगभग १८,००,००० प्रतिनिधि अथवा कुल प्रतिनिधियों के तीन-चौथाई से अधिक शामिल हैं। समितियों के काम में कोई २६,००,००० कार्यकर्ता मदद पहुँचाते है जो जनता के व्यापक तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सारांश यह है कि स्थानीय सोवियतें जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपने क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों पर पूरा क्षेत्राधिकार रखती हैं। उनमें और पूंजीवादी देशों की नगर परिषदों के बीच यह प्रधान अंतर है।

बोल्शेविक पार्टी का उदय एक क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में, रूस की समस्त शासन-प्रणाली का विरोध करने वाली पार्टी के रूप में हुआ। उसके बाद वह देश की शासन पार्टी बन गयी। क्या इन नयी परिस्थितियों में उसने अपनी क्रांतिकारी भावना बरकरार रखी हैं और अगर रखी है तो यह भावना किस प्रकार व्यक्त होती है ?

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद से उसकी क्रांतिकारी भावना तो सबसे पहले उन क्रांतिकारी गतिविधियों में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में अभिव्यक्त होती रही है जिनसे समाज का कायाकल्प हो गया है और वह आज के रूप में आ गया है। पार्टी ने संपूर्ण विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीयतावादी कर्त्तव्य जिस प्रकार पूरा किया है, उसमें भी इस क्रांतिकारी भावना को देखा जा सकता है।

घरेलू दृश्यपटल पर पार्टी का क्रांतिकारी चरित्र देश के उद्योगीकरण की प्रभावोत्पादक दर में, उसकी कृषि के कायाकल्प में, सांस्कृतिक क्रांति में, समाज-वाद के दृढ़ भौतिक और तकनीकी आधार के निर्माण में, कौमियतों के प्रश्न के समाधान में, हमारे आज के विकसित समाजवादी समाज की रचना में, दूसरे शब्दों में, उन तमाम अनेक चीजों में, जिनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अभिव्यक्त हुआ है जो कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकलाप का प्रत्यक्ष परिणाम हैं, वह कार्यकलाप जिसकी जड़ें अक्तूबर क्रांति के क्रांतिकारी विचारों में छिपी हैं।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी एक लेनिनवादी पार्टी है। लेनिनवाद के साथ विश्व इतिहास का एक पूरा का पूरा युग जुड़ा हुआ है, विश्व के सामाजिक ढांचे में आधारभूत क्रांतिकारी परिवर्तनों का युग। हमारी पार्टी अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए सघर्षरत, साम्राज्यवाद और नवउपनिवेशवाद के सभी रूपों से संघर्षरत जनगण को सदा नैतिक, भौतिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान करती रही है और करती रहेगी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेझनेव ने २५वीं पार्टी कांग्रेस में कहा : "हम उस तरह कार्य कर रहे हैं जैसे कार्य करने को हमारी क्रांतिकारी अंतरात्मा और हमारी कम्युनिस्ट आस्था ने हमें प्रेरित किया है।"

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के प्रति यह वफादारी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी चरित्र की सर्वश्रेष्ट अभिव्यक्ति है। वियतनाम, चिली, लाओस और अंगोला की तथा अनेक अन्य उन देशों की जनता जिन्हें सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से सर्वांगीण सहायता प्राप्त हुई है, उसकी क्रांतिकारिता का अभिनंदन करती है।

सोवियत संघ में केवल एक पार्टी क्यों है ?
क्या समाजवाद में बहुपार्टी प्रणाली का स्थान नहीं है ?

सोवियत संघ की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप वहां केवल एक राजनीतिक पार्टी है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी।

अक्तूबर १९१७ की क्रांति से पहले रूस में कई एक राजनीतिक पार्टियां थीं। उनमें से कुछ पार्टियां जो अनुदार थीं, जारशाही का पक्षपोषण करती थीं, तथा अन्य पार्टियां सुधारवादी नीतियों पर चलती थीं। एक मात्र कम्युनिस्टों की पार्टी ही समाज में क्रांतिकारी चेतना का संचार करना तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार की असमानताओं का खात्मा करना चाहती थी। कम्युनिस्टों का कार्यक्रम जनता के विशालतम बहुमत के हितों की पूर्ति करता था।

कम्युनिस्ट लोग सबसे बढ़ कर तो मजदूर वर्ग की पार्टी थे। अन्य ऐसी जनवादी शक्तियां भी थीं जो खास तौर पर कृषक समुदाय के एक हिस्से के विचारों को प्रतिबिंबित करती थीं। मसलन, समाजवादी क्रांतिकारियों का काफी प्रभाव था।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उनके साथ संयुक्त रूप में कार्य करने से इन्कार करने की बात तो दूर रही, कम्युनिस्ट लोग तो उनके साथ मैत्रीमोर्चा कायम करना आवश्यक मानते थे।

विजयी अक्तूबर क्रांति के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी उस मोर्चे को जारी रखने को तैयार थी। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी को राजसत्ता के सर्वोच्च निकाय—अखिल-रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी (जो सोवियतों की एक कांग्रेस द्वारा निर्वाचित हुई थी तथा जिसमें ६२ कम्युनिस्ट, २९ वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी तथा १० अन्य तीन पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे—में एकदलीय सरकार गठित करने का अधिकार था। फिर भी उसने वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के सरकार में सम्मिलित होने को आमंत्रित किया।

नवम्बर १९१७ के उत्तरार्द्ध में ग्राम पांतों के दबाव में जिनमें से बहुत से तो बोल्शेविकों के साथ हो लेने को तैयार थे, वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी नेता बोल्शेविकों के प्रस्ताव पर राजी हो गये। उन्होंने घोषित कर दिया कि वे "सोवियत नीति का अनुसरण करने को तैयार" हैं। नवगठित सरकार में समाजवादी क्रांतिकारियों के सात प्रतिनिधि शामिल थे।

किंतु शीघ्र ही ऐसा हुआ कि समाजवादी क्रांतिकारियों को समाजवादी सुधार के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कम्युनिस्टों के साथ सहयोग करने का लेश मात्र इरादा न रह गया। मार्च १९१८ में ही उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से साझा सरकार छोड़ दी और उसी साल जुलाई में सोवियत सरकार के खिलाफ मास्को में सशस्त्र बगावत कर दी।

निम्न-पूंजीवादी पार्टियों को भंग किये जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया जैसा कि कुछ पश्चिमी इतिहासकार जताने की कोशिश करते हैं। ये जनता की दृष्टि में स्वतः पतन के शिकार होकर राजनीतिक मंच से हट गये। घटनाओं के क्रम ने ही कम्युनिस्टों को देश के भविष्य का दायित्व एकात्मक रूप में अपने कंधों पर उठाने को बाध्य कर दिया।

किंतु एकदलीय प्रणाली समाजवादी समाज का आवश्यक लक्षण नहीं है। अनेक समाजवादी देशों जैसे बुलगारिया, पोलैंड, जर्मन जनवादी गणतंत्र आदि में बहुदलीय प्रणालियां लागू हैं। उनकी प्रधान विशेषता यह है कि कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियां समाजवाद के निर्माण को अपना ध्येय मानने वाली जनवादी पार्टियों और सार्वजनिक संगठनों को एक सूत्र में बांधने वाले जनप्रिय मोर्चे में अग्रणी भूमिका अदा करती हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अगर व्यवहारतः सारे सोवियत नागरिक कम्युनिस्ट विचारों से सहमत हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के केवल १.६ करोड़ सदस्य क्यों हैं।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी देश की संपूर्ण बालिग आबादी को अपना सदस्य बना लेने नहीं निकल पड़ी है। वह मजदूर वर्ग, किसानों और बुद्धिजीवियों के राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक सजग और सक्रिय प्रतिनिधियों को स्वैच्छिक आधार पर ऐक्यबद्ध करती है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने के लिए पार्टी के कार्यक्रम और नियमों को स्वीकार करना और उनसे सहमत होना ही पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि संबद्ध व्यक्ति कम्युनिज्म के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करे, किसी न किसी एक पार्टी संगठन में व्यक्तिगत रूप में कार्य करे तथा पार्टी निर्णयों की तामील करे।

पार्टी समाज के जीवन में जो उत्तरोत्तर भूमिका अदा कर रही है, उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में जो अभिवृद्धि हो रही है, वह सब उसके सदस्यों की संख्या में यंत्रवत वृद्धि का नतीजा नहीं है। जनता के मूल हितों की पूर्ति करने वाली राजनीतिक दिशा के अनुसरण की बदौलत ही पार्टी को संपूर्ण सोवियत जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। यह अर्थपूर्ण बात है कि अनेक नागरिक, जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं, स्वयं को "गैर-कार्डधारी कम्युनिस्ट" कहते हैं और इस प्रकार पार्टी द्वारा अपनायी गयी नीति के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं।

जब आप कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्व की भूमिका की चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है?

सबसे पहले तो हमारा अभिप्राय यह है कि पार्टी जनता के राजनीतिक नेता के रूप में कार्य करती हैं, तथा समाज के विकास की दिशाएं निर्धारित करती है।

कम्युनिज्म का निर्माण क्रांतिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत के आधार पर होता है। कम्युनिज्म के निर्माण से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के प्रबंध के पीछे एक उद्देश्यपूर्ण, सैद्धांतिक दृष्टि से संपुष्ट दृष्टिकोण निहित होता है। आज चूंकि भावी समाज की भौतिक और तकनीकी नींव रखी जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक कम्युनिज्म का सिद्धांत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम एक अछूते पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जो संसार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लिए नया है। इसी से मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत में सृजनात्मक योगदान करना, सोवियत संघ और अन्य देशों में समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण से सबक सीखना तथा इस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार की इष्टतम एकात्मता पर पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट समाज का सफल विकास इसी पर निर्भर है।

कम्युनिज्म के निर्माण से संबंधित दायित्व इतने बृहत और जटिल हैं कि नये समाज के सृजन से संबंधित पूरे के पूरे विपुल कार्य के राजनीतिक, संगठन संबंधी और वैचारिक मार्ग-दर्शन से किये जाने वाले तकाजे अधिकाधिक बढ़ते जाते हैं। पार्टी सोवियत जनता को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने में नेतृत्व प्रदान करती है।

मैं अक्सर पढ़ता रहा हूं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्टों को अन्य नागरिकों से काफी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं। क्या यह सच है?

अगर सुविधा से आपका अभिप्राय ऐसी चीजें पाने का मौका है जो दूसरों को न मिल सकती हों, सोवियत कम्युनिस्टों को ऐसी कोई सुविधा नहीं प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी की अपनी सदस्यता का इस्तेमाल अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए करने का प्रयास करता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है।

पार्टी में होने का अर्थ है जनहित को सदा अपने हितों से आगे रखना। कोई व्यक्ति बिना पार्टी कार्ड के भी स्वयं अपनी लाइन का विशेषज्ञ, अच्छा कामगार और अच्छा नागरिक हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह कार्य में, सार्वजनिक कार्यकलाप में और अपने निजी जीवन में दूसरों के लिए उदाहरण न प्रस्तुत करे।

अगर यह विशेष सुविधा है तो कम्युनिस्टों को यह अवश्य प्राप्त है।

आपके देश में सोवियत राजसत्ता और ट्रेड यूनियनों के बीच क्या संबंध है?

सबसे पहले तो सोवियत ट्रेड यूनियनें और पूंजीवादी देशों की मजदूर यूनियनें मूलत: भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कार्य करती हैं, और इस कारण उनके कार्य करने की विधि को एक ही कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ में ट्रेड यूनियनें जिन औद्योगिक उद्यमों में स्थापित होती हैं वे किसी भी व्यक्ति की खानगी या निजी संपत्ति नहीं होते जैसा कि पूंजीवाद में होता है, बल्कि संपूर्ण समाज की संपत्ति होते हैं। वे मेहनतकशों के राज्य में कार्य करते हैं जिसका लक्ष्य है श्रमी मानव की भौतिक और सांस्कृतिक खुशहाली बढ़ाना। फलतः सोवियत ट्रेड यूनियनों के हित और सोवियत राजसत्ता के हित सर्वथा समान होते हैं।

यही नहीं, सोवियत राज्य ट्रेड यूनियनों की अनेक प्रकार से सहायता करता है। सबसे पहले तो वह उन्हें भौतिक अवलंब प्रदान करता है। सोवियत राज्य ट्रेड यूनियनों को कामकाज के लिए स्थान देता है, सांस्कृतिक केंद्रों और पुस्तकालयों, खेल-कूद की सुविधाओं-साधनों आदि के लिए भुगतान करता है। वह ट्रेड यूनियनों के लिए आरोग्य केंद्रों और अवकाश गृहों की व्यवस्था करता है तथा संपूर्ण सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेल-कूद संबंधी गतिविधियों के लिए धन का प्रबंध करता है।

सोवियत राज्य ने ट्रेड यूनियनों को व्यापक अधिकार दे रखे हैं, जैसे काम और वेतन विषयक सारे प्रश्न, श्रमी मानव के हितों से सीधे संबंध रखने वाले प्रश्न अधिकृत राजकीय निकाय ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर ही हल करते हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियनें उत्पादन के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेती हैं: ७० से अधिक ऐसे सूचीबद्ध मामले हैं जिनमें प्रबंधक ट्रेड यूनियनों की रजामंदी से ही कार्रवाई कर सकते हैं, तथा और भी २० ऐसे विषय हैं जिनसे अकेले ट्रेड यूनियनें ही सरोकार रखती हैं। ट्रेड यूनियनें सोवियत संघ की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने में भी भाग लेती हैं।

सोवियत ट्रेड यूनियनें कानून-निर्माण के लिए पहल कर सकती हैं और करती भी हैं। अखिल-संघीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद ने जो देश का सर्वोच्च ट्रेड यूनियन निकाय है, "सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा संप्रभु समाजवादी जनतंत्रों के बुनियादी श्रम कानून", "कारखानों और संयंत्रों की स्थानीय ट्रेड यूनियन समिति के अधिकारों से संबंधित विनियम" तथा राष्ट्रीय पेंशन कानूनों के तैयार किये जाने में सक्रिय रूप में भाग लिया था। उसने वेतन वृद्धि संबंधी सरकारी आज्ञप्तियों के तैयार किये जाने में तथा सोवियत राज्य की वैधानिक कार्रवाई से संबंधित अन्य अनेक विषयों में भाग लिया।

और अंततः, राज्य ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय बजट के एक हिस्से का नियंत्रण ट्रेड यूनियनों के हवाले कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ट्रेड यूनियनें इस बजट को तैयार करने और उसे बरतने के लिए उत्तरदायी हैं। १९६७ में सामाजिक सुरक्षा का बजट २९.८ अरब रूबल था (जब कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए विनिमुक्त राशि १७.२ अरब रूबल थी)।

सोवियत ट्रेड यूनियन मजदूरों की किससे रक्षा करती है?

इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है: बेकाबू जोश से और नौकरशाही से, चाहे वह विभागीय हो या व्यक्तिगत रूप में किसी प्रबंधक की ओर से, जो उत्पादन के जनवादी प्रबंध के लिए पार्टी और सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति को तोड़ते-मरोड़ते हैं तथा जो उत्पादन का समुचित संगठन करने में अक्षम होने पर श्रम कानूनों और सामूहिक समझौतों की शर्तों की अवहेलना करके येन-केन-प्रकारेण उत्पादन योजना पूरी करना चाहते हैं।

सोवियत ट्रेड यूनियनों के अन्य रक्षात्मक कार्य ये हैं कि ट्रेड यूनियन की सहमति के बिना किसी को उसके काम से बर्खास्त नहीं किया जा सकता; और काम की परिस्थितियों, सुरक्षा आदि के मामले में पहले ट्रेड यूनियन से मंजूरी पा लिये बगैर कोई कर्मशाला या कारखाना चालू नहीं किया जा सकता।

प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए भी ट्रेड यूनियनों की सहमति आवश्यक है। और ट्रेड यूनियन श्रम कानून या सामूहिक समझौते की शर्तों को तोड़ने वाले प्रबंधक की बर्खास्तगी की मांग कर सकती है। यूनियनों के आग्रह पर ऐसी बर्खास्तगियां होती हैं पर विरले ही। इसका कारण यह है कि अधिकांश सोवियत प्रबंधक ऐसे हैं जिन्होंने कर्मक्षेत्र में प्रवेश ही या तो मामूली मजदूरों के रूप में किया था या जो मजदूर वर्ग के परिवारों से आते हैं, और इससे प्रबंधकों और मजदूरों के बीच गंभीर टकराव के पैदा होने की संभावना कम हो जाती है।

अगर मजदूर यह समझें कि राज्य की आर्थिक योजना के लक्ष्य अवास्तविक हैं तो क्या वे उसे बदलवा सकते हैं?

जी हां, ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर किसी कारखाने या संयंत्र को उत्पादन की ऐसी योजना दी जाती है जिसके लक्ष्य के आंकड़े इतने ऊंचे हों कि वे अव्यावहारिक

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हां तो कारखाने के प्रबंधकों और ट्रेड यूनियन समिति को उसे परिमार्जित कराने का अधिकार है।

लेकिन आमतौर पर बात उल्टी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि राजकीय उत्पादन योजनाएं उत्पादन बढ़ाने की समस्त छिपी संभावनाओं को परिकल्पित नहीं कर पातीं। यह एक ऐसी चीज है जिसे जान सकने में वे कार्यकारी सामूहिक—कारखाने के मजदूर और प्रबंधक—ही सक्षम होते हैं जिन्हें राजकीय नियोजन विभिन्न कार्य-भार सौंपते हैं। ऐसी दशा में ट्रेड यूनियन संगठन स्वयं अपनी संशोधित योजनाएं तैयार करती हैं। ऐसी योजनाएं मजदूरों और सोवियत राज्य, दोनों का हित साधन करती हैं। लक्ष्य के बढ़ाये गये आंकड़ों को पूरा करने वालों को अधिक बोनस मिलता है। १९७६ में इस प्रकार की तकरीबन १४,००० योजनाएं मंजूर हुई थीं।

क्या सोवियत संघ में ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को सीमित करने वाले कानून भी हैं ?

पिछले ६० वर्षों में इस देश में ऐसा एक भी कानून पारित नहीं हुआ है जिसने ट्रेड यूनियनों के अधिकारों में लेशमात्र कटौती की हो या कटौती करने का प्रयास किया हो। ट्रेड यूनियनों को किसी सरकारी निकाय के पास अपना पंजीकरण नहीं कराना पड़ता। साथ ही न तो उनके कार्यकलाप पर और न उनके बजट पर सरकार का नियंत्रण होता है। ट्रेड यूनियनें स्वतंत्र संगठन होती हैं तथा सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों के नियमों और ब्रांच यूनियनों के नियमों के अनुसार कार्य करती हैं।

क्या सोवियत नागरिक स्वयं अपने संगठन कायम कर सकते हैं और अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित कर सकते हैं ?

निश्चय ही वे ऐसा कर सकते हैं और इस अधिकार का वे व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं। इस देश में विविध सार्वजनिक संगठन हैं। ट्रेड यूनियनों के अलावा नौजवान और खेलकूद संगठन, संगीतकारों, लेखकों, पत्रकारों और कलाकारों की यूनियनें, सहकारी संघ, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य संगठन हैं।

सोवियत संघ का संविधान सार्वजनिक संगठनों में संयुक्त होने के सोवियत नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। स्वैच्छिक सोसाइटियां और संगठन

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विदेशों के इसी प्रकार के संगठनों से संपर्क रखते हैं तथा अन्य देशों से आने वाले अभ्यागतों का आतिथ्य करते हैं। वे तत्संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हाते हैं। जन संगठन कानून निर्माण के लिए विधेयक पेश कर सकते है। तथा राजसत्ता के निकायों के चुनाव में उम्मीदवार मनोनीत कर सकते हैं।

राजकीय निकाय जन संगठनों को भवन, संचार साधन, मुद्रण-गृह, कागज का भंडार आदि सुलभ करते हैं, अर्थात उन्हें अपनी पत्रिकाओं, पुस्तकों और पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिए भौतिक परिस्थितियां सुलभ करते हैं।

उदाहरण के लिए लेनिनवादी तरुण कम्युनिस्ट लीग (वाइसीएल या कोम्सो-मोल) नामक संगठन के सदस्य देश के ३.४ करोड़ युवा नर-नारी हैं। कोम्सोमोल २.३ करोड़ स्कूली बच्चों के तरुण पायनिर संगठन के कार्य का निर्देशन करता है। उसे नौजवानों के बीच विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यकलाप के लिए व्यापक सुविधाएं प्राप्त हैं : वह स्कूली बच्चों और तरुणों के लिए लगभग २२६ समाचारपत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जिनकी कुल सात करोड़ से ज्यादा प्रतियां वितरित होती हैं; उसके पास तीन प्रकाशनगृह भी हैं जो सालाना पुस्तकों और पुस्तिकाओं की लगभग पांच करोड़ प्रतियां प्रकाशित करते हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

२. अर्थशास्त्र, नियोजन, रोजगार

पिछले ६० वर्षों में विश्व के औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में सोवियत औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार बढ़ा है ?

नीचे की तालिका में विश्व के औद्योगिक उत्पादन में अमरीका के कतिपय महत्वपूर्ण सूचकांकों के संदर्भ में सोवियत संघ के हिस्से में हुई वृद्धि को निर्देशित किया गया है :

विश्व के औद्योगिक उत्पादन में सोवियत संघ का हिस्सा	१९१३	१९७५
	४%	२०%
अमरीका के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में सोवियत संघ का उत्पादन :		
औद्योगिक उत्पादन	१२·५	८० से अधिक
विद्युत उत्पादन	८	५०
तेल उत्पादन	२७	१२०
इस्पात उत्पादन	१५	१२८
कृत्रिम उर्वरक उत्पादन	३	१२५
सीमेंट उत्पादन	१३	१८८

क्रांति के पूर्व का रूस १९१३ में अपने आर्थिक विकास के शिखर पर पहुँच गया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, गृह युद्ध और विदेशी सैनिक हस्तक्षेप का दौर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आ गया और इन सभी के फलस्वरूप देश का अर्थतंत्र वर्षों पीछे चला गया। फिर कहीं १९२६ में जा कर सोवियत संघ औद्योगिक विकास के १९१३ के स्तर पर दुबारा पहुँच सका।

देश के आर्थिक विकास को जिन कठिनाइयों और पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार पेश किया जा सकता है। लगभग २० वर्ष सोवियत संघ पर थोपे गये युद्धों को लड़ने और युद्ध-ध्वस्त अर्थतंत्र का पुनरुद्धार करने में लग गये। इसलिए आमतौर पर आंका जाये तो सोवियत राज्य को आर्थिक विकास के अपने वर्तमान स्तर पर पहुँचते ६० वर्ष नहीं बल्कि मात्र ४० वर्ष लगे।

विकास की इस गतिशील दर से ही पूंजीवादी जगत के हिमायती भयभीत हैं जिसका अर्थतन्त्र वास्तव में पिछले दशक में जहा का तहां ठप पड़ा रहा है। वे यह चाहते हैं कि वे बड़े पैमाने पर हथियारों का और भी निर्माण करें जिसमे हम भी अपनी प्रगति की कीमत पर, प्रतिरक्षा पर अधिक धन खर्च कर और इस प्रकार हमारे आर्थिक विकास की दर को वे धीमा कर सकें। और अधिकाधिक हथियारों की वावलेपन से भरी अपनी आकांक्षाओं को उचित ठहराने के लिए वे ढोंग रचते हुए 'सोवियत सैनिक खतरे" की बातें करते हैं।

हमने १९१३ के आंकड़ों से १९७५ के आंकड़ों की तुलना की है। १९७५ का साल नवीं पंचवर्षीय योजनावधि का आखिरी साल था। वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजना (१९७६-८०) के आर्थिक लक्ष्य और भी ऊंचे हैं। इस अवधि के अंत तक गल्ले की सालाना पैदावार में चार करोड़ टन की वढ़ोतरी हो जायेगी; इस्पात का उत्पादन २·७२ करोड़ टन, तेल का १४·९२ टन, प्राकृतिक गैस का १,४५७ अरब घन मीटर, तथा बिजली का ३,४१४ अरब किलोवाट घंटे बढ़ जायेगा।

सोवियत संघ में भूमि, खनिज संसाधनों तथा उत्पादन के बुनियादी साधनों का स्वामी और प्रशासनकर्ता कौन है ?

हमारे देश में भूमि और खनिज संपदा राष्ट्रीय संपत्ति हैं। भूमि का प्रशासन निर्वाचित सरकारी निकाय—मेहनतकशों के प्रतिनिधियों की सोवियतें—करती हैं। भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती। वह सट्टे के सौदों की चीज नहीं बन सकती। कारखानों, मकानों, सड़कों आदि के लिए निर्माण स्थल खरीदे नहीं जा सकते बल्कि सोवियतें उन्हें मुफ्त आवंटित करती हैं।

सामूहिक फार्म जिस जमीन पर खेती-बाड़ी करते हैं, वह भी राष्ट्रीय संपत्ति

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

होती है और राज्य ने उसे स्थायी तौर पर उपयोग के लिए फार्मों में मुफ्त में सुलभ कर रखा है। मशीनरी, इमारतों, मरम्मत की कर्मशालाओं, प्रोसेसिंग उद्यमों आदि जैसे उत्पादन के अन्य साधन सामूहिक फार्मों के होते हैं। गर्मघरों, मशीन कर्मशालाओं आदि जैसे बहुत से विशाल कृषि उद्यमों पर कई सामूहिक फार्मों का सहकारी आधार पर स्वामित्व होता है।

अनेक औद्योगिक उद्यम राज्य के हैं और उनका संचालन सोवियत संघ के अथवा संघीय जनतंत्र के स्तर के मंत्रालयों के तत्संबद्ध विभाग करते हैं। अधिकांश स्थानीय औद्योगिक उद्यमों और रोजमर्रे के सेवाइ-प्रतिष्ठानों का संचालन स्थानीय सोवियतें करती हैं।

खानगी (व्यक्तिगत) और निजी (वैयक्तिक) संपत्ति में आप क्या विभेद करते हैं ?

हम उस संपत्ति को खानगी या व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं जो दूसरों के कार्य के शोषण से प्राप्त की गयी हो तथा जो शोषण का उद्देश्य सिद्ध करती हो। सोवियत संघ में ऐसी संपत्ति का अस्तित्व नहीं है।

यहां नागरिकों की निजी या वैयक्तिक संपत्ति होती है। इसका स्रोत उनका स्वयं अपना कार्य होता है और उसका उद्देश्य है उनकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की तुष्टि करना। सोवियत जनता की वास्तविक आमदनी ऐसी दर से बढ़ती रही है कि वह हर पंद्रह वर्ष में दुगुनी हो जाती है। आय का उत्तरोत्तर बढ़ा हिस्सा टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियों जैसे फर्नीचर और कालीन, कार, टेलीविजन और टेपरिकार्डर, आमोद, नौका तथा निजी मकान पर खर्च किया जाता है। प्रसंगवश बता दिया जाये कि सोवियत संघ में हर साल बीस लाख से ज्यादा फ्लैट और एक-कुटुंब मकान बनते हैं जिनमें से चार-पांचवें राज्य के होते हैं तथा एक-पांचवें नागरिकों की निजी संपत्ति होते हैं।

कोई व्यक्ति अपनी अर्जित आय, पेंशन, छात्रवृत्ति अनुदान अथवा राज्य द्वारा दिये गये किसी भी भत्ते से जो चाहे कर सकता है। उस धन से खरीदी गयी चीजें निजी या वैयक्तिक संपत्ति होती हैं जिसके अधिकार की कानूनन गारंटी की गयी है। उनके स्वामी चाहें तो उन्हें किसी को बेच दें, दान कर दें या अपने वारिसों के लिए छोड़ दें।

सोवियत संघ में भूमि, खनिज संपदा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, और उत्पादन के

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

बुनियादी साधनों को न तो बेचा जा सकता है और न उन पर वैयक्तिक संपत्ति के रूप में स्वामित्व कायम किया जा सकता है। कोई सामूहिक किसान स्वयं अपनी निजी जोत पर खेती-बाड़ी के लिए जरूरी तकनीकी साधन अपने स्वामित्व में रख सकता है। लेकिन उसे भाड़े पर मजदूरी कराने की इजाज़त नहीं होती।

क्या सोवियत संघ में उद्यम ("जोखिम") की सराहना होती है ?

बखूबी होती है और उसे सक्रिय रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन तभी जब कि वह समाज का हित साधन करे।

उदाहरणार्थ, प्रबंधक अपने कारखाने के संचालन के लिए निर्धारित धनराशि का उत्तम से उत्तम उपयोग करने में विशेष क्षमता का परिचय देता है : वह कार्य-कुशलता सूझ-बूझ से संपन्न तथा स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है जिससे वह योजना लक्ष्यों को यथासंभव अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर सके। इन सारी बातों का स्वागत होता है।

लेकिन वह अगर अपनी प्रतिभा का उपयोग निजी लाभ के लिए करता है, या किसी खास प्रतिष्ठान को अन्य की कीमत पर, समाज और राज्य के अहित में बढ़ाता है, तो वह मुसीबत ही मोल लेता है। ऐसे उद्यम या "जोखिम" को बढ़ावा देने की बात तो दूर रही, उसके कानूनी नतीजे भी निकल सकते हैं।

पूंजीवादी मुक्त-उद्यम प्रणाली में दुकानदार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी दराजों में पर्याप्त माल मौजूद रहे, क्योंकि ये उसके मुनाफे का स्रोत हैं। तथा कारखानेदार और थोक व्यापारी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दुकानदार की मांगों को तुष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह समझ सकना मुश्किल है कि आप के देश के लोग मुनाफे की प्रेरणा के बिना समाज के लाभ के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं।

हम लोगों में बाल्य-काल से ही समाज के हितों को स्वयं अपने हितों से ऊपर स्थान देने की आकांक्षा पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसका अलबत्ता

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह अर्थ नहीं कि हम लोगों के निजी हितों की अवहेलना करते हैं क्योंकि वे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारी राय में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि सोवियत नागरिकों के वैयक्तिक और सार्वजनिक हितों के बीच यथासंभव अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाये। बहरहाल, हमारी नजर में इसकी कोई वजह नहीं कि दोनों में टकराव ही क्यों हो। सोवियत स्टोर का प्रबंधक अपने जिम्मे की दुकान को इस प्रकार चलाने की कोशिश करता है कि वह मुनाफा दे। वे और उसके सहायक योजना के लक्ष्य से बढ़ कर जितना ही माल बेचते हैं, उतना ही ज्यादा बोनस उन्हें अपने कार्य के लिए मिलता है। इसलिए इसमें सोवियत प्रबंधक का भी निजी हित होता है कि अपने स्टोर के दराजों में वह अधिक से अधिक प्रकार के माल रखे। यही बात इन मालों को तैयार और सप्लाई करने वाले कारखानों के साथ लागू होती है। वह जितना ही अच्छा काम करता है, इन मालों के उत्पादन, सप्लाई और बिक्री से संबंधित लोगों को उतना ही ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है, तथा समाज (अर्थात ग्राहकों) को इस कार्य से उतना ही लाभ पहुंचता है। मालों के उत्पादन और बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करके और उनसे आगे बढ़ कर इस कार्य में लगे लोग सोवियत राज्य का हित साधन भी करते हैं। अत: हमारी जनता के पास उसके कार्य के लिए वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है, और दोनों परस्पर पूरक हैं।

सोवियत संघ में रोजगार आश्वस्त करने की समस्या कैसे हल की गयी है, तथा इस मामले में आपके दृष्टिकोण और पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है?

सोवियत संघ में रोजगार (पूर्ण रोजगार) आश्वस्त करने की समस्या आधी सदी पहले हल कर ली गयी थी। यह बात सोवियत संघ के संविधान में परिलक्षित होती है जो प्रत्येक नागरिक के लिए काम के अधिकार की गारंटी करता है।

हमारे विचार से काम का अधिकार किसी भी देश में जनवाद का पैमाना है। गारंटीशुदा रोजगार के बगैर कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता कि वह अपना और अपने कुटुंब का भरण-पोषण कर सकेगा; वह नियोजकों या मालिकों के हाथ का खिलौना बन जाता है जिनका आंख बन्द कर के हुक्म बजाना जरूरी हो जाता है, उसके सामने किसी भी समय बेरोजगारों की सेना में शामिल हो जाने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। आज पूंजीवादी देशों में १.८ करोड़ लोग (उनके परिवारों के सदस्यों को शामिल कर के ५ करोड़ लोग)

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पूर्ण बेरोजगार हैं जो या तो सहायता पर जी रहे हैं या कोई भी सहायता नहीं पा रहे हैं।

बेशक यह संयोग की बात नहीं कि पूंजीवादी देशों के संविधानों में काम के अधिकार की गारंटी नदारद है। पूंजीवादी जगत में बेकारी समाप्त करने का अर्थ होगा पूंजीवाद को समाप्त कर देना : खानगी या व्यक्तिगत स्वामित्व तथा उससे उत्पन्न व्यक्तिगत उद्यम की अराजकता के स्थान पर उत्पादन के साधनों के सार्विक स्वामित्व और नियोजित अर्थतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय पैमाने पर राज्यीय निजोजन के कारण हमारा देश किसी भी मौके पर और साथ ही दीर्घकालिक तौर पर भी श्रम की मांग और सुलभ जनबल के बीच तालमेल कर सकता है, तथा नये कारखानों को ऐसी जगह कायम कर सकता है कि जिससे अधिक मजदूरों को उत्पादन में लगाया जा सके।

सोवियत संघ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पूर्ण रोजगार आश्वस्त करने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं, किंतु पूंजीवादी देशों के विपरीत हमारे सामने मुख्य समस्या रोजगार के बजाय मजदूरों की कमी की है। आज ३० साल से ज्यादा दिनों से सोवियत अर्थतंत्र में जनबल की मांग सप्लाई से बढ़ कर रही है।

अगर किसी को रोजगार से हाथ धोने का भय न हो तो आप इस बात की कैसे गारंटी करेंगे कि लोग काम करें?

हम भय-प्रेरित अनुशासन का नहीं, सामाजिक चेतना पर आधारित कार्य के प्रति विवेकपरायण दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी यह नीति उचित है, हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है।

हमारे देश में जहां पूर्ण रोजगार सुनिश्चित है तथा जहां काम करने वालों से काम ज्यादा है, किसी व्यक्ति को दरअसल बेरोजगारी का कोई डर ही नहीं है। उसे अच्छी तरह काम करने को प्रेरित करने वाली चीजें हैं उसके परिवार की खुशहाली, जो उसके काम से सीधे जुड़ी है, तथा नैतिक प्रेरणाएं—यह चेतना कि राष्ट्रीय संपदा बढ़ाने से सभी का जीवन-स्तर उन्नत होता है। हां, इस चेतना के स्तर को काफी उच्च स्तर का होना जरूरी है। खेद की बात है कि हमारे देश में कुछ लोगों में यह चेतना हमारे समाज में जनवाद के स्तर के समकक्ष नहीं होती।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किंतु हम इस समस्या को जनतांत्रिक अधिकारों (जैसे रोजगार की गारंटी) और स्वतंत्रताओं (जैसे बेरोजगारी से मुक्ति) में कटौती कर के नहीं, बल्कि जनता की सामाजिक चेतना के स्तर को ऊंचा उठा कर हल करने का प्रयास करते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारा रास्ता ही समाजवादी राज्य के लिए स्वीकार्य हो सकता है।

आपका एक लक्ष्य रहा है जनतंत्रों के आर्थिक विकास को लगभग समान स्तर पर लाना। किंतु निश्चय ही यह अधिक उद्योग संपन्न क्षेत्रों की कीमत पर ही संभव है। क्या यह उचित है ?

अगर आप दीर्घकालिक राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हों तो यह उचित है।

अक्तूबर क्रांति के समय रूस के जनगण सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकास के बहुत ही भिन्न-भिन्न स्तरों पर थे। रूस का यूरोपीय भाग और उक्राइन कुछ हद तक उद्योगीकृत थे; ब्येलोरूस और ट्रांसकाकेशिया बहुत पीछे थे, तथा मध्य एशिया और कजाखस्तान के जनगण अभी भी सामंतवाद में जी रहे थे। रूसी मजदूर वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी ने यथासंभव शीघ्र से शीघ्र खाई पाटने के लिए देश के पिछड़े सरहदी प्रदेशों की सहायता करना अपना अंतर्राष्ट्रीयतावादी कर्त्तव्य माना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-३२) के कार्यान्वयन के साथ सोवियत संघ के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन का परिमाण दुगुना हो गया तथा सरहदी जनतंत्रों में ३.५ गुना हो गया। मध्य एशियाई जनतंत्रों में यह वृद्धि और भी अधिक रही—तकरीबन पांच गुनी। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी कुछ हद तक केंद्रीकृत नियोजन और एकीकृत प्राविधिक नीति के फलस्वरूप वृद्धि की ऊंची दरें बरकरार रखी गयीं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हेतु था राष्ट्रीय आय का केंद्रीकृत पुनर्वितरण। दी गयी सहायता का एक उदाहरण यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ताजिक सोवियत समाजवादी जनतंत्र का बजट ४१.७ करोड़ रूबल का था जब कि स्वयं जनतंत्र की अपनी आय से केवल १२.७ करोड़ रूबल की पूर्ति हुई थी।

आमतौर पर सोवियत अर्थतंत्र की विशेषता वृद्धि की ऊंची दरें हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों और जनतंत्रों में चमत्कारी आर्थिक वृद्धि हुई जिसका श्रेय कमजोर जनतंत्रों के अर्थतंत्रों को निर्मित करने को प्राथमिकता देने की लेनिनवादी नीति को है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जाहिर है, इससे देश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत भागों की प्रगति पर असर पड़ा, लेकिन अल्पकालिक दृष्टि से ही—तभी तक जब तक कि उनके और कम विकसित जनतंत्रों के बीच विषमता काफी अधिक बनी रही। उस बिंदु को पार कर लेने के बाद सभी जनतंत्र अपनी सर्वनिष्ठ समृद्धि के लिए उन अन्य समस्याओं पर शक्ति केंद्रित कर सके जो कम महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नहीं थे। यह कार्य शक्ति जुटा कर और आर्थिक विशेषीकरण द्वारा किया गया।

क्या राजकीय योजनाएं समाजवादी समाज के हर पहलू को समेट लेती हैं?

नहीं, और ऐसा इरादा भी कभी न था।

भूमि, खनिज संपदा और उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व के कारण राष्ट्रव्यापी पैमाने पर नियोजन लागू किया जा सकता है। समाजवादी राज्य संपूर्ण जनता के आधारभूत दीर्घकालिक हितों को दृष्टि में रखकर अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियां निर्धारित करता है। वह संसाधनों के नियोजित उपयोग तथा उत्पादक शक्तियों के युक्तिसंगत वितरण के जरिए बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं की तुष्टि करता है। नियोजन सोवियत आर्थिक प्रबंध की नीव का पत्थर है और इससे महत्वपूर्ण नतीजा हासिल हुआ है। समाजवादी समाज आर्थिक संकटों, बेकारी और मुद्रास्फीति से मुक्त हो गया है जो पूंजीवादी देशों के अर्थतंत्रों के अभिन्न सहचर हैं।

किंतु हमारे राज्य ने बारीक से बारीक ब्यौरे तक आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियोजित करने और नियमों-नियंत्रणों से जकड़ देने के असंभव काम का बीड़ा नहीं उठाया है। राज्यीय केन्द्रीय योजना निकाय कोयले, तेल, इस्पात, गल्ले आदि राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार कर लेते हैं तथा आवश्यक विनियोगों के बारे में फैसला कर लेते हैं और उसके बाद स्थानीय पहल जिम्मा संभाल लेता है। इस बात का फैसला स्थानीय स्तर पर होता है कि योजना के लक्ष्य अच्छी से अच्छी तरह कैसे पूरे किये जा सकते हैं तथा आवंटित राशियों का अधिक से अधिक कार्य-कुशलता के साथ उपयोग कैसे किया जाये। दूसरे शब्दो में, योजना के सांचे के भीतर पहल की जिम्मेदारी होती है, ऐसे पहल की जिससे समाज के और आगे के विकास के लिए हर प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या समाजवादी नियोजन पूंजीवादी प्रतियोगिता का स्थान ले सकता है ?

सबसे पहले तो पूंजीवादी प्रतियोगिता है क्या ? यह परिचय के शब्दों में "स्वतंत्र बाजार" में औद्योगिक या व्यापारिक संस्थाओं के बीच और व्यक्तियों के बीच चलने वाला संघर्ष है। पश्चिम में जिसे "स्वतंत्र बाजार" कहते हैं, हम उसे अराजकता की अवस्था कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे की हार या विनाश होता है।

जैसा कि ऐश्ले मांटेगू ने दी अमेरिकन वे आफ लाइफ में लिखा है : "अमरीकी जीवन पद्धति का सिद्धांत है प्रतियोगिता। इसका सीधा-सादा रूप यह रह जाता है कि आप आगे बढ़कर दूसरे से बेहतर कुछ कर दिखाइए, चाहे ऐसा करने की धुन में आप उसे और उसके परिवार को नुकसान भी पहुंचा दें। वह आपके सरोकार का कोई विषय नहीं। आखिर आपकी चिंता के लिए आपका परिवार है। प्रतियोगिता के सिद्धांत में आपकी प्रतियोगिता की वृत्ति से दूसरों के लिए होने वाले परिणामों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता सन्निहित होती है"।*

प्रतियोगिता उस समाज की वस्तु है जहां व्यक्तिगत संपत्ति का वर्चस्व हो, और उसका नियम है "हर व्यक्ति अपने लिए"।

प्रतियोगिता, उद्यम, नवीनता और कार्यकुशलता बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इतना ही नहीं; वह लोभ, निर्ममता, सार्वजनिक हितों के प्रति उदासीनता, स्वार्थ-परायणता को भी जन्म देती है।

चूंकि हमारे यहां व्यक्तिगत, पूंजीवादी संपत्ति नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता के लिए जमीन ही नहीं है। व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह हमारे यहां सार्वजनिक स्वामित्व है। एक मात्र स्वामी—जनता—ही सोवियत कारखानों का स्वामी है, और उन कारखानों को एक-दूसरे के खिलाफ संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनके पास ऐसे कोई औद्योगिक रहस्य नहीं होते जिन्हें ताले-चाभी में बंद कर रखना पड़ता हो। प्रविधि श्रम के संगठन आदि के क्षेत्र की प्रत्येक उपलब्धि जैसे ही लागू होती है, सब की संपत्ति बन जाती है। कारण साफ है कि सोवियत परिस्थितियों में और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमे सभी को लाभ होता है।

साथ ही हमारे यहां प्रतियोगिता है भी, और हम इसे प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं उसे हम समाजवादी स्पर्धा आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में करोड़ों लोग —चाहे वे किसी कर्मशाला में हों, या फार्म पर, या रेलवे में— सर्वश्रेष्ठ कर्मियों के

---

*एश्ले मांटेगू, *दी अमेरिकन वे ऑफ लाइफ*, न्यूयार्क, १९६७, पृष्ठ १०६।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

चरण-चिह्नों पर चलने, होड़ा-होड़ी करने, स्पर्धा करने का प्रयास करते हैं; वे समय से पहले और दूसरों से कम प्रयास द्वारा योजना को पूरा करने, तथा क्वालिटी सुधारने और लागत कम करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। वे काम को कर दिखाने के ज्यादा अच्छे और ज्यादा द्रुत तरीके खोजते हैं, सुझाव देते है और आविष्कार करते हैं। स्पर्धा अभियान में भाग लेने वालों को दिया जाने वाला भौतिक पारिश्रमिक प्रत्येक सर्वनिष्ट ध्येय के लिए किये गये श्रम के समानुपात में होता है। हर व्यक्ति अपने कार्य के केवल उसी हिस्से में कार्यकुशलता बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है जिससे उसे अधिक आमदनी होती है, बल्कि उस हिस्से में भी रुचि लेता है जिसकी आय सार्वजनिक 'कोष' में या सामाजिक कोष में जाती हैं और अंततः उसी के पास, उसके परिवार, उसके संगी साथियों और सहनागरिकों के पास आधुनिक आवासों, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त स्कूली और उद्योगी शिक्षा आदि के रूप में वापस आ जाती है। इसके अलावा अलग-अलग मजदूर और टोलियां, पूरे के पूरे प्रतिष्ठान, नगर प्रदेश, और जनतंत्र स्पर्धा अभियान में भाग लेते हैं।

इस आंदोलन में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस क्रम में कोई बर्बाद नहीं होता। सर्वोत्तम परिणाम और विधियां सबकी संपत्ति बन जाती हैं। पिछड़ जाने वाले जीतने वालों से सीखते हैं। इसलिए औद्योगिक "वातावरण" सहायता और सहयोग का है। कम्युनिज्म के निर्माता का नैतिक सूत्र है: "एक सभी के लिए और सब एक के लिए"।

इस सिलसिले में ओदेस्सा के टर्नर जी. नेझेनेंको की कहानी लाक्षणिक उदाहरण पेश करती है। वे अब पेंशनयाफ्ता हैं और उन्हें विशेष पेंशन मिल चुकी है जो विशिष्ट कामगारों को मिलती है। नेझेनेंको के पिता क्रांति के पहले लोहारी करते थे और अपने हुनर के लिए विख्यात थे, और वे अपने व्यावसायिक गुर अपने तक छिपा कर रखते थे। जब कभी वे किसी घोड़े को नाल जड़ते तो कंधों के ऊपर से मुड़कर ताक लेते कि कोई देख तो नहीं रहा है। उनका बेटा योग्यता प्राप्त टर्नर या खरादिया था। (बृहत सोवियत विश्वकोश में उनका जिक्र एक ऐसे कटाई के औजार के सिलसिले में किया गया है जिसका उसने आविष्कार किया और जिसने टर्निंग या खरादगरी के धंधे में असली क्रांति ला दी।) वे अक्सर अनेक कारखानों का दौरा करते हैं जहां वे तेज गति से धातु-कटाई या खरादगरी की अपनी विधियां सिखाते हैं। उनकी अध्यक्षता में रेडियल मशीनी औजार तैयार करने वाले एक कारखाने के मजदूरों के लिए उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

नेझेनेंको पिता-पुत्र के उदाहरण से चारों ओर की सामाजिक परिस्थितियों तथा उस मनोवैज्ञानिक वायुमंडल का महत्व स्पष्ट हो जाता है जिसमें कोई व्यक्ति

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रहता है। सामाजिक परिस्थितियां मनुष्य के सदगुणों का दम घोंट भी सकती हैं तो दूसरी ओर उनके विकास में सहायक भी हो सकती हैं।

क्या केंद्रीकृत नियोजन स्थानीय पहल में अवरोध नहीं पैदा करता ?

आइए, हम एक ठोस उदाहरण लें। दसवें पंचवर्षीय काल (१९७६-८०) की योजना को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने २९ अक्तूबर १९७६ को स्वीकृत किया। इससे तकरीबन साल भर पहले सोवियत समाचारपत्रों ने अगले पांच वर्षों के लिए सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के निर्देशों का प्रारूप प्रकाशित किया था। प्रारूप का पूरे देश में स्थानीय स्तर पर अध्ययन किया गया, उस पर बहस हुई, तथा समूहों और व्यक्तियों से दस लाख से अधिक सुझाव, परिवर्धन और संशोधन प्राप्त हुए। उनमें से जो अधिक महत्वपूर्ण थे, उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत "१९७६-१९८० के लिए सोवियत संघ के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के निर्देश" में समाविष्ट कर लिया गया। अन्य आवश्यक सुझावों को विचार और मूल्यांकन के लिए विविध प्रतिष्ठानों को भेज दिया गया।

निर्देशों के आधार पर सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद ने राज्यीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, उसे वर्षों में, तथा मंत्रालयों और संघीय जनतंत्रों के अनुसार विभाजित किया। उस चरण में सोवियत संघ के सभी मंत्रालयों और विभागों, जनतंत्रीय मंत्रिपरिषदों, केन्द्रीय और स्थानीय आर्थिक निकायों, सोवियत संघ की विज्ञान अकादेमी तथा अन्य निकायों ने इस काम में हाथ बंटाया।

यह कार्य सर्वोच्च सोवियत की समितियों में जारी रखा गया, और इसके बाद जाकर सोवियत संसद ने पंचवर्षीय योजना संबंधी कानून पारित किया।

इस संक्षिप्त रूपरेखा से भी पता चल जाता है कि योजना को मुट्ठीभर नेता नहीं तैयार कर लेते हैं: योजना को तैयार करने, उस पर विचार-विमर्श करने और उसे स्वीकृत करने में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं—वे लोग जो बाद में योजना के प्रावधानों को अमल में उतारेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अगर आपकी योजनाओं में सब कुछ सुसमन्वित होता है तो उन्हें लक्ष्य से बढ़ कर क्यों पूरा किया जाता है ?

यह उतना आवश्यक नहीं जितना वांछनीय है। प्रत्येक राष्ट्रीय योजना में उत्पादन के लक्ष्य शामिल होते हैं जिन्हें अगर बढ़कर पूरा कर लिया जाता है तो उससे हर किसी को लाभ ही होगा। आमतौर पर आज की दुनिया में तेल, कोयले, आवास, उपभोक्ता माल आदि का बहुत ज्यादा हो जाना संभव नहीं। इसलिए सीधे उपभोग के लिए कार्य करने वाले उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम होते हैं।

क्या इसका यह अर्थ हुआ कि योजना का लक्ष्य जानबूझ कर निम्न स्तर पर रखा जाता है ? अर्थतंत्र की प्रत्येक शाखा में और प्रत्येक उद्यम में उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आरक्षित क्षमताएं होती हैं जिनका राष्ट्रीय योजना तैयार करते समय पहले ही अनुमान कर सकना कठिन है। यह अत्यंत वांछनीय है कि ऐसी आरक्षित क्षमताओं का उपयोग किया जाय, तथा योजना के लक्ष्य से बढ़ जाने के लिए कर्मशाला स्तर से सदा पहल होती है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा मजदूरों को अधिक उत्पादन पर बोनस प्राप्त होता है। निःसंदेह, यह समझदारी की बात न होगी कि टायरों के बगैर अतिरिक्त मोटर कारें बनायी जायें, अथवा खिड़कियों के बगैर मकान बनाये जायें, अथवा जहां बिजली ही न हो वहां बिजली के तार बनाए जायें। किसी चीज को योजना के लक्ष्य से बढ़कर उत्पादित करना तभी श्रेयस्कर होता है जबकि उत्पादन का यह कार्य आद्योपांत प्राविधिक लाइन पर किया जाये और जबकि—जो कि और भी जरूरी है—उस उत्पादन की मांग हो।

यह व्यापक रूप में विदित ही है कि पहले की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को लक्ष्य से बढ़कर पूरा किया जाता रहा है। वर्तमान पंचवर्षीय योजनावधि के प्रथम वर्ष १९७६ में योजना के लक्ष्य से बढ़कर किये गये उत्पादन का मूल्य ५ अरब रूबल से अधिक था। यह राशि सोवियत जनता द्वारा स्वय अपनी पहल से उत्पादित राष्ट्रीय संपदा में अभिवृद्धि का परिचायक है। यह रकम पांच लाख से ज्यादा फ्लैटों का निर्माण करने के लिए, अथवा साइबेरिया में अंगारा नदी पर बने विराट ब्रात्सक बिजलीघर के आकार के छह पनबिजलीघरों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त है।

सामूहिक फार्म और राजकीय फार्म में क्या अंतर है ?

राजकीय फार्म कारखानों, खानों आदि की तरह राज्य के स्वामित्व के उद्यम होते हैं। तथा सामूहिक फार्म सामूहिक स्वप्रशासित अर्थतंत्र, अथवा उत्पादन सहकार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

होते हैं। सोवियत संघ में कोई २८,००० सामूहिक फार्म तथा १८,००० राजकीय फार्म हैं।

राजकीय फार्म में उत्पादन के सारे साधन राज्य की सम्पत्ति होते हैं। राजकीय फार्म में उत्पादन कार्य में लगे लोग मजदूर वर्ग का एक हिस्सा होते हैं तथा उन्हें कारखाना मजदूरों की ही भांति अधिकार प्राप्त होते हैं और वे सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की उसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। राजकीय फार्म की सारी पैदावार राज्य की होती है।

सामूहिक फार्म बिलकुल दूसरे ही आधार पर कार्य करता है। वहां जमीन के अलावा उत्पादन के सारे साधन फार्म के सदस्य किसानों की सामूहिक संपत्ति होते हैं। सामूहिक स्वामित्व वाले खेतों या पशुधन से प्राप्त पैदावार सामूहिक फार्म की होती है और वही इस बात का फैसला करता है कि उसका किस तरह निबटान किया जाये। वह उसका एक हिस्सा स्वयं अपनी जरूरतों या अपने सदस्यों में वितरण के लिए रख लेता है; एक हिस्सा वह राज्य को बेच देता है और शेष को वह सामूहिक फार्म मंडियों में या व्यापार सहकारों के जरिए बेच सकता है। कुछ सामूहिक फार्म बड़े और छोटे नगरों में स्वयं अपनी दुकानें चलाते हैं अथवा मंडियों में अपनी दुकानें रखते हैं।

राजकीय फार्म का प्रबंध राज्य द्वारा नियुक्त कार्याधिकारी करते हैं तथा सामूहिक किसान अपने प्रबंधक चुनते हैं।

सामूहिक फार्मों के अपने नियम होते हैं जो सामूहिक फार्म-जीवन को शासित करने वाले एक प्रकार के संविधान होते हैं। सामूहिक फार्म का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय उसके सदस्यों की आम बैठक होती है। वह एक अध्यक्ष समेत एक बोर्ड या मंडल का चुनाव करती है। यह एक सामूहिक कार्यकारी-प्रशासनिक निकाय होता है जो फार्म के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलाप की देखभाल करता है तथा सरकारी निकायों, सार्वजनिक संगठनों और अन्य सामूहिक फार्मों के साथ उसके संबंधों के मामले में उसका प्रतिनिधित्व करता है। आम बैठक निगरानी समितियों का भी चुनाव करती है जो बोर्ड या अध्यक्ष से स्वतंत्र होती हैं और जिनकी जवाबदेही सामूहिक फार्म के सारे सदस्यों के प्रति ही होती है।

राजकीय और सामूहिक फार्म एक योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। राजकीय फार्मों का नियोजन सीधे राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजनाओं के साथ समन्वित होता है। सामूहिक फार्मों का नियोजन बिलकुल भिन्न होता है।

एक ओर राज्य सामूहिक फार्म से यह नहीं कह सकता कि वह कितनी पैदावार करे तथा कितना बेचे और कितना स्वयं अपनी जरूरतों के लिए रखे। दूसरी ओर, राज्य के लिए पहले से यह जानना जरूरी है कि वह क्या अपेक्षा कर सकता है। मुद्दा

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यह है कि सोवियत कृषि पैदावार में सामूहिक और राजकीय फार्मों का हिस्सा तकरीबन बराबर-बराबर है जिससे राष्ट्रीय अर्थतंत्र में सामूहिक फार्मों का अंशदान बहुत बड़ा होता है। अगर सामूहिक फार्म की पैदावार में अराजकता हो तो राष्ट्र-व्यापी पैमाने पर कोई नियोजन नहीं हो सकता।

व्यवहार से प्रेरित होकर एक ऐसी प्रणाली निर्मित हो गयी है जिसकी मदद से राज्य निर्णय लेने में सामूहिक फार्मों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किये बगैर तथा सामूहिक फार्म जनवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन किये बगैर पैदावार की एक निश्चित मात्रा प्राप्त कर लेता है।

यह प्रणाली इस प्रकार है। सामूहिक फार्म राज्य के साथ कुछ वर्षों के लिए पहले से ही एक प्रकार का सप्लाई संबंधी ठहराव या करार कर लेता है जो "अचल योजना" कहलाता है। इसमें उत्पादन का एक न्यूनतम आंकड़ा मान लिया जाता है जिसे पूरा कर लेना बखूबी सामूहिक फार्म की क्षमता के भीतर होता है और जिस पर राज्य भरोसा कर सकता है। सामूहिक फार्म इस न्यूनतम से ऊपर जितनी भी पैदावार करता है उसे सरकार बढ़ौती मूल्यों पर खरीदने का जिम्मा लेती है। इससे सामूहिक फार्म के लिए पैदावार को विस्तृत और सघन बनाना लाभकर होता है।

सामूहिक फार्म विशाल और अत्यंत यंत्रीकृत कृषि उद्यम बन गये हैं। एक सामूहिक फार्म आज औसतन ६,५०० हेक्टर (१६,००० एकड़) का होता है तथा उसमें लगभग ५,००० चौपाये होते हैं। औसत राजकीय फार्म इसके दुगुने आकार का होता है।

सामूहिक फार्मों के विकास तथा देश की आर्थिक क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप सामूहिक किसानों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक उपाय करना, गारंटीशुदा वेतन तथा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली लागू करना संभव हो गया है। इन सारी बातों से सामूहिक किसानों और राजकीय फार्म श्रमिकों के रहन-सहन और कार्य की परिस्थितियों को समान स्तर पर लाने तथा नगरों और देहातों के बीच रहन-सहन की परिस्थितियों में विषमता को और भी कम करने में मदद मिली।

आप इस बात का कैसे स्पष्टीकरण देते हैं कि जारशाही रूस गल्ले का निर्यात करता था और सोवियत संघ आयात करता है?

जिन दिनों १९०९ और १९१३ के बीच रूसी पूंजीवाद अपनी पराकाष्ठा पर था, देश सालाना औसतन १.१ करोड़ टन गल्ला निर्यात करता था। उन दिनों किसान व्यवहारतः केवल गल्ले का ही उत्पादन करता था जो ८८.५ प्रतिशत

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

काबिलकाश्त जमीन में फैला था तथा ब्रेड ही उसका मुख्य आहार था। अगर गल्ले का निर्यात होता था तो इसका यह अर्थ नहीं कि जारशाही रूस में फाजिल अनाज था। १९११ में ३ करोड़ लोग (रूस की २० प्रतिशत आबादी) भूखे थे। किन्तु विश्व में बाजार की स्थिति अत्यंत अनुकूल थी तथा रूसी गल्ले का निर्यात १.३५ करोड़ टन के रिकार्ड तक पहुंच गया था।

आज क्रांति के पहले के काल की तुलना में पैदावार तीन-गुनी हो गयी है, और फिर भी सोवियत संघ गल्ला खरीदता है। क्यों ?

सोवियत काल में आबादी का आहार आमूल बदल गया है। १९१३ में ब्रेड की प्रति व्यक्ति खपत २०० किलोग्राम और मांस की २९ किलोग्राम थी। आज यह १४२ किलोग्राम ब्रेड और ५८ किलोग्राम मांस हो गयी है। ब्रेड अब प्रतिदिन का मुख्य आहार नहीं रह गया है और उसका स्थान अधिक पोषक मूल्य के पशु उत्पादों ने ले लिया है। किन्तु मांस की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने के उद्देश्य से पशुधन फार्मों का सघन विकास करने के लिए चारे के रूप में बड़े परिमाण में गल्ले की जरूरत पड़ती है।

एक अग्रणी सोवियत अर्थशास्त्री अकादेमीशियन नेम्चिनोव ने अनुमान लगाया है कि देश में गल्ले की कुल मांग प्रति निवासी एक टन सालाना है। नीचे की तालिका सोवियत संघ में अनाज की उपज और आबादी में वृद्धि के बीच का संबंध प्रस्तुत करती है :

वर्ष	गल्ले की औसत सालाना पैदावार (करोड़ टनों में)	वृद्धि (प्रतिशत)	वर्ष	आबादी में वृद्धि (करोड़ों में)	वृद्धि (प्रतिशत)
१९६१-१९६५	१३.०३	—	१९६६	२३.२२	—
१९६६-१९७०	१६.७६	२२.७	१९७१	२४.३९	५.०
१९७१-१९७५	१८.१५	७.७	१९७६	२५.५५	४.७

आठवें दशक के पूर्वार्द्ध में अनाज की पैदावार की वृद्धि की दर में जो गिरावट आयी, उसका कारण, जैसा कि विदित है, देश को प्रताड़ित करने वाले विनाशकारी सूखों से फसल का चौपट हो जाना था। किन्तु इतने पर भी गल्ले की पैदावार बढ़ी। फसल के चौपट होने को यथोचित ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि सोवियत संघ में गल्ले की पैदावार आबादी से कहीं ज्यादा गति से बढ़ रही है, और संकेत इस बात के हैं कि प्रति व्यक्ति एक टन का अंतिम लक्ष्य

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

समय के भीतर प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही हमें चारे के लिए अनाज की आवश्यकता बनी हुई है। इसका ब्रेड से तो सीधा ताल्लुक नहीं है। पिछले दस वर्षों में हुई सबसे कम पैदावार (१९७५ में १४ करोड़ टन—सूखे का परिणाम) भी पूरे देश में ब्रेड और आटे से बने अन्य आहारों की पूरी तरह यथेष्ट और अबाध सप्लाई आश्वस्त रखने के लिए जितना गल्ला चाहिए, उससे काफी ज्यादा है।

जब तक सोवियत संघ ने अपने पशुपालन को औद्योगिक लाइनों पर रखना शुरू नहीं किया था, तब तक चारे के गल्ले की गहरी कमी महसूस नहीं की गयी थी। यह महत्वपूर्ण है कि १९६० में, गल्ले की कुल पैदावार मात्र १२.५५ करोड़ टन थी, ६८ लाख टन का निर्यात किया गया था और केवल दो लाख टन का आयात करना पड़ा था।

अब चारे के लिए सालाना १० करोड़ टन से अधिक गल्ले की जरूरत पड़ती है, और इस आवश्यकता को २२-२३.५ करोड़ सालाना गल्ले की पैदावार होने पर भी, जो वर्तमान मानकों के अनुसार भारी पैदावार मानी जाती है, इस मांग की आयात के बगैर पूर्ति मुश्किल है। इसी कारण सोवियत संघ अनाज खरीद रहा है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पहले की वचनबद्धताओं को निभाते हुए सूखे के सालों में भी गल्ले को केवल खरीदता ही नहीं बल्कि बेचता भी है। लेकिन इसका संबंध चारे से नहीं बल्कि 'खाद्यान्न" से है।

सोवियत संघ में गल्ले की उपजें पश्चिमी यूरोप और अमरीका से कम क्यों होती हैं?

प्राकृतिक परिस्थितियां मुख्य कारण हैं।

अमरीका में कृषि-योग्य आधी जमीन पर साल भर में कम से कम ७०० मिलीमीटर वर्षा हो जाती है। बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस के गल्ला पैदा करने वाले मुख्य गल्ला-उत्पादक इलाके भी समानतः ठीक-ठाक रहते हैं। अमरीका की सिर्फ एक फीसदी काबिलकाश्त जमीन अपर्याप्त नमी के क्षेत्र में है तथा पश्चिमी यूरोप को आम तौर पर इन कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं पड़ता। यह लाक्षणिक ही है कि १९७६ के सूखे को वहां "सदी का जलवायु संकट" माना गया।

सोवियत संघ में गल्ले की दो-तिहाई फसलें जहां से प्राप्त होती हैं वे भारी जोखिम के इलाके कहलाते है। ४० प्रतिशत काबिलकाश्त जमीन पर साल भर में

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

४०० मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तथा इष्टतम ७०० मिलीमीटर वर्षा केवल एक प्रतिशत काबिलकाश्त जमीन पर होती है।

और अपर्याप्त वर्षा ही सोवियत कृषि की एक मात्र मुसीबत नहीं है। मसलन १६७६ मे वर्षा तो पर्याप्त हुई लेकिन मौसम फसल के लिए आवश्यकता से अधिक ठंडा था। फिर अगर जाड़ों में हिमपात बहुत कम हुआ तो शरद में बोयी गयी फसल अक्सर जम जाती है। जहां तक उत्तर और साइबेरिया का सवाल है, वहां तो गल्ले की पैदावार के लिए हालात लगभग हर साल मुश्किल रहते हैं। वसंत में देर से होने वाला तुषारपात जून के आरंभ में समाप्त होता है और शरद के शुरू के दिनों का तुषारपात कभी-कभी जुलाई के अंत में ही शुरू हो जाता है।

लेखा-जोखा कर के विशेषज्ञ लोग यह कहते हैं कि सोवियत संघ के कृषि क्षेत्र में जैव-जलवायु शक्यता अमरीका और पश्चिमी यूरोप की केवल आधी है। इसीलिए उपज कम होती है।

अगर अनावृष्टि होगी तो खेत सूखे से दग्ध हो ही जायेंगे, चाहे उसे जिसने बोया हो, सामूहिक किसान ने या निजी किसान ने। १६७६ में जब फ्रांस वर्षा न होने के कारण अच्छी फसल प्राप्त न कर सका और उसे आयात का सहारा लेना पड़ा तो उसके लिए स्पष्टतः मौसम दोषी था।

लेकिन जब सोवियत संघ में सूखा पड़ता है तो हम देखते हैं कि पश्चिमी प्रचार साधन सोवियत समाज व्यवस्था या सामूहिक फार्म प्रणाली को दोषी ठहराते हैं।

सोवियत संघ में १६७१-७५ की अवधि में गल्ले की पैदावार औसतन लगभग १.५ टन प्रति हेक्टर पहुंच गयी; इनमें से सबसे अच्छे वर्षों में औसत पैदावार १.६ और १.७ टन रही। जहां तक अमरीका और पश्चिमी यूरोप के साथ कमोबेश तुलना करने लायक कृषि परिस्थितियों वाले इलाकों (जैसे उत्तर काकेशस, क्रीमिया, दक्षिणी उक्राइन और बल्टिक तट) का सवाल है, वहां अनाज की उपज बहुत पहले ही तीन टन प्रति हेक्टर से ऊपर पहुंच चुकी है जो कुछ पश्चिमी देशों की पैदावारों से थोड़ी-बहुत कम है लेकिन अमरीका से बढ़ कर है।

सोवियत संघ का लक्ष्य यह है कि कृषि को और भी सघन बनाने की नीति पर चल कर, इसके लिए अपार धनराशि का निवेश कर के, मशीनरी और उर्वरकों का उत्पादन और बढ़ा कर, तथा संसार का सबसे बृहत भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करके कृषि को प्रकृति की सनक से मुक्त कर दिया जाये।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एक अमरीकी किसान और एक सोवियत किसान जितने लोगों का "पेट भरता है", उनकी संख्या की तुलना कैसे होगी ?

अमरीका में २१.२ करोड़ आबादी के लिए ४० लाख किसान हैं और सोवियत संघ में २६ करोड़ आबादी के लिए २.४ करोड़ लोग कृषि में लगे हैं। अत: एक सोवियत किसान ग्यारह व्यक्तियों का पेट भरता है। एक अमरीकी किसान जितने लोगों का पेट भरता है, उसका यह लगभग एक-पांचवां है।

पश्चिमी समाचार-पत्र इस बात को अक्सर इसी रूप में पेश करते हैं। और जाहिरा तौर पर यह ऐसा ही प्रतीत भी होता है। लेकिन यह तुलना ठीक नहीं है, जैसा कि हम अभी देखेंगे।

उक्राइन के तेर्नोपोल प्रदेश के "पोबेदा" (विजय) सामूहिक फार्म के सदस्यों में १३६ विशेषज्ञताओं के १,५०० लोग शामिल हैं। उनमें फार्म की मरम्मत की दुकानों पर काम करने वाले मेकैनिकल इंजीनियर, सुरक्षा विशेषज्ञ, फिटर, टर्नर और मिलिंग–मशीन आपरेटर और ५०० मोटरों की सेवाई करने वाले बिजली मिस्त्री शामिल हैं। यही नहीं, इस संख्या में प्रबंधक, अर्थशास्त्री, मुनीम, फार्म की आहारशालाओं के रसोइए और खाना परसने वाली स्त्रियां, रात के पहरेदार, क्लीनर, ट्रक ड्राइवर, अंतरफार्म निर्माण संगठनों के कंक्रीट साज, राजगीर और बढ़ई; सामूहिक फार्मों के जंगलों की देखभाल करने वाले वनरक्षक; फार्म के रेडियो और टेलीफोन प्रणालियों की सेवाई करने वाले आपरेटर शामिल होते हैं। सोवियत आंकड़ों में उन सभी का उल्लेख किसानों के रूप में किया जाता है।

लेकिन अमरीकी आंकड़ों में ऐसे तमाम कर्मी प्रशासन, परिवहन, संचार, निर्माण, वन सेवा आदि को अलग-अलग कोटियों में रख दिये जाते हैं। अर्थात उन्हें किसानों में शामिल नहीं किया जाता।

हम अब तक के इस निर्विवाद तथ्य पर फसाद नहीं कर रहे हैं कि कृषि में श्रम उत्पादकता की दृष्टि से सोवियत संघ अमरीका से बहुत पीछे है। १९७१-७५ में दोनों देशों की औसत सालाना कृषि पैदावार के बीच अनुपात १००:८५ रहा। किंतु यह दावा करना कि अमरीका और सोवियत संघ में प्राप्त की जाने वाली पैदावार क्रमश: ४० और २४० लाख किसानों की मेहनत का फल है, स्थिति को बुरी तरह तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आप अपनी दसवीं पंचवर्षीय योजना को कार्यकुशलता और ऊंची क्वालिटी हासिल करने की योजना क्यों पुकारते हैं? क्या आपने ऐसे दायित्व पहले नहीं उठाये थे?

उठाये थे, लेकिन इतना जोर दे कर या इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं जैसा आज कर रहे हैं।

अनेक पश्चिमी विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि सोवियत अर्थतंत्र की कार्यकुशलता या दक्षता पूंजीवादी अर्थतंत्र की अपेक्षा कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। यह सच है कि सोवियत उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का पैमाना तथा कुछ उत्पादों की क्वालिटी अभी तक अत्यंत उद्योगीकृत पूंजीवादी देशों की तुलना में निम्न है लेकिन इसका कारण यह है कि इस देश के औद्योगिक विकास का आरंभिक स्तर अत्यंत प्रतिकूल था। इसके अलावा अन्य वस्तुगत कारण भी हैं जिनका अन्य उत्तरों में पहले ही जिक्र किया जा चुका है।

दूसरी ओर हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि सोवियत संघ में कायम विश्व के विशालतम बिजलीघरों में कार्य करने वाले नाभिकीय रिऐक्टरों, टर्बाइनों और जेनरेटरों के बराबर बृहत क्षमता और उन्नत प्रविधि के इन उपकरणों के समकक्ष और कोई देश नहीं पहुंच सका है। सोवियत ड्रिलिंग, धातुकर्म, झलाई और अन्य उपकरण संसार के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के समकक्ष हैं।

यह सब हमारे विस्तृत विकास के दौर में हासिल किये गये हैं—जब कि अर्थतंत्र का मुख्यतः विस्तार किया गया। उस समय विकास का वह पथ आवश्यक था तथा मुख्य, आगे का पथ माना जाता था। किन्तु उस समय भी हम जो कुछ बनाते थे, उसकी क्वालिटी पर हमने कम ध्यान न दिया। यहां यह लक्षित कर देना ही पर्याप्त होगा कि हमने अपने विस्तृत विकास के अंतिम चरण में ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कीं।

उसके बाद इस बात का यथासंभव अधिक से अधिक बारीकी के साथ फैसला करना जरूरी हो गया कि राष्ट्रीय अर्थतंत्र को कब विस्तृत या व्यापक से सघन या गहन विकास की ओर मोड़ा जाये। यह कार्य कर लिया गया है। यह किस बात का सूचक है?

इसका सर्वप्रथम तो यह अर्थ है कि जहां पूर्ववर्ती, नवें पंचवर्षीय योजना काल में अर्थतंत्र में पूंजी निवेश राष्ट्रीय आय से ५० प्रतिशत अधिक तेज गति से बढ़ा, वहीं वर्तमान पंचवर्षीय काल में पूंजी निवेश में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से कम रहेगी जो सोवियत अर्थतंत्र के इतिहास में व्यवहारतः पहली बार होगा। अर्थतंत्र कम पूंजी-प्रधान हो जायेगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. ......3283......

और जहां तक क्वालिटी का सवाल है, १९७६ के एक सवाल में उच्चतम क्वालिटी का माने जाने वाले औद्योगिक मालों का उत्पादन ३०-६० प्रतिशत बढ़ गया, और हम आशा करते हैं कि यह वृद्धि बाद के वर्षों में भी जारी रहेगी। फलतः १९८० तक संसार के उच्चतम स्तरों के मालों का परिमाण १९७५ की तुलना में कई गुने बढ़ चुका होगा।

जैसाकि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस ने निरूपित किया है, देश के आर्थिक विकास में कार्यकुशलता और ऊंची क्वालिटी के लिए मौजूदा अभियान का लक्ष्य है सोवियत नागरिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके जीवनमान को और भी तथा तेजी से ऊंचा करना।

क्या आप यह नहीं सोचते कि १९८० के ओलंपिक खेलकूद के लिए मास्को में इस समय जो निर्माण कार्य चल रहा है वह कुछ ज्यादा खर्चीला नहीं है?

नहीं। इसके दो कारण हैं।

एक तो मास्को में ओलंपिक १९८० के आयोजन के फैसले के पहले भी नगर के पास ऐसे खेल-कूद के लिए आवश्यक सारी सुविधाएं व्यवहारतः पहले से ही मौजूद थीं। मास्को में सोवियत संघ के खेल-कूद के फाइनल मैच (जो इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि उनकी तुलना ओलंपिक से की जा सकती है), विश्वविद्यालीय खेल, अनेक विश्व और यूरोपीय चैंपियनशिप तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। वहां की खेल-कूद सुविधाओं में से अनेक तो अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरी करती हैं और ओलंपिक में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें ६९ स्टेडियम, १,३०० से अधिक व्यायामशालाएं, २२ प्रतियोगिता के लिए आवश्यक आकार के तैराकी के जलाशय, दो इंडोर टेनिस कोर्ट, दो साइकल-चालन पथ और एक नौका-चालन की नहर।

दूसरे, इस समय हम मास्को में १९८० के ओलंपिक के लिए जो कुछ बना रहे हैं, वे खेल के बाद भी उपयोग में आ सकेंगे। उनका तो मास्को के मास्टर प्लान के तहत निर्माण किया जाना ही था, चाहे ओलंपिक न भी होता। मास्टर प्लान में यह तय कर रखा गया है कि खेल-कूद सुविधाओं के लिए प्रतिव्यक्ति इष्टतम ३.५ वर्ग मीटर निर्धारित होने चाहिए जो हमारे पास इस समय जितना क्षेत्रफल है उसके तीन-गुने से कुछ अधिक है। ऐसा भी नहीं है कि ओलंपिक के समाप्त हो जाने के बाद खेल-कूद सुविधाओं का निर्माण बंद हो जायेगा। इस कार्यक्रम से अतिरिक्त

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अनियंत्रित खर्च उतना नहीं करना पड़ रहा है जितनी विविध परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लानी पड़ रही है। लेकिन इससे नियोजित गृह निर्माण कार्यक्रम में कटौती कतई नहीं करनी पड़ रही है।

सोवियत संघ के मन्त्रिपरिषद के उपाध्यक्ष तथा सोवियत ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष इग्नाती नोविकोव का कहना है : "हमारा इरादा विराट खेल-कूद प्रतिष्ठानों के निर्माण में अपने पूर्ववर्तियों को पछाड़ने का नहीं है, बल्कि हम वही करना चाहते हैं जिसे हम कार्यसाधक महसूस करते हैं।"

ओलंपिक खेल १९८० के लिए क्या निर्मित किया जा रहा है ?

फ्लैटों की पांच ऊंची इमारतों का एक ओलंपिक गांव जो खेल के बाद १२० हेक्टर का एक नया रिहायशी जिला बन जायेगा। १०,००० बेड का एक बड़ा होटल। १,५०० चैनेलों वाला एक स्वचल अंतर्राष्ट्रीय टेलिफोन एक्सचेंज। एक स्वचालित खेलकूद प्रशासन और सूचना प्रणाली। एक बहु-उद्देश्यीय इंडोर खेल-स्थल। एक मंडप वाला स्टेडियम। एक घुड़सवारी के खेलों का स्थान।

ओलंपिक खेल हों या न हों, मास्कोवासी निःसंदेह इन तमाम सुविधाओं का स्वागत ही करेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

३. प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान

ऊर्जा संकट से आपका देश किस सीमा तक प्रभावित हुआ है ?

वह लेश मात्र प्रभावित नहीं हुआ है। सोवियत संघ के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं और वह कच्चे मालों और ईंधन के आयात पर निर्भर नहीं है।

जैसे देश का संपूर्ण अर्थतंत्र एक राष्ट्रीय योजना के अनुसार विकसित किया जाता है, ठीक उसी तरह ईंधन और ऊर्जा उद्योग भी विकसित किया जाता है। हमारी नियोजित आर्थिक प्रबंध की प्रणाली के कारण सुलभ संसाधनों के साथ आवश्यकताओं का तालमेल बैठा लिया जाता है, इस बात का यथासमय पता कर लिया जाता है कि कहां कमी हो सकती है, तथा संकट की स्थितियों को पैदा होने से रोक लिया जाता है।

ईंधन और ऊर्जा उद्योग अर्थतंत्र की एक आधारभूत और अपरिहार्य शाखा है। अतः उस पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है और उसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

सोवियत संघ में ईंधन और ऊर्जा के उत्पादन को नीचे की तालिका में दिखाया गया है :

	१९६५	१९७०	१९७५	१९८० (योजना)
तेल (करोड़ टन)	२४·३	३५·३	४९·१	६४·०
कोयला (करोड़ टन)	५७·८	६२·४	७०·१	८०·५
गैस (अरब घन मीटर)	१२८	१९८	२८९	४३५
बिजली (अरब किलोवाट घंटे)	५०७	७४१	१,०३९	१,३८०

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस देश में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिनकी दिलचस्पी कृत्रिम कठिनाइयां पैदा करने में हो ताकि तेल, कोयले और बिजली की कीमतें बढ़ाई जा सकें अथवा जिनकी दिलचस्पी स्वयं अपने उत्पादों के पक्ष में देश के ईंधन उद्योग का एकांगी विकास करने में हो, अथवा जो तेल जैसे किसी खास ईंधन की खपत कृत्रिम तरीके से बढ़ा कर मुनाफा कमाना चाहते हों।

सरकारी नियोजन और निर्णयों से सोवियत संघ के खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो जाता है। देश की भूमिगत संपदा की खोज ऐसी सांगोपांग योजना के तहत वैज्ञानिक आधार पर की जाती है जो बुनियादी अनुसंधान से लेकर परीक्षण ड्रिलिंग तक सभी चरणों को समेट लेती है। इन उद्देश्यों के लिए विशाल रकमें आवंटित की जाती हैं। तेल, कोयले और गैस के नये खोजे गये भंडारों की बदौलत सोवियत संघ इन ईंधनों के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर आ गया है।

बहरहाल, भूवैज्ञानिकों की सफलताएं महज पहले चरण की परिचायक हैं। खोजे गये भंडारों पर जो काम करना पड़ता है, उसमें अक्सर भीषण कठिनाइयां सामने आती हैं। साइबेरिया, सुदूर उत्तर और मध्य एशियाई रेगिस्तान के बिरल आबादी वाले दुर्गम इलाकों में बड़े-बड़े भूमिगत भंडार खोजे गये हैं। यहां के गंतव्य स्थल अक्सर हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। अतः उनके विकास और परिवहन दोनों के लिए श्रम और धन दोनों का अपार खर्च अपेक्षित होता है।

कोई भी भंडार, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अक्षय नहीं होता। अतः हम वर्तमान निष्कर्ष से ज्यादा तेज गति से नये संसाधन खोजने का प्रयास करते हैं। इसी कारण सोवियत संघ तेज गति से खोज और विकास का कार्य करता जा रहा है, हालांकि वह पहले ही अन्य देशों की तुलना में सबसे अनुकूल स्थिति हासिल कर चुका है।

अधिक ठंड वाले जाड़ों में अमरीका और अन्य देशों
के लोगों को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।
जनवरी और फरवरी १९७७ में तापमान में भारी
गिरावट आ जाने से चार हजार प्रतिष्ठानों ने काम
स्थगित कर दिया, तीस लाख लोगों को जबरी छुट्टी दे दी
गयी, तथा घरों और कार्यालयों में हवा का तापमान
आरामदेह स्तर से नीचे चला गया।
क्या आपको अपने देश में यही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं?

अधिक ठंड वाले जाड़े यहां भी बहुत बड़ी समस्या हैं, तथा हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की वजह से यह आशा की जा सकती है कि वे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अन्य

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा गंभीर समस्या हों। जब १६७७ के आरंभ में अमरीका में वायु का तापमान शून्य से १०-१५ डिग्री नीचे गिर गया, सोवियत संघ के कुछ भागों में तापमान शून्य से ४० डिग्री नीचे बना हुआ था। किंतु अमरीका में जो कुछ घटित हुआ, वह इस देश में नहीं हुआ। हमारे किसी प्रतिष्ठान ने काम बंद नहीं किया, किसी को जबरी छुट्टी नही दी गयी, हमारे घरों और कार्यालयों में वायु का तापमान गिरने नहीं दिया गया, तथा ईंधन और बिजली के भाव नही चढ़े।

मसलन, जिस समय मौसम खासतौर पर ठंडा था, मास्कोवासियों ने अपने घरों में दुगुनी गैस जलायी लेकिन उन्होंने चाहे जितनी गैस जलायी हो, वे प्रति व्यक्ति प्रति मास १६ कोपेक (२१ अमरीकी सेंट) की आम निश्चित दर पर भुगतान करते रहे। यही बात गर्म पानी (८६ अमरीकी सेंट प्रति व्यक्ति प्रति मास) और केन्द्रीय तापन (१ डालर १८ सेंट प्रति व्यक्ति प्रतिमास) के साथ भी लागू होती है। न तो बिजली की और न पेट्रोल की कीमतों में कोई परिवर्तन हुआ। कारण यह है कि ठंड वाले जाड़े के महीनों में इमारतों को गर्म रखने से संबंधित सारे अतिरिक्त खर्च सोवियत राज्य ने वहन किये।

जाड़े के लिए तैयारियां गरमियों में की जाती हैं। भूमिगत भंडारों में विशाल परिमाण में गैस पंप कर दी जाती है जिससे उसे साल के सबसे ठंडे महीनों में उपयोग में लाया जा सके। ब्वायलरों और तापन प्रणालियों के रखरखाव का कार्य शरद के आने से पहले पूरा कर लिया जाता है। परिवहन सुविधाएं तथा खासतौर पर हिम की सफाई की मशीनें जाड़े के लिए तैयार कर ली जाती हैं।

आपके नगरों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या किया जाता है ?

इस सिलसिले में जो उपाय किये जाते हैं, उन्हें मास्को का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है।

मास्को में ४,५०० छोटे ब्वायलर संयंत्र बंद कर दिये गये हैं और उनका स्थान कोयले की जगह गैस जलाने वाले तापन संयंत्रों ने ले लिया है। फलस्वरूप वायु प्रदूषण की गति कम हो गयी है। आज मास्को के व्यवहारतः सभी आवास और अन्य इमारतें गैस जलाने वाले तापन केन्द्रों से गर्मी प्राप्त करती हैं। सभी तापन संयंत्र गर्द और गैस को रोक लेने वाले यंत्रों से सुसज्जित हैं।

अनेक कारखानों को मास्को से बाहर पहुँचा दिया गया है और उनका स्थान

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस प्रकार चुना गया है कि वे एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। नये और आधुनिकीकृत मोटर मार्गों के तैयार किये जाने और नगर की सीमाओं के भीतर भारी लारियों के उपयोग के परिसीमित कर दिये जाने से निकास गैस से वायु का प्रदूषण ठोस रूप में कम हो गया है।

लेनिनग्राद, नोवोसिबिर्स्क और अन्य अनेक बड़े औद्योगिक केन्द्रों में इसी प्रकार के उपाय किये गये हैं। अन्य अपेक्षाकृत कम उद्योगीकृत स्थानों की अपेक्षा वहां वायु को साफ रखना कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता है। मसलन, मास्को में पिछले पांच वर्षों (१९७१-७५) में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कुल मोटे तौर पर ८५ लाख रूबल खर्च हुआ जिसमें वृक्षों और झाड़ियों की रोपाई और देखरेख, सड़कों के पुनर्निर्माण, कारखानों के नये ठिकानों पर स्थानांतरण आदि को शामिल नहीं किया गया है, जिन सभी पर उसका दस गुना खर्च आता है।

शहर में अच्छी वायु की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए प्रमुख महत्व का एक उपादान है पार्कों और उद्यानों के क्षेत्र का विस्तार। नगरों के चारों ओर विशाल पार्क और जंगलात की पट्टियां फैली हैं। उदाहरणार्थ, मास्को के चारों ओर १,७५,००० हेक्टर (४,४०,००० एकड़) की हरी पट्टी है।

हमारा देश पानी, मिट्टी और हवा में हानिकर द्रव्यों के मान्य संकेंद्रणों की कानूनी सीमाएं निर्धारित करने में प्रथम है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजनाओं में हर साल प्रकृति-परीक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी एक खंड होना है जिसमें पानी-जंगलात और हवा की रक्षा करने, मत्स्यधन का पुनरुत्पादन करने, और खनिज संपदा का परीक्षण करने के लिए उपाय निर्दिष्ट किये होते हैं।

सोवियत संघ में पर्यावरण रक्षा का संगठन कैसे किया जाता है?

चालू पंचवर्षीय योजना काल के अंतिम वर्ष १९८० तक देश का औद्योगिक उत्पादन एक-तिहाई से ज्यादा बढ़ चुका होगा। किंतु इससे पर्यावरण इसी अनुपात में प्रदूषित नहीं होगा।

खासतौर पर अनेक उद्योगीकृत देशों की परिवेशीय स्थिति के बिगड़ते जाने को दृष्टि में रखते हुए पूछा जा सकता है कि यह कैसे संभव है? यह समाजवादी परिस्थितियों में औद्योगिक विकास के अनुभव से संभव होता है और इसके लिए सुनिश्चित भौतिक और कानूनी गारंटियां हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस अनुभव में सबसे बढ़कर प्राकृतिक संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग सम्मिलित है। मसलन, प्रथम राजकीय योजना (रूस के विद्युतीकरण के लिए) में भी जल-प्रदूषण रोकने के लिए प्रावधान था। यह योजना बनायी गयी थी कि नये प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक परिष्कार बेसिनों दोनों के बेहतर उपयोग के लिए पूरे देश में "उद्योग को विकीर्ण किया जाय"।

तभी से पर्यावरण रक्षा के लिए बजट आवंटनों को प्रत्येक विशिष्ट उद्योग के लिए योजनाओं में सम्मिलित किया जाता है। फलतः राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता में इतनी ज्यादा वृद्धि के बावजूद देश ने सापेक्ष्य पर्यावरणीय संतुलन बरकरार रखा है।

भौतिक गारंटियां स्वयं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं। १९७६-८० की अवधि में पर्यावरण रक्षा के लिए ११ अरब रूबल की राशि प्रत्यक्षतः आवंटित की गयी है। अगर हम इसमें जल और वात से होने वाले कटाव को रोकने के लिए और वनरोपण आदि के लिए किये गये आवंटनों को तथा साथ ही ऐसे उद्देश्यों के लिए स्थानीय तौर पर आवंटित की जाने वाली रकमों को भी जोड़ दें तो कुल लगभग ५० अरब रूबल अथवा सोवियत संघ की राष्ट्रीय आय का २.७ प्रतिशत होती है।

योजना में औद्योगिक उद्यमों का स्थान तय करने तथा खनिज धातु, शहतीर और पानी आदि समस्त प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के बारे में एक सांगोपांग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है जिसका उदाहरण है साइबेरिया के उस्त इलिम क्षेत्रीय-औद्योगिक समुच्चय के उद्यम। निष्कर्षण तकनीकों में भी काफी परिवर्तन लाया जाना है। निकट भविष्य में ८० प्रतिशत खनिज लोहे, ७५ प्रतिशत अलौह खनिज धातुओं तथा ५० प्रतिशत से अधिक कोयले का उत्पादन खुले मुंह की खानों की विधि से किया जायेगा जिससे खनन में न्यूनतम क्षति हो।

इस सांगोपांग दृष्टिकोण से प्रत्येक खनिज का कुशल उपयोग होता है। मसलन, अनुमान लगाया गया है कि ग्यारह प्रधान अलौह खनिज धातुओं से और भी साठ तत्व प्राप्त हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए कजाखस्तान के उस्त कामेनोगोर्स्क सीसा और जस्ता संयंत्र में पहले ही शुरूआती कदम उठाये जा चुके हैं। वहां कच्चे मालों का उपयोग पहले ही ९३ प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है तथा अलौह धातुओं के उत्पादन में बहुत वृद्धि की जा चुकी है। बल्खाश खनन एवं धातुकर्म समुच्चय में उपयोगी धातुओं की निष्कर्षण दर लगभग १०० प्रतिशत है। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए अपनायी गयी प्राविधिक नीति का आधार है तथा इससे प्रदूषण के स्तरों में उल्लेखनीय कमी आ गयी है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कानूनी गारंटियों में हाल के वर्षों में पारित अनेक कानून और सरकारी आज्ञप्तियां सम्मिलित हैं। मसलन, भूमि के उपयोग तथा जल और खनिज संसाधनों के उपयोग, वनरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी कानून तथा कास्पियन, काला और बाल्टिक सागरों और अजोव सागर तथा वोल्गा और उराल नदियों और बैकाल झील के बेसिनों से संबंधित परिरक्षण के उपायों के बारे में विशेष सरकारी आज्ञप्तियां मौजूद हैं।

प्रकृति की रक्षा करने के अन्य उपायों में श्रम कानून के तहत ऐसी कानूनी बंदिशें शामिल हैं जिनमें ऐसे नये या पुनर्निर्मित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के चालू किये जाने की मनाही कर रखी गयी है जिनमें हानिकर कचरा द्रव्यों का पर्याप्त परिष्कार करने, उन्हें निष्प्रभाव करने और फैलने से रोक लेने की व्यवस्था न हो। वायु में फेंके जाने वाले ४८७ निस्रावों और १४५ तत्वों के लिए अत्यंत निम्न संकेंद्रण सीमाएं निर्धारित कर दी गयी हैं।

आपराधिक (फौजदारी) कानून और प्रशासनिक कानून पर्यावरण की रक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके प्रावधानों के तहत अंतस्थलीय जल का तेल और अन्य हानिकर उत्पादों से प्रदूषित करने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माना हो सकता है या उसे जेल भी हो सकती है।

किंतु इन तमाम उपायों के बावजूद आमतौर पर पर्यावरण पर उद्योग का ऐसा असर पड़ता है कि अलग-अलग देशों की सीमाओं के भीतर परिवेशीय नियमन अब पर्याप्त नहीं रह गया है। इसी कारण इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद (सीएमईए) द्वारा किया जा रहा कार्य ऐसे सहयोग का उदाहरण है। उसके ढांचे के भीतर पर्यावरण रक्षा से संबंधित प्रश्नों से निबटने वाली एक विशेष परिषद स्थापित की गयी है, तथा एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें लगभग १६० परिवेशीय समस्याओं पर वैज्ञानिक लोग सहयोग कर रहे हैं। साथ ही परिष्कार संयंत्रों और उपकरणों तथा इस क्षेत्र में आवश्यक अन्य यंत्रों का उत्पादन सहकारी आधार पर आरंभ कर दिया गया है।

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों के बीच चल रहा सहयोग अन्य देशों के सामने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मिल कर कार्य करने का उदाहरण पेश करता है। मसलन सोवियत संघ और कई बाल्टिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने बाल्टिक सागर के समुद्रीय पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक उपसंधि पर हस्ताक्षर किये हैं, तथा चेकोस्लोवाकिया और स्वेडन ने पर्यावरण की रक्षा करने के क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्राविधिक सहयोग के संबंध में एक समझौता किया है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या राजकीय योजना प्रणाली विज्ञान की प्रगति में, उसके स्वतंत्र विकास में दखलंदाजी नहीं करती ?

"यह स्वतंत्र सर्जनात्मक चिंतन में, उसके उस आंतरिक तर्क में दखलंदाजी है जो कि किसी 'सौंपे गये कार्य' की सीमाओं के भीतर बंद नहीं रहता।"

कुछ लोगों ने १९२७ में यह कहा था, जब सोवियत विज्ञान अकादेमी की आम बैठक ने अकादेमी के १८३६ के पुराने संविधान के स्थान पर क्रांति के बाद का प्रथम संविधान स्वीकृत किया था। नये संविधान ने अनुसंधान के क्षेत्र में नियोजन का सिद्धांत लागू किया। बहुतेरों को यह विचार ही अनर्गल लगता था। कि "ऊपर से कोई विनियम न हो" अथवा "सरकार अनुसंधान के मोर्चे पर कमान संभाले"। १९१७ की समाजवादी क्रांति के पहले वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के बजाय व्यक्तिगत रुझानों पर चलता था। शोधकर्ता एक-दूसरे से कटे हुए अलग-अलग कार्य करते थे तथा सरकार इस मामले में कोई रुचि न लेती थी कि वे क्या कर रहे हैं।

अप्रैल १९१८ में ही लेनिन के मार्गदर्शन में विज्ञान के व्यापक विकास के लिए तथा इस बात का अध्ययन करने के लिए एक योजना तैयार की गयी कि उद्योग, परिवहन और कृषि में बिजली कैसे पहुँचायी जाये, कच्चे मालों और ऊर्जा के बीच कैसे उत्तम से उत्तम संयोग स्थापित किया जाये तथा देश के औद्योगिक उद्यमों को सर्वाधिक युक्तिसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जाये।

पिछले साठ वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्षेत्र अभूतपूर्व हो गया है तथा उसने अर्थतंत्र में अपार योगदान किया है। देश के विकास की संपूर्ण योजनाओं से घनिष्ठ रूप में जुड़ी बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक और प्राविधिक समस्याएं ऐसे विशाल वैज्ञानिक निकायों के संयुक्त प्रयास से हल की जाती हैं जिनमें अनेक लाइनों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सोवियत संघ की विज्ञान अकादेमी, सोवियत मंत्रिपरिषद की विज्ञान एवं प्रविधि समिति तथा संघीय और स्वायत्त जनतंत्रों की तत्संबद्ध एजेंसियां वैज्ञानिक केंद्रों के एक विस्तृत ताने-बाने के कार्य में तालमेल कायम करती हैं।

तब भला नियोजन सिद्धांत का आशय क्या है ? निश्चय ही वैज्ञानिकों से किसी निश्चित तिथि तक किसी खास चीज की खोज करने को नहीं कहा जाता है। किया यह जाता है : अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं, मुख्य-मुख्य लाइनें पृथक कर ली जाती हैं तथा अलग-अलग अनुसंधान केंद्रों को काम सौंप दिया जाता है ताकि उनके प्रयासों में तालमेल रखा जा सके और उन्हें सबसे आशावर्धक लाइनों में ध्यान केन्द्रित करने में मदद दी जा सके। अकादेमी के लिए यह आवश्यक है कि यह

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुसार प्रवृत्तियों का विश्लेषण और पूर्वानुमान कर के तथा अपने कर्मियों और केंद्रों की अलग-अलग योजनाओं में तालमेल करके अनुसंधान की समष्टिगत रणनीति स्पष्ट करे।

विज्ञान के प्रति यह नियोजित दृष्टिकोण अपना औचित्य पूरी तरह सिद्ध कर चुका है। किंतु पूछा जा सकता है कि आज जब कि सोवियत संघ के अर्थतंत्र में लाखों वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं, शायद वह उतना जरूरी नहीं रह गया है? नहीं, उल्टे नियोजन तो अब और भी जरूरी है। अगर ये लाखों वैज्ञानिक बगैर तालमेल के मनमर्जी से काम करें तो अनुपातहीनता पैदा हो जायेगी, तथा अनुसंधान की कुछ लाइनें अन्य से बहुत आगे बढ़ जायेंगी तथा फिजूल की दुहरावट होगी।

अनुमान लगाया गया है कि बेहतर संगठन मात्र से विज्ञान अतिरिक्त निवेश के बगैर ही चार से पांच गुना अधिक कारगर हो जाता है। १९७६-८० की पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

साइबेरिया और सोवियत संघ के अन्य भागों में विशाल वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना क्यों आवश्यक हुई?

विज्ञान अकादेमी ने १९३१ में ही एक आम बैठक में स्थानीय सांगोपांग वैज्ञानिक आधारों की स्थापना का फैसला किया था जो संघीय जनतंत्रों और स्वायत्त जनतंत्रों के भावी अनुसंधान केंद्र बन जाने को थे। ऐसे आधार कजाखस्तान और ताजिकिस्तान में तथा कोला प्रायद्वीप के खिबिन पर्वत पर स्थापित किये गये। विज्ञान अकादेमी की शाखाएं ट्रांसकाकेशिया, उराल और सोवियत सुदूर पूर्व में भी कायम की गयीं। १९३६ में देश के विभिन्न भागों में अकादेमी की छह शाखाएं कायम हो चुकी थीं, और उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही गयी।

किंतु द्वितीय विश्व युद्ध से यह सिलसिला बिलकुल बंद तो हो गया लेकिन उसमें व्यवधान अवश्य उत्पन्न हो गया। युद्ध के बाद छठे दशक में सोवियत संघ के अपार प्राकृतिक संपदा वाले पूर्वी क्षेत्रों के विकास की शुरूआत की गयी। यह कार्य मात्र विज्ञान की मदद से किया जा सकता था। विकेंद्रीकरण विज्ञान की कुशलता बढ़ाने का एक तरीका है। १९५७ में सोवियत विज्ञान अकादेमी ने अपना साइबेरियाई प्रभाग कायम किया। १९६१ तक सोवियत संघ के सभी संघीय जनतंत्रों में विज्ञान अकादेमियां कायम हो गयीं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ की प्राकृतिक परिस्थितियों में व्यापक बहुरूपता होने के नाते हर क्षेत्र की आर्थिक विकास की स्वयं अपनी रणनीति होती है जिसका निर्धारण राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा होता है। दीर्घकालिक पूर्वानुमान भी क्षेत्रीय रणनीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और यह अधिकतर सोवियत विज्ञान अकादेमी के साइबेरियाई प्रभाग जैसे स्थानीय केंद्रों का विषय होता है।

संघीय जनतंत्रों और स्वायत्त जनतंत्रों के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और संगठन में तथा स्थानीय कर्मीदल के प्रशिक्षण में रूसी संघ के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

क्या सोवियत वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्र लाइन का अनुसरण करने को आजाद हैं?

यह वास्तव में संभावनाओं का सवाल अधिक है।

आज उत्पादक शक्तियों और विज्ञान का विकास एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां यह सर्वथा असंभव है कि लोमोनोसोव या एडिसन जैसे लोग पैदा हों और वे अकेले ही एक साथ भौतिकी, रसायन, विद्युत इंजीनियरी, अंतरिक्ष या नाभिकीय सिद्धांत के क्षेत्र में कार्य कर सकें। नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार के साथ व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर लेने वाले वैज्ञानिक के पीछे भी सैकड़ों नहीं तो दर्जनों सहकर्मियों, वैज्ञानिक दलों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों का हाथ अवश्य होता है। वह उनसे जुड़ा और उन पर निर्भर होता है। वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति की परिस्थितियों में ऐसे अलग-थलग वैज्ञानिक नहीं हो सकते जो अपने ही बूते और अपने ही खर्च पर प्रयोग करते हों। इस वजह से किसी भी वैज्ञानिक को, चाहे वह सोवियत हो, या अमरीकी या अन्य कोई, परम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

विचारों को सूत्रबद्ध करने के लिए हर वैज्ञानिक स्वतंत्र है। उनमें से सबसे अधिक संभावना वाले विचारों को दल, प्रयोगशाला या संस्थान में विचार-विमर्श के बाद चुन लिया जाता है। इस प्रकार पृथक विचारों के आधार पर सामूहिक योजनाएं तैयार की जाती हैं जो ज्ञान के क्षेत्र-विशेष में सभी वैज्ञानिक केंद्रों द्वारा दिये गये सुझावों का निचोड़ पेश करने वाले अनुसंधान के और भी वृहत्तर कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली जाती हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अंतरिक्ष अनुसंधान निःसंदेह बहुत ही खर्चीला मामला है। लेकिन प्रथम भू-उपग्रह के छोड़े जाने के बाद के पहले दशक में इन अंतरिक्ष अन्वेषण-यानों में प्रत्येक की लागत सैकड़ों गुनी कम हो गयी है। और जब अंतरिक्ष-पोतों का बारंबार उपयोग होने लगेगा तो किसी वस्तु को अंतरिक्षीय कक्षा में पहुँचाने की लागत और भी घट जायेगी। वह दिन अब दूर नहीं है।

अंतरिक्ष अनुसंधान न केवल प्रत्यक्ष अर्थ में पूरी तरह किफायती हो जायेगा, बल्कि उससे लाभ भी होगा। आज भी मौसम और संचार उपग्रहों से उन पर खर्च की गयी रकम वसूल हो जाती है जिसमें उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ने का खर्च भी शामिल है। उदाहरणार्थ, अनुमान है कि हमारी उपग्रह मौसम पूर्वानुमान सेवा से राष्ट्र को सालाना ५०-७० करोड़ रूबल की बचत होती है। अंतरिक्ष से लिये गये चित्रों की मदद से भूगर्भीय जल और खनिज संसाधनों के भंडारों का पता चला है।

अंतरिक्ष उपग्रहों की मदद से किये गये अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है मानचित्र तैयार करना और स्थल का सर्वेक्षण करना। दिन और रात की परिस्थितियों में २४ घंटे फोटोग्राफ लेकर एक उपग्रह पृथ्वी की समूची सतह को समेट सकता है। उतने ही समय में यह काम पूरा करने में कम से कम एक हजार विमान लगेंगे।

अंतरिक्ष प्रविधि से राष्ट्रीय अर्थतंत्र को समानतः लाभ की आशाएं हैं। मसलन, पृथ्वी से जुड़ी परिस्थितियों में काफी समय तक भारहीनता या गहन शून्यता को बरकरार रख सकना असंभव है। किंतु अंतरिक्ष की भारहीन और विरलीकृत परिस्थितियों में असाधारण तौर पर शुद्ध द्रव्यों का उत्पादन किया जा सकता है, अथवा पदार्थों की इस प्रकार ढलाई की जा सकती है जैसी पृथ्वी पर संभव नहीं। अति उच्च शक्ति वाले एकमणिभों (मोनोक्रिस्टलों) के विकास से इलेक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरी, संचार तथा लेसर और संगणक तकनीकों के क्षेत्र में सचमुच क्रांति की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष में शीघ्र ही अरबों रूबल मूल्य के सैकड़ों टन बहुमूल्य द्रव्यों का उत्पादन होने लगेगा।

अंतरिक्ष अनुसंधान के नतीजे चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रयोग में आ रहे हैं। अंतरिक्ष यान की सतह पर चोट करने वाले अनेकानेक उल्का कणों का पता रखने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता रहा है, वह एक ऐसी युक्ति का आधार बन गया है जो पेशीय कंपनों को दर्ज करके कुछ तंत्रिकीय रोगों का आरंभिक चरणों में ही निदान कर लेता है। कुछ राकेट प्रणालियों में इस्तेमाल किया जाने वाला पंप कृत्रिम हृदय के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कास्मोनाट जो चश्मे पहनते हैं, उसके कान वाले हिस्से में प्रयुक्त होने वाला स्विच, जो मात्र आंख की गति से चालू या बन्द कर दिया जाता है, अब लकवे के मरीजों की चल कुर्सी के संचालन में प्रयोग में लाया जाने लगा है।

इस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान में जो धन लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग ही हो रहा है।

क्या यह सही है कि जो सोवियत संघ विज्ञान और प्रविधि की कुछ शाखाओं में अग्रणी है, वही कम महत्वपूर्ण अन्य शाखाओं में पिछड़ा हुआ है ?

सोवियत संघ विज्ञान पर चाहे जितना भी खर्च क्यों न करता हो (१७ अरब रूबल से अधिक प्रति वर्ष), और अनुसंधान की दिशाएं चाहे जितनी भी विविधतापूर्ण क्यों न हों, वह आधारभूत और प्रयुक्त ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी होने का मुश्किल से ही दावा कर सकता है।

एक तो सुलभ कोष और विशेषज्ञों की संख्या वैज्ञानिक अनुसंधान के पूरे-के पूरे मोर्चे पर प्रगति की एक ही दर आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ विज्ञान पर अधिक खर्च किया जाता है। यह खर्च बढ़ता जायेगा, क्योंकि विज्ञान में किया गया निवेश किसी अन्य क्षेत्र में किये गये निवेश से ज्यादा प्रतिलाभ देता है।

सिद्धांततः सोवियत संघ, जिसके पास संसार में सर्वाधिक वैज्ञानिक और प्राविधिक शक्यता और एक शक्तिशाली अर्थतंत्र है, काफी व्यापक मोर्चे पर अनुसंधान का विकास करने में सक्षम है। फिर भी प्रगति की मुख्य दिशाओं के मामले में चुनाव करना ही पड़ता है। यह चुनाव किन बातों पर निर्भर है ?

एक तो अर्थतंत्र की आवश्यकताएं। दूसरे, समस्याओं का सामान्य महत्व—उनसे की जा सकने वाली आशाएं। और अंततः, देश के अग्रणी वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक रुचियां। व्यवहार में इसका अर्थ क्या हुआ ?

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए विज्ञान अकादेमी द्वारा तैयार की गयी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

योजना ५०० से अधिक आधारभूत समस्याओं को समाविष्ट करती है। अलबत्ता, वह इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती कि इनमें से किसी में पांच वर्षों में अंतिम क्या परिणाम हासिल किया जायेगा। योजना में केंद्रीय स्थान आणविक जैविकी, मानव काया के कार्य के शरीरक्रियात्मक और जीव-रासायनिक सिद्धांतों, प्राथमिक कणों की भौतिकी, परमाणु नाभिक और प्लाज्मा, क्वांटम इलेक्ट्रानिकी, रसायन और रसायन-इंजीनियरी, गणित और यांत्रिकी, तथा स्वचल नियंत्रण के क्षेत्रों में सांगोपांग अनुसंधान के दीर्घकालिक कार्यक्रमों को प्राप्त है।

अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य जारी रखा जायेगा जिसे कुछ लोग प्रतिष्ठा का कार्य मानते हैं। लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों का यह नज़रिया नहीं है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, संचार और अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्षयान के उपयोग का मूल्य स्वयंसिद्ध है। मसलन "साल्युत" अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा ली गयी अल्ताई पर्वत (दक्षिणी साइबेरिया) की तस्वीरों से उस क्षेत्र की खंड-संरचना का पता चला जो इससे पहले भूवैज्ञानिक मानचित्रों में नहीं दिखाया जाता था। नये साक्ष्य से उस इलाके में खनिज भंडारों के मिलने की संभावना का अनुमान लगाना सुगम हो गया है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है गोकि अंतरिक्ष-भूविज्ञान अभी अपने शैशव में है।

हम कामा मोटर वर्क्स जैसे विशाल प्रतिष्ठानों, ६४ लाख किलोवाट क्षमता के सायानो-शुशेंस्काया जैसे बिजलीघरों, या ५,००० घन मीटर क्षमता के क्रिवोय रॉग की धमन भट्ठी जैसे धमन भट्ठियों का डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने का कार्य किसी प्रकार की प्रतिष्ठा के विचार से नहीं करते। सोवियत अर्थतंत्र के पैमाने और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण वे आर्थिक दृष्टि से जरूरी हो जाते हैं।

सोवियत संघ प्राकृतिक संसाधनों से अच्छी तरह संपन्न है। फिर भी ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज में काफ़ी धन और श्रम लगाया जाता है। हम ताप-न्यूट्रन और द्रुत-न्यूट्रन बिजलीघरों के निर्माण में सर्वप्रथम थे। नियंत्रित नाभिकीय विलयन में पारंगत होने में सोवियत विज्ञान द्वारा प्राप्त की गयी सफलताएं सुविदित हैं। मानव जाति के सामने ऊर्जा की कमी का जो खतरा पेश है, उसे टालना है तो इस समस्या के समाधान पर बहुत कुछ निर्भर है।

कहा जाता है कि बहुत-सी महत्वपूर्ण खोजें विभिन्न विज्ञानों के चौराहों पर पड़ती हैं। इसी के साथ यह कहा जा सकता है कि वे अनुसंधान में क्षेत्र के व्यापकतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की लाइनों पर भी पड़ती हैं। अनुसंधान की किसी लाइन-विशेष में सोवियत संघ आगे हो या न हो, वह व्यापकतम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तत्पर है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में अत्यधिक आसानी होगी।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

४. जीवन स्तर

जीवन स्तरों की बात करते समय अमरीका और सोवियत संघ में भिन्न-भिन्न कसौटियां प्रयोग में लायी जाती हैं। उनमें तुलना कैसे की जा सकती है ?

यह सच है कि दोनों अपने नागरिकों के जीवन स्तर का वर्णन करने के लिए भिन्न-भिन्न कसौटियों का इस्तेमाल करते हैं। अमरीका में रहन-सहन के स्तर की माप मोटरकारों की संख्या और कीमत से लगायी जा सकती है, जबकि इस देश में हम आबादी को मुहैया की गयी निःशुल्क सेवाओं के मूल्य का हवाला देते हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि किसी के भी जीवन में बहुतेरी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिनमें मोटरकार जैसी स्पृहणीय चीजें भी शामिल हैं। और इस मायने में अमरीका अभी भी बहुत आगे है।

किंतु हमारा विश्वास है कि जीवनमान के अन्तर्गत भौतिक सामग्रियों की अपेक्षा कहीं व्यापक क्षेत्र आ जाता है। आखिरकार भरपूर जिंदगी, तृप्ति और सुरक्षा का सुखोपभोग करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का भी होना जरूरी है जो कहीं ज्यादा जरूरी हैं—अच्छी सेहत, शिक्षा, अपनी पसंद का गारंटीशुदा रोजगार, तथा बुढ़ापे में भौतिक सुरक्षा। सोवियत नागरिक मनुष्य की खुशहाली के इन बुनियादी घटकों को एक व्यावहारिक हकीकत के रूप में उपभोग करते हैं।

जीवनमान और जीवन के गुण से संबंधित हमारे तर्क का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है।

जब एक परिवार में सभी स्वस्थ होते हैं, उसकी खुशहाली पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की दशा, अस्पताल में रहने के खर्च, दवाओं की कीमतों आदि का कोई

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

असर नहीं पड़ता। किंतु दुर्भाग्य से हम सदा स्वस्थ नहीं होते। अतः स्वास्थ्य सेवा के संगठन से संबंधित किसी चीज से कोई उदासीन नहीं रह सकता।

सोवियत नागरिक जानता है कि उसकी बीमारी का उसके कुटुंब की खुशहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसे निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी, राज्य पर चाहे जितना खर्च आये। उसे न तो अस्पताल में ठहरने पर एक भी कोपेक खर्च करना पड़ता है और न विशिष्टतम विशेषज्ञ से परामर्श के लिए। बीमारी के दौरान उसे अपने रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जायेगा। (इसकी कानूनन मनाही है) तथा उसे किसी बीमा योजना या अन्य योजना का सदस्य बने बगैर एक अधिकार के रूप में बीमारी का वेतन मिलेगा।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम यह मानते हैं कि माध्यमिक स्कूल से लेकर मास्को विश्वविद्यालय तक कतई कहीं भी अध्ययन करने का अवसर परिवार की आय पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तथा शिक्षा संस्थाओं को केवल चंद लोगों की पहुंच में होने वाली विशिष्ट लोगों की विशेषाधिकार संपन्न और सभी की पहुँच में होने वाली अन्य संस्थाओं में विभाजित नहीं होना चाहिए। हमारे यहां हर प्रकार की शिक्षा के लिए निःशुल्क अध्यापन की गारंटी है।

अब आइए, हम परिवार की आमदनी पर नजर डालें और देखें कि वह खर्च कैसे की जाती है।

अमरीका में एक औसत परिवार अपनी आवश्यकता की चीजों पर अपनी आमदनी का केवल ४० प्रतिशत खर्च कर सकता है और शेष ६० प्रतिशत करों, सामाजिक बीमे के भुगतानों, डाक्टर की फीस, ट्यूशन, भाड़े आदि जैसे मदों पर खर्च करना पड़ता है।

सोवियत संघ में एक औसत परिवार अपनी आय का ८० प्रतिशत अपनी मर्जी से खर्च करने को आजाद है।

"जीवनमान" या "रहन-सहन के स्तर" की अवधारणा एक संश्लिष्ट अवधारणा है जिसमें वर्तमान को ही नहीं, अतीत और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आय, मूल्य और दरों में संभावित उतार-चढ़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में निरापद महसूस कर सकता है, अथवा क्या "दुर्दिन" के लिए कमर कस कर तैयार रहना जरूरी है ? दूसरे शब्दों में, भविष्य में क्या छिपा है ?

हमारे देश में जीवन स्तर की वक्ररेखा निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। फुटकर भावों, भाड़ों और अन्य देनदारियों के स्थिर रहन के साथ-साथ निजी आय पिछले १५ वर्षों में दुगुनी हो गयी है और बढ़ती ही जा रही है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

स्मरणीय है कि पश्चिमी देशों का आंकड़ों से प्राप्त औसत परिवार अक्सर एक ऐसी अमूर्त चीज होता है जो यथार्थ जीवन में नहीं पाया जाता। भला एक करोड़-पति और एक ऐसे बेरोजगार मजदूर के बीच जिसका बेरोजगारी का भत्ता बंद हो गया हो, तैराकी के तालाब से सज्जित खर्चीले बंगले के एक मालिक और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जिसके पास कोई मकान ही न हो, औसत कैसे निकाला जा सकता है? आंकड़ों की गणना में दोनों ही योग देते हैं जिसमें जीवनमान की घोर विषमताएं छिपी होती हैं।

समाज के पास अपने विकास के किसी भी विशेष चरण में भौतिक मालों की एक खास कुल राशि सुलभ होती है। आज अमरीका के पास यह राशि सोवियत संघ से ज्यादा है। यह विषमता ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुई है और इसे समाजवाद की "खामियों" के माथे नहीं मढ़ा जा सकता। उल्टे, समाजवाद इस खाई को लगातार और तेजी के साथ पाटता जा रहा है तथा साथ ही अपने पास सुलभ संपदा को अपने नागरिकों के बीच न्यायानुसार वितरित किया जाता है।

क्या हमने जो स्तर हासिल कर लिया है, उससे हम संतुष्ट हैं? नहीं, वह शुरूआत भर है। हमार लक्ष्य है और अधिक भौतिक माल का उत्पादन करना, और हम कारें भी अधिकाधिक तैयार करेंगे। हमारी आबादी ने १९६५ में ६४,००० कारें खरीदीं तथा १९७५ में लगभग दस लाख कारें खरीदीं। हम मोटर परिवहन विकसित करते जायेंगे, लेकिन इस प्रकार नहीं कि सार्वजनिक परिवहन या पर्यावरण को क्षति पहुंचे, ऊर्जा संकट में फंस जाने का खतरा पैदा हो जाये और वाकई हम कार को अपने जीवन स्तर का पैमाना नहीं बनाने जा रहे हैं।

क्या सोवियत अर्थतंत्र मुद्रास्फीति के बगैर विकसित हो सकता है?

वह विकसित ही इसी प्रकार होता है। बजट में घाटा पैदा कर देने वाले, हम पर थोपे गये युद्धों से ही मुद्रास्फीति पैदा हुई थी। सोवियत काल के आरंभ में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अल्प अवधियों के अलावा हमारे यहां न तो आय से राज्य का खर्च कभी ज्यादा हुआ और न कभी मुद्रास्फीति हुई।

कुल मिलाकर मूल्य सूचकांक आज २५ साल पहले का चौथाई है और लगभग वही है जो १९७० में था।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें स्थिर कैसे रखी जाती हैं ?

सोवियत संघ में १९७६ में ९९ प्रतिशत खाद्य वस्तुएं और ९२ प्रतिशत खाद्य के अलावा अन्य वस्तुएं १९७० की ही कीमतों पर बिकीं।

यह मूल्यों के केंद्रीकृत नियोजन द्वारा ही संभव है। उद्योग में प्रयोग में लायी जाने वाली नियोजन प्रणाली और प्रेरणा प्रणाली इस प्रकार की हैं कि कोई भी कारखाना अपना लाभ अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर नहीं बल्कि उत्पादन लागत घटाकर प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, कीमतें इसलिए नहीं बढ़ती हैं कि सोवियत राष्ट्रीय अर्थतंत्र में ऐसी कोई युक्ति है ही नहीं जो उन्हें स्फीत करने या बढ़ाने में मदद करे। ऐसी केन्द्रीयकृत नियोजन प्रणाली के न होने पर और किसी साधन से, मूल्य नियंत्रण की पूर्ण से पूर्ण विधियों से भी कोई लाभ नहीं होगा।

सोवियत संघ में राज्य मूल्य समिति और उसकी एजेंसियां मूल्य निर्धारित करती हैं। यह समिति उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक प्रकार के एजेंट या माध्यम का कार्य करती है। अगर कारखानों को स्वतः कीमतें तय करनी हों तो उसका नतीजा मुद्रास्फीति को जन्म देने वाली अराजकता होगी। यह समिति बिजली और तापन प्रणाली, परिवहन और सेवाओं के लिए अदा की जाने वाली थोक, फुटकर, राज्य द्वारा खरीद की और अन्य कीमतों और दरों को मंजूरी देती है। साथ ही वह अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ कीमतों, दरों, अतिरिक्त प्रभारों और कटौतियों में लगातार संशोधन करती रहती है। समिति कीमतों में ऐसे परिवर्तन सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद की मंजूरी पाने के बाद लागू करती है जिनसे बजट में घाटा होता हो।

सोवियत संघ में विभिन्न वस्तुओं का मूल्य स्तर वहन अंशों में उनके सामाजिक महत्व पर निर्भर होता है। मसलन, मांस और मांस के उत्पाद, दूध और डेरी उत्पाद और अनेक प्रकार की मछलियां और उनके उत्पाद, बच्चों के वस्त्र और जूते, स्कूलों और कालेजों की पाठ्य पुस्तकें, खिलौने, कापियाँ और लिखने की अन्य सामग्रियां, दवाऐं, सूती कपड़े, तथा अन्य अनेक वस्तुएं स्थिर कीमतों पर बेची जाती हैं जो उनकी वास्तविक लागत से कम होती हैं। इस क्षेत्र में राज्य द्वारा अदा की जाने वाली सहायता राशि अरबों रूबल पहुंच जाती है। राज्य जवाहरात और आभूषणों, प्राकृतिक समूरों (फर) और विलासिता की अन्य सामग्रियों तथा मादक पेयों के लिए ऊंचे मूल्य निर्धारित करके अपनी कुछ हानि की पूर्ति करता हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किंतु, सहायता राशि का मुख्य स्रोत राज्य के उद्यमों द्वारा अर्जित किया जाने वाला लाभ होता है। इस प्रकार राज्य उपभोक्ता के पक्ष में उठायी गयी हानि की प्रतिपूर्ति करता है।

पूंजीवादी देश में अगर आपके पास धन है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोवियत संघ में ऐसा क्यों नहीं है ?

आप वही चीज खरीद सकते हैं जो बिक्री के लिए हो। जैसाकि हम पहले ही कह चुके हैं सोवियत संघ में हर चीज (जैसे भूमि और उत्पादन के साधन) बिक्री के लिए नहीं होती। हमारी ये बंदिशें समाजवादी व्यवस्था के विशिष्ट पहलुओं और समाजवादी जीवन पद्धति की देन हैं।

कुछ अन्य, अस्थायी, बंदिशें ऐसी हैं ज़ो बाजार में कुछ वस्तुओं की कमी होने से लगायी गयी हैं। चूंकि सोवियत संघ को अपनी यात्रा का समारंभ ऐसी परिस्थितियों में करना पड़ा जिनमें बुनियादी जरूरत की चीजें भी पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए उसके लिए एकाएक प्रचुरता प्राप्त कर लेना संभव न था। ब्रेड, मकान, स्कूल और अस्पताल समूर के कोट और हीरे-जवाहरात से ज्यादा जरूरी थे। जैसे-जैसे सार्वजनिक संपदा बढ़ती गयी, बहुत-सी विलासिता की वस्तुएं विलास की चीजें न रहकर उपभोक्ता वस्तुऐं बनती गयीं जैसे रेडियो और टेलिविज़न सेट, कपड़ा धुलाई की मशीन, रेफ्रिजरेटर, कारें, फैशनेबुल कपड़े आमोद नौकाएं आदि-आदि। यह क्रम जारी है, और हालांकि चाहे आपके पास धन हो या न हो, सोवियत संघ में कुछ चीजें अभी भी दुर्लभ हैं, इसका कारण यह नहीं है कि वे बिकती नहीं हैं बल्कि मांग की पूर्ति करने के लिए वे पर्याप्त नहीं हैं (जैसे प्राकृतिक समूर)।

सोवियत नागरिक कितना भाड़ा देते हैं ?

सोवियत नागरिकों का अधिकांश हिस्सा राज्य द्वारा मुहैया किये गये फ्लैटों और मकानों में रहता है। उनका भाड़ा, जिसमें बिजली, गैस, केन्द्रीय तापन (मकान को गर्म रखने के लिए गरमाहट की केन्द्रीय व्यवस्था) और पानी के लिए लगने वाला प्रभार भी शामिल है, औसतन परिवार के बजट के ४-५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

१९२८ के बाद से आधी सदी से इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि आवास में बहुत सुधार किया गया है। सौ में ८७ फ्लैटों में पानी के नल हैं, ८० में केंद्रीय तापन है, ८६ में फ्लश शौचालय हैं, ७४ में स्नानगृह हैं तथा ८८ के रसोईघरों में गैस की व्यवस्था है। ऐसे देश बहुत कम ही हैं जहां मकानों का इतना बड़ा प्रतिशत सभी आधुनिक सुविधा-साधनों से सज्जित हो। सालाना लगभग ५० लाख मकानों को गैस से सज्जित किया जाता है और यह दर मकानों के निर्माण की दर की दुगुनी है।

सोवियत संघ में आवास-निर्माण वाणिज्यिक कार्य न होकर शिक्षा और स्वास्थ्य की ही भांति सामाजिक सेवा है।

सोवियत संघ में लगभग सात प्रतिशत गृह-निर्माण सहकारी गृह-निर्माण के अंतर्गत आता है और उनमें मकानों के लिए भुगतान का तरीका थोड़ा-बहुत भिन्न है। उनके लिए जमीन मुफ्त मिलती है तथा राजकीय भवन-निर्माण संगठन बैंक ऋण से सहकारी आवास प्रखंडों का निर्माण करते हैं।

सहकारी आवास-निर्माण की लागत की पूर्ति उसी प्रकार होती है जैसे सरकारी गृह-निर्माण की। आवास-निर्माण सहकार के सदस्य कुल लागत का ३०-४० प्रतिशत नकद भुगतान करते हैं। शेष की पूर्ति ऋण से की जाती है जिस पर एक प्रतिशत सालाना का ब्याज लगता है और जिसे १०-२० वर्षों में चुकता करना होता है।

निजी मकान भी बनाये जाते हैं जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। कुल ग्रामीण गृह-निर्माण में वे लगभग आठ प्रतिशत होते हैं। भावी मकान मालिक लागत की ३० प्रतिशत रकम जमा करता है (अक्सर वह जिस सामूहिक फार्म में काम करता है उससे उसे इसके लिए मदद मिल जाती है)। शेष की पूर्ति स्टेट बैंक के ऋण से होती है जो ०.५ प्रतिशत ब्याज पर १०-२० साल में देय होता है। अक्सर राज्य ही कुल निर्माण लागत के एक-तिहाई से अधिक का भुगतान करता है। मकान मालिक को कोई स्थायी देय प्रभार अदा नहीं करना पड़ता लेकिन मकान का रख-रखाव उसे अपने खर्च पर करना पड़ता है।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर राज्य का बहुत-सा धन खर्च होता है जिसका इस्तेमाल मजदूरी और वेतन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिससे जनता इनका भुगतान खुद करे। आप ऐसा क्यों नहीं करते ?

क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में इन सामाजिक सेवाओं के लिए भुगतान करना

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पड़ता है जबकि कौटुंबिक आयों में अन्तर है (और कार्य की मात्रा और गुण के अनुसार उसके लिए पारिश्रमिक के समाजवादी सिद्धांत के तहत उनमें अंतर है) तो वे सभी नागरिकों की पहुंच में समान रूप से नहीं होंगे, और फिर इससे आर्थिक असमानता और भी उजागर रूप ले लेगी। बड़ी आय वाले लोग शिक्षा और चिकित्सा सहायता के मामले में छोटी आय वालों से ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे।

हमारा लक्ष्य है पूर्ण सामाजिक समानता। इसीलिए चिकित्सा सेवा, हर स्तर की शिक्षा, मकान (सहकारी फ्लैटों के अलावा) आदि को जानबूझ कर आय से स्वतंत्र कर दिया गया है। मुफ्त होने से वे सभी की पहुंच में समान रूप से हैं।

क्या सोवियत समाज "उपभोक्ता समाज" बनता जा रहा है ?

हमारी दृष्टि में यह प्रश्न अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के साधन के रूप में उपभोग का जिक्र नहीं करता बल्कि उपभोग को स्वयं में एक साध्य मान कर, उपभोग्य वस्तुओं की उपासना के रूप में उसका जिक्र करता है।

समाजवादी समाज में ऐसे परिवर्तन के लिए कोई वस्तुगत आधार नहीं है। उपभोक्ता मनोवृत्ति इस समाज के लिए तत्वतः परकीय है, क्योंकि यहां वस्तुओं का नहीं, मनुष्य और उसके कार्य का गुणगान होता है, तथा यह समाज व्यक्ति के समरस विकास का प्रयास करता है। सोवियत जनता परिवार में और स्कूल में बाल्यकाल से ही शुरू करके लगातार इसी प्रकार का लालन-पालन पाती है तथा साहित्य, जन-संचार साधनों और उन जन-संगठनों से जिनमें वह भाग लेती है, उस पर इसी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं।

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे यहां ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव नहीं है जिन पर "उपभोक्ता" वस्तुओं की धुन न सवार हो। कारण यह है कि कुछ नागरिकों के मानसिक क्षितिजों की अपेक्षा आय में ज्यादा तेज गति से वृद्धि होती है (हम बता चुके हैं कि सोवियत संघ में वास्तविक आय हर पंद्रह वर्ष में दुगुनी हो जाती है)। सर्वतोमुखी विकास के, लोगों की दृष्टि को व्यापक बनने और सामाजिक क्रियाकलाप में अधिक पुरजोर तरीके से सहभागी बनने के अवसरों में वृद्धि उन्हें इस्तेमाल में लाने की कुछ लोगों की आकांक्षा

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होती है। यह अनुपातहीनता भिन्न-भिन्न तरीकों से अभिव्यक्त होती है जिनमें एक है—और सब कुछ छोड़ कर वस्तुओं का क्रय करने की उत्कंठा।

पश्चिम की स्थिति के प्रतिकूल सोवियत संघ में जब वस्तुओं के प्रति यह धुन पैदा होती है तो वह समाज की देन तथा उसके विकास की तर्कसिद्ध परिणति नहीं होती। इसीलिए इस देश में यह कहीं कम आम होती है और सामान्यतः उसकी निंदा की जाती है।

क्या आपके देश में कोई फैशनेबुल विश्राम-केंद्र है, और अगर है तो उसका इस्तेमाल कौन करता है?

हमारे सबसे लोकप्रिय विश्रामकेंद्र—आरोग्य केंद्र और अवकाश केंद्र—काला सागर और बाल्टिक सागर के तट पर, काकेशस, मध्य एशिया और दक्षिणी उक्राइन में हैं जहां सालाना लगभग पांच करोड़ लोग पहुंचते हैं अथवा एक-पांचवीं आबादी विश्राम करने जाती है। इन स्थलों को जाने वाले लोग अपनी ट्रेड यूनियनों अथवा स्वास्थ्य संगठनों से वाउचर प्राप्त करते हैं जिसके जरिये उन्हें टिकने और आहारादि की सुविधा प्राप्त होती है।

ज्यादातर उन्हें वास्तविक खर्च का केवल ३० प्रतिशत चुकता करना पड़ता है और शेष की अदायगी यूनियनें सामाजिक बीमा कोष से करती हैं। इस प्रकार की सहायता के साथ किसी अवकाशगृह में दो सप्ताह के प्रवास पर औसतन मासिक वेतन का पांच प्रतिशत खर्च आता है जो वस्तुतः बहुत सस्ता है।

अवकाशगृहों को लाभ कमाने के लिए वाणिज्यिक धंधा नहीं बल्कि एक सामाजिक सेवा माना जाता है।

पुस्तकें, थियेटर, संग्रहालय आदि साधारण सोवियत जनता को किस हद तक सुलभ है?

संग्रहालयों में जाने वालों की सालाना संख्या आधी आबादी के लगभग

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पहुंच जाती है, तथा थियेटरों, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों में कुल आबादी से ज्यादा हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि टेलिविजन के प्रसार से (१९७५ में प्रति १०० परिवार ७४ टेलिविजन सेट थे) थियेटर, संगीत कार्यक्रमों, सिनेमा और संग्रहालय में रुचि कम नहीं हो सकी है।

चेल्याबिंस्क प्रदेश (उराल) के मजदूरों के बीच किये गये एक सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि १०० में से ९५ मजदूर सिनेमा जाते हैं, दो-तिहाई नाटक और संगीत कार्यक्रमों में जाते हैं तथा लगभग सभी पुस्तकें पढ़ते हैं।

स्वेर्द् लोव्स्क और निझ्नी तागिल (ये भी उराल में ही हैं) के ६० प्रतिशत मजदूरों के पास स्वयं अपने घरेलू पुस्तकालय हैं। सोवियत संघ के अन्य भागों में भी तस्वीर ऐसी ही है।

सोवियत नागरिक संसार में और किसी से ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं (यूनेस्को के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है), और औसत कुटुंब इसके अलावा चार पत्रिकाएं खरीदता है। वे सिनेमा भी दुनिया में और किसी से ज्यादा जाते है।

औसत सोवियत नागरिक साल में १८ बार सिनेमा जाता है, जो अमरीका की तत्संबंधी संख्या का तीन गुना, ब्रिटेन और फ्रांस का छह गुना तथा पश्चिम जर्मनी का नौ गुना है।

इसके दुहरे कारण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सांस्कृतिक सुविधाएं सोवियत नागरिकों की व्यापक पहुंच में हैं। पहला कारण आर्थिक है। पुस्तकें, पत्रिकाएं, थियेटर और सिनेमा टिकट आदि पश्चिम से कहीं ज्यादा सस्ते हैं। सिनेमा के एक टिकट की कीमत अधिक से अधिक ७० कोपेक (९३ अमरीकी सेंट) होती है। बोल्शोई थियेटर का एक टिकट अधिक से अधिक ३.५ रूबल (४.७ अमरीकी डालर) का होता है। जाहिर है, टिकटों के मूल्य इतना कम होने से उनसे न तो थियेटरों का खर्च पूरा हो सकता है और न संग्रहालयों का। राज्य उन्हें सहायता देता है।

दूसरा कारण यह है कि समाजवादी समाज में आबादी के सांस्कृतिक विकास को शिक्षा की दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से, हर प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या सोवियत संघ में कोई "हानिकर" दवा तैयार की जाती है? दवाओं और अन्य ऐसी चीजों के स्तर का नियंत्रण कैसे किया जाता है?

इस देश में कभी ऐसी नौबत नहीं आयी कि किसी दवा या ऐसी अन्य चीज का निर्माण मरीज की तंदुरुस्ती पर हानिकर असर का पता चलने के कारण बंद करना पड़ा हो।

दवाओं के निर्माण और उपभोग पर हमने बहुत ही सख्त नियंत्रण कर रखा है, तथा विदेशों में बनी अच्छी साख वाली दवाओं और ऐसी अन्य चीजों की भी पहले हम प्रयोगशाला में भरपूर जांच करते हैं।

सोवियत संघ में दवाओं और ऐसी अन्य चीजों का परीक्षण राजकीय संगठन करते हैं जो उन्हें तैयार करने वाले स्थानों पर अपनी वित्त-व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार निर्भर नहीं होते, तथा उनके उपयोग में जाने के पहले यह आवश्यक है कि सोवियत संघ का स्वास्थ्य मंत्रालय विशेष तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दे। अंतिम मंजूरी नयी औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के प्रवर्तन संबंधी विभाग की भैषज्य समिति देती है। अनुसंधान संस्थाएं दर्जनों दवाएं निकालती हैं लेकिन जब तक यह समिति मंजूरी न दे, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, तब तक एक भी दवा का उत्पादन आरंभ नहीं किया जा सकता।

उदाहरण के लिए हम फ्तोराफ़ुर की बानगी पेश कर सकते हैं। यह एक कैंसर-निरोधक दवा है और इसे लात्वियाई विज्ञान अकादेमी के जैव संश्लेषण संस्थान ने १९६५ में विकसित किया था। शरीरविदों, जीव-रसायनविदों अर्बुद वैज्ञानिकों और भैषज्यविदों के सहयोग से संस्थान के कर्मियों ने पहले तो कोशा-संवर्धनों पर और फिर पशुओं पर उसके गुणों और अतिरिक्त परिणामों का दो वर्षों तक विश्लेषण किया। जो भी आंकड़े प्राप्त हुए वे सभी भैषज्य समिति को सुपुर्द किये गये। जब हमने उस दवा को मंजूरी दे दी, उसके बाद सोवियत आयुर्विज्ञान अकादेमी के प्रायोगिक और नैदानिक अर्बुदविज्ञान संस्थान के कर्मियों ने यह तय किया कि इस दवा का किन विशिष्ट विधियों से और किन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए।

मरीजों के एक सीमित नियंत्रित समूह को इस दवा से चिकित्सा करने पर जो नतीजे प्राप्त हुए उन्हें पुनः भैषज्य समिति के सामने रखा गया, जिसने इसकी पात्रता का और मानव शरीर पर इसके प्रभावों का फिर से जायजा लिया और

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फिर यह सिफारिश की कि उसे औषधियों और विनिर्मित पदार्थों की राजकीय पंजी में सम्मिलित किया जाय।

इस पंजी में अभी तक २,५०० दवाएं और विनिर्मित पदार्थ दर्ज हैं। तुलना के लिए उल्लेखनीय है कि स्पेन, ब्राजील और फ्रांस में हजारों विदेशी दवाओं के अलावा क्रमशः २५,०००, १४,००० और ११,००० स्थानीय दवाएं चलती हैं। हम इसे पिछड़ेपन का संकेत नहीं बल्कि यह मानते हैं कि नयी दवाओं और विनिर्मित पदार्थों के प्रति हमारा रुख अधिक कड़ा है। उन्हें प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास जो केंद्रीकृत प्रणाली है, वह रोगियों के हित में है। यह उस स्थिति से उनकी रक्षा करने के लिए है जिसका जिक्र एक अग्रणी फ्रेंच भैषज्यविद प्रादाल ने किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे देश में हर तीन दवाओं और विनिर्मित पदार्थों में से दो बेकार होते हैं तथा कुछ तो सीधे हानिकर ही होते हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

५. समाज
और नागरिक अधिकार

सोवियत संघ में कौन-से वर्ग हैं ?
क्या उनके बीच कोई अंतर्विरोध हैं ?

सोवियत समाज मजदूर वर्ग, सामूहिक किसानों और बुद्धिजीवियों से गठित है। आबादी के हर एक हजार में ६१२ मजदूर और १६४ किसान हैं। आज इस देश के लगभग ३·७ करोड़ लोग बौद्धिक कार्य करते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टि में वर्ग पहचान की मुख्य कसौटी है उत्पादन के साधनों से सम्बन्ध।

हम उनसे सहमत नहीं हैं जो अन्य विशेषताओं जैसे काम की किस्म को पहला स्थान देते हैं, क्योंकि एक ही निगम में कार्य करने वाले अध्यक्ष और क्लर्क एक ही कोटि में आ जायेंगे।

स्वामित्व का चरित्र ही समाज की वर्ग-संरचना को तथा लाभ की प्राप्ति और वितरण के रूप को परिभाषित करता है। सोवियत उदाहरण से इसकी पुष्टि हो जाती है। उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के उन्मूलन से हमारे समाज की वर्ग-संरचना में ज़बरदस्त बदलाव आ गया। भूस्वामी वर्ग तथा शहरी और देहाती पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व समाप्त हो गया, तथा उत्पादन के प्रधान साधनों पर स्वामित्व रखने वाले शोषकों और अस्वामी या गैर मालिकाना शोषितों में जनता के विभाजन का अंत हो गया। वर्ग विरोधों और वर्ग संघर्ष का आधार समाप्त हो गया। बुद्धिजीवियों को हमने कभी एक वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि समाज के एक तबके मात्र के रूप में देखा है।

सोवियत संघ में कार्य के चरित्र और जीवन शैलियों में, आय के स्तरों और

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ऐसी अन्य चीजों में जो वर्ग विभेद अभी भी मौजूद हैं, वे गहरे होने के बजाय उल्टे धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं।

इसी प्रकार शिक्षा के स्तरों में अंतर लुप्त होते जा रहे हैं—कारण यह है कि नगर या देहात के सभी नौजवान कम से कम पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। १९३९ में प्रति एक हजार मजदूरों में ८४ तथा प्रति एक हजार सामूहिक किसानों में १८ उच्चतर या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थे, १९७६ में ये आंकड़े क्रमशः ७१५ और ५३७ थे।

जहां तक किसानों की आय का सवाल है, जो ऐतिहासिक कारणों से लंबे अरसे तक शहरी आय से पिछड़ी रही, अब तेजतर गति से ऊपर उठ रही है जिससे अंतर घटता जा रहा है।

घरेलू सुख-सुविधा के साधनों, रोजगार और उन्नति के अवसरों, अवकाश-कालीन कार्यकलाप की परिस्थितियों आदि के साथ भी यही बात लागू होती है।

अन्य अंतर और खासतौर पर बौद्धिक और शारीरिक श्रम के अंतर भी खत्म होते जा रहे हैं।

कुल मिला कर हम एक ऐसी प्रक्रिया को घटित होते देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा समाज अधिकाधिक समरस बनता जा रहा है। यह प्रक्रिया वस्तुगत उपादानों तथा कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य के सोद्देश्य प्रयास दोनों का परिणाम है।

क्या अनेक सोवियतविदों के इस दावे में कोई सच्चाई है कि सोवियत संघ में एक संभ्रांत वर्ग है ?

इन दावों में लेश मात्र सच्चाई नहीं है। इस देश में संभ्रांत या अभिजात वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है जिसमें पहुंच का रास्ता "सामाजिक सोपान की निचली सीढ़ियों" के लोगों के लिए बन्द या दुर्गम हो।

सोवियत सरकार के वर्तमान सदस्यों में एक भूतपूर्व मंथन-कर्मी, एक स्वचल मशीन मिस्त्री, एक डिज़ायन इंजीनियर, एक फिटर, एक रेल इंजन ड्राइवर का सहायक, एक पायलट, एक बिजली मिस्त्री, एक बढ़ई, एक नक्शानवीस, और एक अकुशल मजदूर शामिल हैं। प्रत्येक दस मंत्रियों और राज्य समिति अध्यक्षों में सात लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्य-जीवन का आरंभ मामूली मजदूरों या किसानों के रूप में किया था। इसी प्रकार राजसत्ता के सर्वोच्च निकाय—सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत— के आधे से ज्यादा सदस्य भी मजदूर और किसान हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ये तथ्य हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो लोग देश के उच्चतम पदों पर आसीन हैं, वे इसके लिए "पैदा ही हुए थे"। उन्हें घर पर कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, किसी विशेष सुविधा-संपन्न कालेज या विश्वविद्यालय में, जो सोवियत संघ में कोई है भी नहीं, शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, तथा वे चुनिंदा लोगों के किसी प्राइवेट क्लब के सदस्य न थे क्योंकि इस देश में ऐसा कोई क्लब भी नहीं है। उनके मन में कभी किसी ने यह विचार नहीं जमाया कि वे शासन करने के लिए पैदा ही हुए हैं। वे तो अपनी प्रमाणित सांगठनिक योग्यता, ज्ञान, विशेषज्ञता, उद्यम, दूसरों के प्रति निःस्वार्थ और उत्तरदायित्वपूर्ण रुख के कारण उच्च पद प्राप्त कर सके। उन्हें "चिरकाल तक" सत्ता में रहने का कोई जनादेश नहीं मिला है, और वे ऐसी कोई विशेष जाति नहीं है जो शेष समाज से कटी हो और वस्तुतः उसके प्रति कोई जवाबदेही न रखती हो। जैसा कि अन्य किसी भी कार्य सार का नियम है, अगर वे अपने मौजूदा दायित्वों को निभाने में असफल रहते हैं या अपने प्रति व्यक्त किये गये विश्वास का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें उनके कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

क्या आपका विचार है कि आपके देश में कौमियतों का सवाल हल कर लिया गया है ?

जी हां, हम मानते हैं। अक्तूबर क्रांति के सम्पन्न होने के बाद आठवें दिन १५ नवम्बर (पुराने रूसी कैलेंडर से २ नवम्बर), १९१७ को नयी सोवियत सरकार ने लेनिन द्वारा हस्ताक्षरित रूस के जनगण के अधिकारों की घोषणा जारी की जिसने रूस के जनगण की समानता और संप्रभुता की, उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की जिसमें अलग होकर स्वयं अपना स्वाधीन राज्य बनाना भी शामिल था, समस्त राष्ट्रीय और धार्मिक विशेषाधिकारों और बंदिशों की समाप्ति के, तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के स्वतंत्र और निर्विघ्न विकास की घोषणा की।

इस प्रकार समाजवादी क्रांति की विजय के बाद शुरू के चंद दिनों के ही भीतर पूर्ववर्ती रूसी साम्राज्य के जनगण आपसी वैर, शत्रुता और विरोध के रास्ते से हटा दिये गये और शीघ्र ही वे आपसी सहयोग और अपने बीच सहयोग पर आधारित सम्बन्ध विकसित करने लगे। उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर में अंतर के समाप्त किये जाने के गुरुतर महत्व का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

कौमियतों के सवाल का जो सही समाधान निकाला गया, उसके फलस्वरूप

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जनगण का सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ या सोवियत संघ के एक बहुराष्ट्रीय राज्य में स्वैच्छिक एकीकरण हो गया जो पंद्रह घटक जनतंत्रों का एक संघ है।

परस्पर सहायता कार्यक्रमों से इन तमाम जनतंत्रों ने आधुनिक महत्वपूर्ण उद्योगों का निर्माण कर लिया, स्वयं अपने राष्ट्रीय कुशल श्रमिकों और बुद्धिजीवियों को प्रशिक्षित किया, तथा स्वयं अपनी संस्कृति का संवर्धन किया जिसका रूप राष्ट्रीय और अंतर्वस्तु समाजवादी है। पहले के पिछड़े अनेक जनगण विकास के पूंजीवादी चरण को लाघं गये तथा सीधे समाजवाद के निर्माण के चरण में दाखिल हो गये।

किरगीज़िया सांस्कृतिक क्रांति के प्रभावों का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। १९१७ से पहले प्रत्येक पांच सौ किरगीज़ियाइयों में से एक लिख-पढ़ सकता था। आज इस जनतंत्र में निरक्षरता वस्तुतः उन्मूलित की जा चुकी है, तथा प्रत्येक दस हज़ार की आबादी पर अमरीका या फ्रांस से ज्यादा विश्वविद्यालय और कालेज हैं; वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रतिष्ठानों के कर्मीदल में विज्ञान के डाक्टर या कैंडिडेट की अकादेमिक डिग्री वाले २,४०० से अधिक किरगीज़ियाई हैं।

किरगीज़िया के साहित्य और कलाओं ने विस्मयकारी प्रगति की है : जहां कभी लिपिबद्ध वर्णमाला भी न थी, वहां आज राष्ट्रीय साहित्य और आपेरा और सुरीला संगीत मौजूद है।

अन्य राष्ट्रीय जनतंत्रों में भी इसी प्रकार की प्रगति की गयी है। इस सोवियत अनुभव की ओर विदेशों का ध्यान बहुत ही ज्यादा आकृष्ट हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिन दिनों पर्यटन का मौसम पूरी बुलंदी पर होता है, मध्य एशियाई जनतंत्रों में उन परिवर्तनों को स्वयं अपनी आंखों देखने के लिए हजारों विदेशी जमा हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने केवल सुन या पढ़ रखा है मगर जिन पर उन्हें विश्वास कर पाना मुश्किल होता है।

क्या आप के यहां कोई राष्ट्रीय विशेषाधिकार या बंदिशें हैं ?

कोई भी नहीं। सोवियत संघ के संविधान के अनुच्छेद १२३ में कहा गया है: "सोवियत संघ के नागरिकों के आर्थिक, सरकारी, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में अधिकारों की समानता, चाहे वे जिस कौमियत या जाति के हों, एक अमोघ कानून है।"

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस अनुच्छेद के दूसरे भाग में यह व्यवस्था है : "अगर जाति या कौमियत के आधार पर नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष बंदिश लगायी जाती है, अथवा विलोमतः प्रत्यक्ष या परोक्ष विशेषाधिकारों की प्रतिष्ठा की जाती है, और इसी प्रकार अगर जातीय या कौमी विशिष्टता या घृणा और अवमानना का प्रतिपादन किया जाता है; तो वह कानूनन दंडनीय होगा।"

क्या "मिश्रित" विवाह आम हैं ?
आपके देश में उन्हें कैसी दृष्टि से देखा जाता है ?

सोवियत संघ में हर सात में से एक परिवार "मिश्रित" विवाह से बना होता है। ऐसे विवाहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उक्राइन, लात्विया और कजाखस्तान में प्रत्येक पांच में से एक विवाह, तथा मध्य एशिया के नगरों और कस्बों में प्रत्येक चार में से एक विवाह मिश्रित होता है।

हम यह मानते हैं कि ऐसे विवाह सामाजिक एकता में योग देते हैं। कानून उन पर कोई बंदिश नहीं लगाता, और ऐसे विवाहों से उत्पन्न बच्चे इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि वे सोलह साल की उम्र के होने पर कौन-सी राष्ट्रीयता को ग्रहण करें—पिता की या माता की।

समाजशास्त्रियों का कहना है कि "मिश्रित" शादियों में आम शादियों की अपेक्षा तलाकों का अनुपात कम होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि इन विवाहों के नियोजन पर सोच-विचार अधिक करना पड़ता है।

क्या सोवियत नागरिक विदेशियों से विवाह कर सकते हैं ?

जी हां, जरूर। पिछले चंद वर्षों में ८,००० से अधिक सोवियत नागरिकों ने विदेशियों से शादियां की हैं तथा अपनी पत्नियों या पतियों के साथ ११० अन्य देशों में रहने चले गये हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

समानता से हमारा आशय है समाज द्वारा अपने सदस्यों को राष्ट्रीयता, जाति, धर्म या सामाजिक हैसियत के आधार पर कोई रोक लगाये वगैर समान अधिकारों और अवसरों का प्रदान किया जाना।

समानता का आधार है कार्य करने का कारगर अधिकार जिसके वगैर अन्य तमाम अधिकार और आजादियां अधिकांशत: गुरु-गंभीर लेकिन थोथे शब्द भर रह जाती हैं। इस देश में चौथे दशक के आरंभ मे ही बेरोजगारी समाप्त कर दी गयी थी। अर्थतंत्र के योजना के अनुसार संम, सतत विकास का अर्थ है माध्यमिक स्कूलों अथवा व्यावसायिक स्कूलों तथा उच्चतर और विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा प्रतिष्ठानों में शिक्षा समाप्त करने के वाद लाखों नौजवानों के लिए उनके अपने धंधे या पेशे में रोजगार की गारंटी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सबकी पहुँच में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा तथा बुढ़ापे में, बीमारी या अक्षमता की दशा में या भरण-पोषण करने वाले के न रहने पर सामाजिक सुरक्षा, तथा विश्राम और मनोरंजन का अधिकार, ये तमाम बातें सोवियत कानून में शामिल हैं और भौतिक रूप में इनकी गारंटी कर रखी गयी है।

लेकिन इसका अर्थ यह मत मान लीजिए कि हम वेतन का एक ही स्तर निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। किये गये काम के परिमाण और उसके गुण के अनुसार श्रम के लिए पारिश्रमिक या मेहनताना देने के समाजवादी सिद्धांत में यह पूर्वकल्पित है कि मजदूरों की विभिन्न कोटियों के बीच नकद आमदनी के स्तरों में कुछ अंतर होते हैं। साथ ही कमोबेश समान आय वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति आय उनके आकार के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

विभिन्न व्यक्तियों, परिवारों और जब-तब मजदूरों की पूरी की पूरी श्रेणियों के रहन-सहन के स्तरों को कुछ अन्य हेतु भी प्रभावित करते हैं। मसलन, आर्कटिक प्रदेश की कठोर जलवायु के हालात में, तथा साइबेरिया और सुदूर पूर्व के अभी भी अत्यल्प विकसित भागों में रहने वाले लोगों को ही लीजिए। उन्हें आवास, आवागमन, उपयुक्त कपड़ों और आहार तक पर काफी अधिक खर्च करना पड़ता है। प्रसंगवश बता दिया जाये कि यह बात केवल इसी देश के साथ लागू नहीं होती। सोवियत राज्य अपने समस्त नागरिकों को रहन-सहन की समानत: अनुकूल परिस्थितियां मुहैया करने के लिए अपने भरसक-प्रयास कर रहा है, चाहे वे मास्को में रहते हों या मध्य एशिया में या साइबेरिया में। विशेष रूप में

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कठोर जलवायु में रहने वाले लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे अधिक वेतन, ज्यादा लम्बी छुट्टियां, या यात्रा भाड़े से छूट आदि।

वेतन में जो वृद्धि अभी वर्तमान पंचवर्षीय काल में की जा चुकी है तथा इस समय लागू की जा रही है, उसका ताल्लुक सबसे पहले निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों से है तथा यह कानून द्वारा स्वीकृत न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच के अन्तराल को धीरे-धीरे कम करता जायेगा। पेंशनों, अनुदानों, भत्तों और छात्रवृत्तियों में तथा निःशुल्क लाभों और सेवाओं में की गयी वृद्धियां भी हमें अपने लक्ष्य के निकटतर पहुंचा रहीं हैं।

सोवियत राज्य सामाजिक समानता को सच्चे अर्थों में आश्वस्त करने के लिए जो कुछ कर रहा है, उस सबका वर्णन करने के लिए यहां स्थान न होने से हम निम्नलिखित उदाहरण दे देना मात्र पर्याप्त मानते हैं। सोवियत संघ जैसे विशाल देश में अभी भी एक बड़े नगर और एक छोटे से ग्राम्य समुदाय में रोजगार और कार्य-जीवन के समान सुयोगों, सर्वथा समान सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं अथवा सांस्कृतिक उन्नति के समान सुअवसरों की गारंटी कर सकना असंभव है। किंतु नगर और ग्राम के बीच के अंतर को दूर करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। पार्टी और सरकार ने ग्रामीण आबादी को बेहतर परिस्थितियां और जीवन स्तर सुलभ करने के लिए, अथवा उदाहरण के रूप में गांवों के नौजवानों को उच्चतर या विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर सुलभ करने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिन्हें लागू किया जा चुका है, तथा और भी अनेक उपायों की योजना बन रही है।

--

सोवियत संघ में किसे आलोचना करने का अधिकार है और किसकी आलोचना की जा सकती है?

प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी या पार्टी के निकाय की तथा किसी भी कार्याधिकारी की उसके ओहदे की परवाह किये वगैर आलोचना करने का अधिकार है।

इस अधिकार का व्यवहार में अनेक प्रकार से व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम आलोचना के विकास के बगैर और आगे सामाजिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। किसी समाचारपत्र या पत्रिका की ऐसी प्रति खोज सकना

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मुश्किल होगा जिसमें आलोचनात्मक पत्र, लेख और अन्य सामग्रियां न हों। प्रमुख सोवियत दैनिकों में स्थान पाने वाले घरेलू मसलों से संबंधित औसतन हर पांच सामग्रियों में से एक में किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की आलोचना होती है। यह बहुत ज्यादा है या बहुत कम ? सोवियत संघ में ८,००० समाचारपत्र हैं जिनकी कुल १६.५ करोड़ प्रतियां बिकती हैं जिनमें से प्रावदा, त्रुद और इज्वेस्तिया जैसे अग्रणी दैनिकों की २.५ करोड़ प्रतियां बिकती हैं। इनके अलावा कुछ विशेष व्यंग्य पत्रिकाएं हैं जैसे क्रोकोदिल (अर्थात घड़ियाल) या इसकी समकक्ष राष्ट्रीय भाषाओं की पत्रिकाएं हैं जो विभिन्न घटक जनतंत्रों में प्रकाशित होती हैं। इन व्यंग्य पत्रिकाओं का स्पष्ट उद्देश्य ही हमारे दैनंदिन के हर पहलू को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना है।

आलोचना केवल समाचारपत्रों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जाती। संभवत: राज्य संबन्धी और स्थानीय दोनों ही विषयों की आलोचना अन्य कहीं से ज्यादा विविध ट्रेड यूनियन और पार्टी मीटिंगों में सुनी जा सकती है। कर्मशाला अधीक्षक से मंत्री तक हर स्तर के कार्याधिकारी अपने पास से भेजी गयी किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी का संतोषजनक उत्तर देने तथा इस बात की रिपोर्ट देने को बाध्य होते हैं कि त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या किया गया या किया जायेगा।

आलोचना के अधिकार का सोवियत जनता द्वारा व्यापक प्रयोग देश के जीवन में तथा अपने काम करने के कारखाने, फार्म या कार्यालय के मामलों में उनकी गहरी और सक्रिय रुचि का परिचायक है।

सोवियत नागरिक यह महसूस करता है कि वह अपने देश के कामकाज के संचालन में भाग लेता है, और इससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का, ऐसी किसी भी चीज के प्रति असहिष्णुता की भावना को बल मिलता है जो सामान्य जीवन और कार्य के अभी भी आड़े आती हो, जो अपने कम्युनिस्ट आदर्शों की प्राप्ति की दिशा में सोवियत समाज की प्रगति में अड़चन पैदा करती हो।

सोवियत जन ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे भविष्य के प्रति आश्वस्त अनुभव करते हों। यह विश्वास उन्हें किस बात से होता है ?

एक तो वह देख सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में उनके लिए क्या कुछ है, क्योंकि वह उस विकास कार्यक्रम में सन्निविष्ट होता है जिस पर पूरा देश बहस करता है

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ग्रोर जिसे लागू करने के लिए वह पूरा प्रयास करता है। ये योजनाएं उनकी अपनी योजनाएं होती हैं, ग्रौर चूंकि उनको तैयार करने की जिम्मेदारी उन पर होती है ग्रोर फिर वे ही उनको कार्यान्वित करते हैं इसलिए उनके फलीभूत हो जाने की भी वे ठीक ही ग्राशा करते हैं।

सोवियत समाज की राजनीतिक सुस्थिरता, उसकी सतत ग्रार्थिक प्रगति तथा उसका निरंतर ऊपर उठता जीवनमान उसे संकटों, बेकारी ग्रौर मुद्रास्फीति तथा तज्जन्य तमाम कुपरिणामों से त्राण दिला देते हैं।

सोवियत इन्सान की ग्राशावादिता निश्चय ही ग्रनेक पीढ़ियों के दौरान संचित ग्रनुभव की भी देन है। विदेशी हस्तक्षेप ग्रौर गृह युद्ध के वर्षों की विभीषिका, सोवियत सत्ता के ग्रारंभ के वर्षों में सर्वत्र व्याप्त ग्रार्थिक ग्रव्यवस्था ग्रौर भूख, ग्रथवा नाज़ी जर्मनी के खिलाफ पिछले युद्ध में झेली गयी ग्रतिमानवीय ग्रग्निपरीक्षा के बावजूद सोवियत जन ने भविष्य के प्रति ग्रपनी विश्वास की भावना कभी नहीं खोयी। उन्होंने ग्रपने देश की रक्षा की ग्रौर ग्रब उन्नत समाजवाद के समाज का निर्माण कर लिया है जिसमें सब कुछ मानव के कल्याण के लिए किया जाता है।

इसका यह ग्राशय नहीं कि हमारी जनता को धक्के नहीं लगे। कौन दावे से कह सकता है कि कार्य-जीवन का वह सही चुनाव ही कर लेगा, ग्रथवा किसी ग्रकादेमिक डिग्री के लिए ग्रपने शोधग्रंथ को प्रस्तुत करने में सफल ही हो जायेगा? व्यक्तिगत दुर्भाग्य या त्रासदी से रक्षा की गारंटी करने का कोई रास्ता नहीं है।

ग्रापके देश में क्या पुरानी ग्रौर नयी पीढ़ियों के बीच टकराव है?

ग्रगर ग्राप हमारे समाज को समष्टि रूप में लें तो उसका ग्रस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके संभावित हेतुग्रों का भी ग्रस्तित्व नहीं है। दूसरी ग्रोर, "स्थानीय" गलतफहमियां या टकराव हो सकते हैं, खासतौर पर तब जब कि पुरानी पीढ़ी के लोग नौजवानों की जीवन-शैली, ग्रभिरुचियों, फैशनों ग्रौर मनपसंद बातों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, या जब नौजवान इन बातों पर हठधर्मी के साथ ग्रड़ जाते हैं। ग्रगर एक भी पक्ष सूझ-बूझ की कमी का परिचय देता है, या नयी पीढ़ी के लोग ग्रपने पांव पर वस्तुतः खड़े होने के पहले ही ग्राजाद होने की इच्छा करने लगते हैं तो कभी-कभी पारिवारिक टकराव पैदा हो जाते हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फिर भी इस देश में ऐसी समस्याओं को लेकर पीढ़ियों के बीच मतभेद नहीं पैदा होते जिनसे हमारे जीवन का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता हो। कुल मिला कर युवा पीढ़ी अपने ज्येष्ठों के आदर्शों, हमारी समाज व्यवस्था के प्रति, जीवन के लक्ष्यों और भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को आत्मसात और विकसित करती है, तथा उनके कार्य को कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ाती है।

इस सर्वनिष्ठ कार्यक्रम के कारण विविध विषयों को ले कर फूट डालने वाले अंतर्विरोधों को इसके पहले हल कर लिया जाता है कि वे बढ़ कर व्यापक टकराव और "नौजवानों के विद्रोह" का रूप ले सकें जो पूंजीवादी समाज की लाक्षणिक विशेषता बन चुके हैं।

आप कहते हैं कि आपके देश में स्त्री-पुरुष की समानता कानूनन है। स्त्रियों की समानता आश्वस्त करने के लिए वस्तुतः क्या किया जाता है?

स्त्री-पुरुष की समानता की व्यवस्था सोवियत संघ के संविधान में की गयी है, तत्संबद्ध कानून और भौतिक सुविधाओं द्वारा उसकी गारंटी की गयी है, तथा इसका सख्ती के साथ पालन किया जाता है।

प्रतिशत में देखा जाये तो इस देश में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा-प्राप्त स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा हैं। युद्ध कालीन भारी जन हानि के कारण संपूर्ण कार्यकारी शक्ति में स्त्रियां ५१ प्रतिशत हैं जो निःसंदेह समान कार्य के लिए समान वेतन अर्जित करती हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश स्त्रियां बौद्धिक और यंत्रीकृत कार्यों में लगी हैं; अतः प्रत्येक पांच स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों में चार, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों में पूर्ण बहुमत मे, रेडियो इलेक्ट्रानिकी उद्योग के प्रत्येक तीन कर्मियों में दो स्त्रियां हैं। चार हजार से अधिक स्त्रियां औद्योगिक संयंत्रों का प्रबंध और प्रशासनिक कार्यालयों की अध्यक्षता करती हैं, तथा २,००,००० से अधिक महिलाएं कारखानों की कर्मशालाओं और अनुभागों या प्रयोगशालाओं की देख-रेख करती हैं।

सोवियत नारियां देश के राजनीतिक और सार्वजनिक विषयों में, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयास में तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में ३१ प्रतिशत, संघीय जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतों में ३५ प्रतिशत, तथा स्थानीय सोवियतों में

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

४८ प्रतिशत स्त्रियां हैं। तुलना के लिए उल्लेख किया जा सकता है कि अमरीका में संघीय और स्थानीय शासन में कार्य करने वाली स्त्रियां केवल पांच प्रतिशत हैं।

हमारे देश और अन्य समाजवादी देशों के अनुभव से पता चलता है कि स्त्रियां अनेक कार्यों में तथा शासन के संचालन में बहुमूल्य योगदान कर सकती हैं। सच तो यह है कि हम आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए उनकी सहभागिता को अनिवार्य मानते हैं।

हालांकि हमारी उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी समस्याएं अभी भी शेष हैं। इन्हें पार्टी और राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व का विषय माना जाता है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में खासतौर पर कहा गया है कि दैनंदिन जीवन में महिलाओं की असमान स्थिति के अवशेषों को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए।

इसके लिए क्या किया जा रहा है? पिछले बीस वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं का परिमाण बढ़ कर सात गुना हो गया है, और आज किंडरगार्टेनों और शिशुसदनों में पहले से दुगुने बच्चे रखे जा सकते हैं। वैकुअम क्लीनरों और कपड़ा धुलाई मशीनों जैसी घरेलू मशीनों की संख्या पिछले दस वर्षों में तिगुनी हो गयी है, तथा रेफ्रिजरेटरों की संख्या छह गुनी।

आज अनेक परिवारों में और खासतौर पर युवा परिवारों में "श्रम विभाजन" का सवाल पति और पत्नी दोनों से संबन्धित होता है। समाजशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि हर पांच परिवारों में से दो में स्त्रियां प्रधान होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह देखा है कि बच्चों वाले कुटुंबों के घरेलू कामकाज में पत्नियों का पतियों से औसतन दुगुना समय लगता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार में ही नहीं बल्कि स्त्रियों के घरेलू कामकाज के बोझ को कम करने का एक नया दूरगामी कार्यक्रम रखा है। स्त्रियों की काम और रहन-सहन की और आम परिस्थितियों तथा माता और शिशु के कल्याण से संबंधित प्रश्नों से निवटने के लिए सोवियत संसद के दोनों सदनों—संघीय सोवियत और कौमियतों की सोवियत—ने विशेष स्थायी समितियां नियुक्त कर रखी हैं।

हालांकि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में युद्ध के बाद पहली बार कार्यबल में पुरुष कर्मचारियों का प्राधान्य हो जायेगा, फिर भी नारी-श्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। उनके काम को हलका बनाने के लिए बहुत कुछ किया जायेगा। १,१६५ बुनियादी व्यवसायों में से ऐसे कोई २०० को स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित कर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दिया गया है जिन्हें खतरनाक माना जाता है या जिनमें कठोर शारीरिक श्रम जरूरी होता है, और यह सूची लगातार बढ़ती जा रही है।

सोवियत संघ के आर्थिक विकास के एक विशेष खंड में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि महिला कर्मचारियों के काम और रहन-सहन की और आम परिस्थितियों में और सुधार किया जाये। उन्हें शिशुओं की एक साल की उम्र तक देखभाल करने के लिए आंशिक वेतन पर छुट्टी का अधिकार है तथा कार्यदिवस या कार्यसप्ताह कम घंटों का रखने या घर पर काम करने दिया जाता है।

स्त्रियों के लिए घरेलू कामकाज को आसान बनाने के लिए और भी प्रयास किये जायेंगे। लोक सेवाओं का परिमाण ४८ प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा दिवाकालीन देखरेख स्कूलों में स्थान दुगुना कर दिया जायेगा तथा किंडरगार्टेनों और शिशुसदनों में और भी २८ लाख बच्चों के लिए व्यवस्था की जायेगी। इससे साफ पता चल जाता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक कार्यक्रम कितना "स्त्रीप्रधान" है, जो स्त्रियों और पुरुषों को सामाजिक और घरेलू स्तर पर यथार्थ समानता प्रदान करने में नयी छलांगें लगायेगा।

किशोरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप क्या करते हैं ?

बच्चों को १८ वर्ष की आयु का होने के पहले अनेक कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

अक्तूबर क्रांति के बाद नवगठित सोवियत सरकार ने १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाड़े पर रखने की मनाही करते हुए एक विशेष आज्ञप्ति जारी की। ४ जनवरी, १९१९ को एक विशेष बाल प्रतिरक्षा परिषद स्थापित की गयी। गृहयुद्ध, विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक अस्तव्यस्तता के भयावह दिनों में नवोदित सोवियत जनतंत्र ने उदीयमान पीढ़ी की रक्षा करने के लिए कई कानून बनाये और उन्हें लागू किया। मई १९१९ में, जिस समय पूरा देश भुखमरी के कगार पर था, १४ साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता था, चाहे उनके माता-पिता सोवियत सत्ता के पक्ष में रहे हों या विपक्ष में।

उन आरंभिक वर्षों में जो मानवीय कानून लागू किये गये, उनमें बच्चों और किशोरों के अधिकारों को बुलंद रखने और उनकी रक्षा करने के लिए और आगे के कानूनों की नींव पड़ गयी। वर्तमान विधि संहिताओं में विशेष रूप से बच्चों के लिए

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अनुच्छेद हैं। जैसे रूसी संघ की श्रम संहिता के २५६ अनुच्छेदों में से ४८ का संबन्ध श्रमी किशोरों और बच्चों वाली स्त्री कर्मचारियों की श्रमरक्षा और विशेषाधिकारों एवं लाभों से है। जैसे यह व्यवस्था कर दी गयी है कि बच्चों को १६ वर्ष की आयु के बाद ही वेतन पर रखा जा सकता है। कुछ असाधारण परिस्थितियों में और चिकित्सकीय अनुमति और ट्रेड यूनियन की मंजूरी लेकर ही १५ वर्ष की आयु में किसी बच्चे को काम पर रखा जा सकता है।

बाल श्रमिकों का कठोर भूमिगत कार्य में या ऐसे कार्यों में लगाने की मनाही है जिन्हें स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है या जिनसे रात में या अतिरिक्त समय काम करना जरूरी होता है। १६ से १८ वर्ष की आयु के लिए कानूनन स्वीकृत ४१ घंटे के कार्यसप्ताह को घटाकर ३६ घंटे कर दिया जाता है हालांकि उन्हें उतना ही वेतन मिलता है जितना तत्संबंधी हुनरों और योजनाओं वाले वयस्कों को।

श्रमी बालकों को पहले इतने ज्यादा लाभ हासिल हैं कि किसी-किसी प्रबन्धक को उसकी जगह बालिगों को रख लेने का "प्रलोभन" पैदा हो जाता है। लेकिन यहां फिर कानून आड़े आता है। किसी बच्चे को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जबकि स्थानीय सोवियतों से संलग्न बाल विषय आयोग अपनी सहमति दे दें। और अगर किसी बच्चे को बर्खास्त कर भी दिया जाता है तो उसे फौरन उसकी पसंद का कोई दूसरा काम दिया जाना चाहिए।

हालांकि जैसा हम कह चुके हैं, एक नौजवान सरकारी तौर पर १८ वर्ष की उम्र में वयस्क या बालिग सोता है, मसलन उसे मतदान का अधिकार मिल जाता है, फिर भी कम आयु की बालक-बालिकाएं अनेक नागरिक अधिकारों का उपभोग करती हैं। जैसे किसी रचना या संगीत के बाल प्रणेता को कापीराइट का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। उत्तराधिकार या उपहार की दशा में बच्चों को जन्म से ही संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है।

सामाजिक भरण-पोषण और सामाजिक बीमे को बच्चों पर भी लागू कर दिये जाने से उदीयमान पीढ़ी को समानता प्रदान करने में सबसे ज्यादा सहायता मिली है। अपने से ज्येष्ठ लोगों की ही भांति बाल कर्मचारियों को भी वही बीमारी के समय की सुविधाएं और भत्ते तथा वही वार्षिक सवेतन अवकाश मिलते हैं। जो बच्चे काम और अध्ययन एक साथ चलाते हैं, उन्हें परीक्षा आदि के लिए अतिरिक्त सवेतन अवकाश का अधिकार होता है।

सभी बच्चों को समान अवसर का सिद्धांत पूरी तरह लागू है; जैसे सोवियत संघ पहला देश है जिसने उच्चतर स्तर तक सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा लागू की।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या सोवियत संघ में हथियार खरीदे जा सकते हैं ?

रूसी संघ के फौजदारी कानून की धारा २१८ के तहत "स्पष्ट अनुमति के बिना चिकनी नली की शिकारी बंदूक के अलावा अन्य आग्नेयास्त्र, तथा बारूद और विस्फोटक भी, साथ लेकर चलना, जमा रखना, बनाना या बेचना दो साल तक स्वतंत्रता से वंचित कर के या साल भर तक के परिष्कारी श्रम द्वारा, अथवा सौ रूबल के जुर्माने द्वारा दंडनीय है। स्पष्ट अनुमति के बिना कटार, तलवार या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर चलना, जमा रखना, बनाना या बेचना, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां धारदार हथियारों को पहनना राष्ट्रीय वेशभूषा का अंग है अथवा शिकार और पशुओं को पकड़ने से सम्बन्धित है, एक साल तक स्वतंत्रता से वंचित करके या एक साल के परिष्कारी श्रम द्वारा अथवा तीस रूबल के जुर्माने द्वारा दंडनीय है।

खेलकूद और शिकार की बंदूकों और पिस्तोलों के अलावा देश में और कोई हथियार नहीं बिकता। बहरहाल, शिकार और खेलकूद के ये हथियार विशेष दुकानों पर खरीदे जा सकते है, बशर्ते विदेशी नागरिकों के मामले में सोवियत संघ के आंतरिक विषय कार्यालयों से, और सोवियत नागरिकों के मामले में उनके रिहायशी क्षेत्र के स्थानीय मिलिशिया थाने से शिकारी बन्दूक या बारीक नली की राइफल का आवश्यक अनुमतिपत्र जारी कर दिया गया हो, बशर्ते वे शिकारी का कार्ड, अथवा खेलकूद का हथियार जरूरी होने पर किसी खेलकूद क्लब का सदस्यता कार्ड पेश करें।

इतने पर भी भावी शिकारी को १८ साल से कम आयु का न होना चाहिए, और अगर वह किसी शिकारी संगठन का सदस्य बनना चाहता है तो उसे यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह ऐसी बंदूकों को बरतना जानता है।

शिकारी बंदूकें बेचने वाली दुकानें प्रत्येक बंदूक बेचने के साथ ग्राहक का नाम, पता और शिकारी कार्ड की संख्या दर्ज करती हैं। इसी प्रकार उसका शिकारी क्लब अपने सदस्यों की बंदूकों की क्रम संख्याएं दर्ज रखेगा। इसी तरह शिकार के चाकू भी तभी खरीदे जा सकते हैं जबकि भावी ग्राहक अपना शिकारी कार्ड दिखाये।

बच्चों को, अवरुद्ध विकास वाले या मानसिक दृष्टि से विक्षुब्ध व्यक्तियों को, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी न्यायिक जांच हो रही हो या जिस पर मुकदमा चल रहा हो, या इसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पहले किसी बड़े अपराध के लिए दंड मिल चुका हो, किसी भी प्रकार के हथियार की बिक्री की कतई मनाही है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आप गुण्डागर्दी से कैसे लड़ते हैं ?

सोवियत समाज अपराध का पूर्ण उन्मूलन कर देना चाहता है, इसलिए वह गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करता, जिसके लिए कानून में छोटे जुर्माने से ले कर स्वतंत्रता से वंचित किये जाने तक विविध सजाएं हैं।

हम सामुदायिक अदालतों द्वारा सामाजिक अनुनय-अनुरोध और भर्त्सना को विशेष महत्व देते हैं। बहुत से अपराधी कानूनी दंड से ज्यादा अपने कार्य सामूहिकों की नैतिक निंदा से डरते हैं।

सार्वजनिक कानून और अमन के उल्लंघनों से लोहा लेने का कार्य केवल मिलिशिया ही नहीं बल्कि कारखाने या कार्यालय के कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय और कालेज छात्रों से गठित जन द्रुझिना या स्वयंसेवी जत्थे भी करते हैं जो सड़कों, चौकों, पार्कों, खेलकूद मैदानों और क्लबों में कानून और अमन की रक्षा करने में मदद करते हैं।

स्थानीय सोवियतों से संलग्न बाल-विषय आयोगों के सदस्य तत्संबद्ध सोवियत के सदस्य ही नहीं बल्कि सार्वजनिक संगठनों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा संगठनों के प्रतिनिधि भी होते हैं। ये निकाय जो विस्तृत विविधतापूर्ण कार्य करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिक मानों का उल्लंघन करने वाले युवा अपराधियों पर दबाव डालना ही नहीं, बल्कि समाज विरोधी व्यवहार की रोकथाम करना तथा उपद्रवी बच्चों के सुधार में मदद करना भी है।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुंडागर्दी से लड़ने में अच्छी प्रगति की गयी है। जैसाकि सोवियत संघ के गृह मंत्री निकोलाइ श्चेलोकोव ने कहा: "आबादी के ऐसे हजारों केंद्र हैं जहां सार्वजनिक कानून और अमन के भंग किये जाने की एक भी बड़ी घटना काफी लंबे अरसे से नहीं दर्ज हुई।

सोवियत संघ में जो लोग शारीरिक दृष्टि से कार्यक्षम होते हुए काम से इनकार करते हैं, उनके प्रति क्या कार्रवाई की जाती है ?

सोवियत संविधान में कहा गया है कि शारीरिक दृष्टि से प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है कि "जो काम नहीं करेगा, वह खायेगा भी नहीं।"

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्या यह जरूरत से ज्यादा दो टूक हैं ? हमारे विचार से नहीं। हमारा समाज नागरिकों को अनगिनत लाभ प्रदान करता है जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। हर सक्षम व्यक्ति से सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद प्रतिदान की आशा करना स्वाभाविक ही है। ध्यान रखिए कि हम गृहिणी के कामकाज को भी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। पर हमारे लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें ज्यादातर पुरुष होते हैं, समझ पाना मुश्किल है जो मजबूत और स्वस्थ और शारीरिक दृष्टि से सर्वथा कार्यक्षम होते हैं, लेकिन काम करने से इनकार करते हैं। इसलिए अगर हम इन व्यक्तियों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाते हैं, खासतौर पर अगर वे अनैतिक जीवन बिताते हों, हम सर्वथा उचित महसूस करते हैं। भला क्यों उन्हें भी वही सामाजिक लाभ प्राप्त हों जो ईमानदार श्रमिकों को मिलते हैं ? और साथ ही एक ऐसे समाज में जिसमें अन्य किसी व्यक्ति के श्रम का शोषण सिद्धांततः अकल्पनीय है, उनके पास अस्तित्व का कौन-सा जायज साधन है ?

ऐसे लोगों पर जो स्पष्टवादिता के साथ काम करने से इनकार कर देते हैं, जिन्हें हम परजीवी पुकारते हैं, हम जनमत का दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इस कारण और भी कि रिक्त स्थानों की संख्या तथा असंख्य रोजगार एजेंसियों से प्राप्त सहायता की बदौलत रोजगार खोजने में कोई समस्या नहीं पैदा होती।

किंतु कुछ ऐसे विशेष मामले हैं जहां कामचोरी को सामाजिक दृष्टि से हानिकर काहिलपन माना जाता है, जैसे उन लोगों के मामले में जिन्हें अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण का खर्च पूरा करना चाहिए, अथवा जो केवल कालाबाजारी या अन्य मुजरिमाना धंधे करते हों। जब उन्हें समझाने-बुझाने से कुछ नहीं बन पाता तो उन्हें फौजदारी कानून के अनुसार दंडित किया जाता है—लेकिन हम दुबारा कहना चाहेंगे, काहिलपन के लिए नहीं, बल्कि मुजरिमाना अपराध के लिए।

क्या सोवियत संघ में अधिकार और स्वतंत्रताएं किसी प्रकार मर्यादित हैं ?

जी हां, इस दृष्टि से कि इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता तथा उसके श्रम के फल को अपहृत नहीं कर सकता। युद्ध और हिंसा का किसी भी रूप में प्रचार तथा राष्ट्रीय या धार्मिक एकांतिकता की हिमायत मुजरिमाना अपराध माने जाते हैं। न तो स्त्री-पुरुष की समानता का

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उल्लंघन किया जा सकता है और न सामाजिक या राजकीय गतिविधि या कार्य के क्षेत्र में किसी के प्रति भेदभाव किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की वेश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य की ही भांति यह भी कानूनन दंडनीय है।

हम इन मर्यादाओं को उचित मानते हैं क्योंकि ये संपूर्ण समाज के हितों की पूर्ति करते हैं और साथ ही आनुषंगिक रूप में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों के भी अनुरूप हैं।

क्या सोवियत संघ में संपादकों पर किसी प्रकार की बंदिशें हैं ?

जी हां, सोवियत कानूनों के अनुसार बंदिशें हैं। कोई भी संपादक ऐसी सूचना नहीं प्रकाशित कर सकता जो सैनिक या राजकीय दृष्टि से गोपनीय हो, अथवा ऐसी सामग्री नहीं प्रकाशित कर सकता जो धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, अंधराष्ट्रवादी वृत्तियां भड़काती हो, चरित्र का अपमान करती हो, नस्लवाद को उकसावा देती हो, सामीवाद-विरोधी विचारों की हिमायत करती हो, युद्ध का आह्वान करती हो, अथवा अश्लीलता और परपीड़नमुख के संस्कार पैदा करती हो।

हमारे विचार से यह भी समान रूप में उचित और आवश्यक है।

क्या आपके देश में लोग धार्मिक उपासना कर सकते हैं ?

सोवियत संविधान में "धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता तथा धर्म-विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता" सभी नागरिकों के लिए स्वीकृत है। राज्य धार्मिक संगठनों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता या उन्हें कोई भौतिक अवलंब नहीं प्रदान करता; उधर धार्मिक संगठन राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है या उसे सर्वथा तिलांजलि दे सकता है। इस मसले में वह चाहे जो फैसला ले, उसकी एक नागरिक के रूप में उसके जीवन में कतई कोई भूमिका नहीं होती। किसी व्यक्ति के घरेलू पारपत्र, सरकारी प्रपत्रों या जनगणना की फाइलों में उसके धर्म का या धर्म के न होने का कोई उल्लेख नहीं होता।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

धर्मानुयायियों के प्रति भेदभाव की इस देश में मनाही है। अगर कोई धार्मिक उपासना और अनुष्ठान, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था का अतिक्रमण न करते हों और अन्य नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों तो उनमें बाधा उत्पन्न करने के दोषी किसी भी व्यक्ति पर फौजदारी कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को वेतन पर रखने या किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश देने से इनकार करना, इसी आधार पर किसी व्यक्ति को ऐसे विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित करना जिनका वह कानूनन अधिकारी है, अथवा अन्य किसी नागरिक अधिकार पर रोक लगाना कानून का घोर उल्लंघन माना जाता है।

सभी धर्मों को सर्वथा समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं, चाहे उनके अनुयायी थोड़े से हों या ज्यादा। स्थानीय शासनिक की निकायों के साथ समझौते द्वारा हर धार्मिक सत्संग या संघ को, जिसकी सदस्य संख्या कम से कम २० हो, उस जमीन के नि:शुल्क प्रयोग का अधिकार होता है जिस पर उसका गिरजाघर या उपासना-गृह बना हो, तथा उस इमारत के रखरखाव और मरम्मत का खर्च उक्त सत्संग या संघ पूरा करता है। कार्यवाहक पुरोहितों को विविध अनुष्ठानों और संस्कारों के लिए सत्संग के चंदे और शुल्क से पारिश्रमिक दिया जाता है। मोमबत्तियां बनाने के लिए स्थान और विविध धार्मिक सामग्रियों के निर्माण के लिए कर्मशालाएं पट्टे पर लेने, निर्मित करने या प्राप्त करने की भी अनुमति होती है।

सोवियत सरकार और विविध धार्मिक संघों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित धार्मिक विषय परिषद उनके आंतरिक मामलों में तो दखल नहीं देती, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि धार्मिक संघों की स्थिति को शासित करने वाले कानून का यथोचित पालन किया जाये।

देश में विविध धर्मों के २०,००० से भी अधिक गिरजाघर, प्रार्थनागृह, मठ और आश्रम हैं। सभी धार्मिक संप्रदायों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

धार्मिक साहित्य कौन प्रकाशित करता है ?

सारे मुख्य धर्म अपना साहित्य प्रकाशित करते हैं। जैसे १९७६ में मास्को पैट्रियार्की ने बाइबिल का एक और संस्करण निकाला जिसमें पूर्व और नव विधान (टेस्टामेंट) दोनों शामिल हैं। शीघ्र ही पैट्रियार्क पिमेन की रचनाओं की पहली जिल्द, कई धर्मशास्त्रीय कृतियां और अन्य चर्च संबंधी साहित्य प्रकाशित होंगे। *जर्नल आफ दि मास्को पैट्रियार्की* नामक पत्रिका की काफी अधिक प्रतियां

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

बिकती हैं जिसमें चर्च संबन्धी विषयों पर ही सामग्री नहीं होती है, बल्कि धर्मोपदेश, धर्मशास्त्रीय निबन्ध और अन्य सामग्रियां भी होती हैं।

इंजीली खीस्तीय बपतिस्मा-दाता चर्च की अखिल-संघीय परिषद भी बाइबिल और सुसमाचार के संस्करणों को तथा प्रार्थना पुस्तकों, पंचांगों और भजन-संग्रहों को नियमित रूप में प्रकाशित करती है, तथा उसकी पत्रिका *दि ब्रदर्ली हेराल्ड* रूसी के अलावा और कई राष्ट्रीय भाषाओं में निकलती है।

जहां तक मध्य एशिया और कजाखस्तान के मुस्लिम धार्मिक मंडल का सवाल है, हाल के वर्षों में उसने कुरान के छह संस्करण, इमाम अल-बुखारी के "अल-जमी-अल-सहीह" और "अल-अदब अल मुफ़ाद" तथा इस्माइल महमूद सत्तिएव का ओथमान इब्न अफ़्फ़ान कृत कुरान का इतिहास जो ताशकंद में सुरक्षित है, प्रकाशित किया है। वह *सोवियत पूर्व के मुसलमान* नामक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

भिन्नमतावलंबी कौन हैं और
वे कितने हैं?

"हम भिन्नमतावलंबी तीस से ज्यादा नहीं हैं", यह आंद्रेइ सखारोव ने एक बार विदेशी संवाददाताओं से बातचीत में स्वीकार किया था।

ये लोग कौन हैं जिनके नामों के साथ पश्चिम में "असाधारण", "अत्यन्त लोकप्रिय" और "प्रसिद्ध" जैसे विशेषण जोड़े जाते हैं?

हमारी दृष्टि में ये लोग जिन्हें पश्चिम में भिन्नमतावलंबी और "स्वतंत्रता का चैंपियन" माना जाता है, सोवियत संघ के खिलाफ—और तनाव-शैथिल्य के भी खिलाफ—चली जा रही एक नयी चाल के मुहरे हैं। प्रमुख पश्चिमी देशों के समाचार-पत्र अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भिन्नमतावलंबी लोग सोवियत सत्ता के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उसे सुधारना मात्र चाहते हैं।

खेद की बात है कि यह सच्चाई से बहुत दूर है।

हम अगर भिन्नमतावलंबियों की सलाह मानें तो हम अपने मकान में चंद छोटी-छोटी मरम्मतें न कर के, उससे बिलकुल हाथ ही धो बैठें।

अपेक्षाकृत अधिक सुविख्यात भिन्नमतावलंबी जिस बात की वकालत करते हैं और जहां उनकी सहानुभूतियां हैं, उनकी कुछ मिसालें यहां पेश हैं!

सोल्झेनित्सीन : "…वे लोग, जो '४१ के पहले भी हथियार उठा लेने और

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उन लाल कमिस्सारों की खुशामद करने के अलावा और कोई सपना नहीं देखते थे।" *(दि गुलाग आर्किपेलेगो)*; उनका आदर्श है फ्रंकोवादी हुकूमत जिसने स्पेनवासियों को "आदर्श जनवाद" प्रदान किया (स्पेन में दी गयी भेंट से)।

कुज्नेत्सोव : "...मैं सोवियत सत्ता के *विरुद्ध हूं* (*रुस्सकाया मिस्ल*, पेरिस, में छपे एक बयान से)।

सखारोव : पिनोशेत ने चिली में "पुनर्जागरण और एकीकरण के युग" का सूत्रपात किया (समाचार पत्रों को दिये गये एक बयान से)। सखारोव यह विश्वास करते हैं कि समाजवादी देशों की अपेक्षा "...पूंजीवादी किंतु जनतांत्रिक राज्य सच्चे अर्थों में मानव समाज के निकटतर हैं" तथा पश्चिम से यह अनुरोध करते हैं कि वह "सोवियत अधिकारियों पर प्रबलतम और अधिक से अधिक सचेत दबाव डाले" (अमरीका में प्रकाशित पुस्तक *सखारोव स्पीक्स* से); "भारी उद्योग, माल और नौभार यातायात और डाक सेवा के अलावा" सोवियत संघ की सेवाओं के संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण उद्योग को निजी हाथों में सौंप देना आवश्यक है (*डेर स्पायगेल* में प्रकाशित उनकी पुस्तक के सारांश से)। संक्षेप में, पूंजीवाद में वापसी !

बुकोव्स्की ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मैं बचपन से ही "सोवियत सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति" के स्वप्न देखता आया हूं, "लेकिन जब तक पश्चिम इस नियम से चिपका रहेगा कि उसे सोवियत संघ के अंदरूनी मामलों में दखल देने का हक नहीं है, तब तक इससे कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि हेल्सिंकी का समझौता इतना खतरनाक है।"

मानवाधिकारों की झंडाबरदारी का स्वांग भरने वाले भिन्नमतावलंबी और प्रथमतः तो उनके पक्षपोषक तनाव-शैथिल्य के समाप्त किये जाने का अनुरोध करते हैं। यही इस सबका निचोड़ है। सोल्झेनित्सीन ने एक नवफासिस्ट इटालियन पत्र में दी गयी भेंट में यह पूछे जाने पर कि वे चाहते क्या हैं, ऐलान किया : "सोवियत संघ के खिलाफ जेहाद।"

क्या ये लोग यह महसूस करते हैं कि आज की परिस्थितियों में सोवियत संघ के खिलाफ "जेहाद" का अर्थ क्या होगा ?

हम लंदन के *डेली मिरर* की उस समय की उद्विग्नता को भलीभांति समझ सकते हैं जब उसने ब्रिटेन में दिये गये सोल्झेनित्सीन के बयानों पर जुगुप्सा से भरकर यह कह डाला कि यह लखपति प्रवासी अंग्रेजों से यह चाहता है कि वे एक और युद्ध छेड़ देने के लिए आम लामबन्दी का ऐलान कर दें और फिर से हथियारबन्द हों।

लंदन में जिस समय इंटरनेशनल पेन क्लब का सम्मेलन आरंभ होने को था, उसके कुछ ही पहले सोवियत "लेखक" व्लादीमिर बुकोवस्की की सफाई में एक दस्ता-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

वज प्रकाशित की गयी जिसके बारे में यह दावा किया गया कि वह निर्दोष था और फिर भी जेल भेज दिया गया। उस समय वे सचमुच ब्लादीमिर जेल में थे। लेकिन उन पर जो आरोप लगाये गये थे उनसे वे निर्दोष कतई न थे। १९६३, १९६७ और १९७२ में उन्हें रूसी संघ की आपराधिक संहिता की धाराओं ७०/१ और १९०/३ के तहत सार्वजनिक कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने वाली समूहगत कार्रवाइयों को संगठित करने और उनमें सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए तथा सोवियत राज्य प्रणाली के खिलाफ संघर्ष की मुख्य विधि के रूप में आतंक के प्रयोग का स्पष्ट अनुरोध करने के लिए विविध अवधियों तक स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने का दंड दिया गया। १९७६ के उत्तरार्ध में उन्हें सोवियत संघ से निष्कासित कर दिया गया। अदालत ने यह निष्कर्ष रखा कि बुकोव्स्की की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां विदेश से निर्दिष्ट होती रही हैं।

जिन लोगों ने बुकोव्स्की को "लेखक" बना दिया, उन्हीं लोगों ने सोवियत संघ को त्याग कर बाहर जा बसने वाले आंद्रेइ अमालरिक को एक "अग्रणी सोवियत इतिहासकार" घोषित कर दिया और इस बात को बिलकुल विस्मृत ही कर दिया कि २३ वर्ष की आयु में अमालरिक को कालेज के द्वितीय वर्ष के अपने अध्ययन कार्य में पिछड़ जाने की वजह से मास्को विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से निष्काशित कर दिया गया था।

'भिन्न मतावलंबियों" में वालेंतिन मोरोज़ ने उन उक्राइनी राष्ट्रवादियों की आतंकवादी गतिविधि की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में संदिग्ध ख्याति अर्जित कर रखी है जिन्होंने पिछले युद्ध में नाज़ियों के साथ सहयोग किया था। उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में अपने विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जिसमें रूसियों और ब्येलोरूसियों से प्रति शत्रुता की भावना भड़काने के महत्व पर जोर दिया गया है तथा पश्चिम की कुछ शक्तियों के सैनिक समर्थन से सोवियत सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष संगठित करने का अनुरोध किया गया है। १९६६ में सोवियत कानून के तहत मोरोज़ को सोवियत-विरोधी आंदोलन और प्रचार के लिए चार साल तक स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने की सजा दी गयी। सजा पूरी कर लेने के बाद उन्होंने अपनी शत्रुतापूर्ण, राष्ट्रघाती गतिविधियां पुनः शुरू कर दीं जिसके लिए उन्हें पुनः दंडित किया गया।

और भी चंद शब्द उन कतिपय "भिन्नमतावलंबियों" के बारे में जो अब सोवियत संघ के बाहर रहते हैं। एन. गोर्बानेव्स्काया, ए. गालिच और वी. मक्सीमोव को भी "अग्रणी साहित्यिक विभूति" घोषित कर दिया गया है। पश्चिम के कुछ हलके इन प्रवासियों का ध्वंसात्मक सोवियत-विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ये "लेखक" और "वैचारिक योद्धा" वास्तव में किस प्रकार के लोग हैं, इस सम्बन्ध में कुछ धारणा इस तथ्य से बनायी जा सकती है कि सोवियत संघ में निवास के दिनों में गालिच ने "भाग्यशाली नक्षत्र में" नामक एक नाटक लिखा था तथा "राजकीय अपराधी" शीर्षक एक फिल्म का आलेख तैयार किया था जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान नाज़ियों के साथ सहयोग करने वालों को सोवियत मातृभूमि के प्रति गद्दार करार दिया था। किंतु आज देश की सीमा पार करते ही उन्होंने रुख पलट लिया है और अब सोवियत संघ के जीवन की स्याह तस्वीर पेश कर रहे हैं।

ये हैं वे सोवियत "भिन्नमतावलंबी" जो सिर्फ उन हलक़ों के लिए मूल्यवान हैं जो सोवियत संघ के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहे हैं।

क्या कोई व्यक्ति सोवियत संघ से बाहर जाकर बस सकता है ?

जी हां। किंतु ऐसा करने वालों की संख्या नगण्य है। ज्यादातर लोग अपने परिवारों के साथ जाकर रहने के लिए या किसी विदेशी से शादी कर लेने के कारण बाहर जाते हैं।

सोवियत कानून और उत्प्रवास के नियम नागरिक और राजनीतिक अधिकारों सबन्धी उन अंतर्राष्ट्रीयप्रतिज्ञापत्रों के सर्वथा अनुरूप हैं जिन्हें संयुक्तराष्ट्र महासभा ने १६ दिसंबर १९६६ को स्वीकृत किया था। दस्तावेज में खासतौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति का किसी अन्य देश में स्थायी रिहायश के उद्देश्य से स्वयं अपने देश का त्याग करने का अधिकार उस दशा में मर्यादित किया जा सकता है जिसका संबंध राज्यीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या आचार अथवा दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता से हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ मामलों में उत्प्रवास की अनुमति का निर्णय तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि परिवार अपने पारिवारिक मामलों का निबटारा न कर लें जिसमें भौतिक किस्म के मामले भी शामिल हैं। इसी प्रकार ऐसे लोगों को बहिर्गमन का वीसा देने का फैसला स्थगित किया जा सकता है जिनके पास राज्यीय गोपनीय सूचनाएं हों या जिन्होंने महत्वपूर्ण सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। निश्चित अवधि के समाप्त हो लेने पर जब उक्त व्यक्ति के पास की सूचना को वर्गीकरण से बाहर कर लिया जाता है, उसके बाद बहिर्गमन वीसा पर पुनर्विचार होता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

बाहर जा कर बसने के लिए अर्जी देने से क्या किसी नागरिक की सरकारी या सामाजिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

आमतौर पर नहीं। इसके चन्द अपवाद वे आवेदक होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में या वर्गीकृत अनुसंधान कार्य में रत संस्थाओं में कार्य करते होते हैं। ऐसे मामलों में ट्रेड यूनियन की सहमति से तथा श्रम कानून संहिता के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को उनके काम से मुक्त करके दूसरा कार्य सौंपा जा सकता है।

पश्चिम में गर्भपात की वैधता पर बहस
चलती ही जा रही है। आप इस
प्रश्न से कैसे निबटते हैं ?

सोवियत संघ की सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपमन्त्री प्रोफेसर येलेना नोविकोवा ने, जिनपर सोवियत माता एवं शिशु-कल्याण सेवा का प्रभार है, कहा है : "हालांकि मैं गर्भस्राव के खिलाफ हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है कि उसको कितने बच्चे हों, तो उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता।"

इस देश में गर्भपात की इजाजत है। स्त्री-पुरुष की समानता को स्वीकार करने वाले किसी राज्य के लिए यही स्वाभाविक रुख हो सकता है। गर्भपात की अनुमति देने वाले कानून के फलस्वरूप अवैध गर्भपात के हानिकर प्रभाव न्यूनतम हो गये हैं, क्योंकि गर्भपात पर प्रतिबन्ध से गर्भस्रावों की संख्या नहीं घटती बल्कि स्त्रियां अयोग्य व्यक्तियों की सहायता लेने को बाध्य हो जाती हैं। उन देशों में जहां कानून गर्भ के कृत्रिम स्राव की अनुमति नहीं देता, हजारों स्त्रियां अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठती हैं या मौत तक का शिकार हो जाती हैं।

आधुनिक नारी केवल अपने घर और परिवार से बंधकर नहीं रहना चाहती है, वह अपने शैक्षिक स्तर का विस्तार करना, एक स्वाधीन व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठापना करना, तथा अपनी बौद्धिक और आत्मिक क्षमताओं का विकास करना चाहती है। समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकांश सोवियत स्त्रियों का यह विश्वास है कि आदर्श परिवार में दो या तीन बच्चे होते हैं। जाहिर है, यह समझदारी का दृष्टिकोण है क्योंकि अपेक्षाकृत कम बच्चों का उपयुक्त लालन-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पालन काफी आसान होता है। एक अन्य बात यह है कि प्रसव आमतौर पर तो शरीर के लिए लाभकारी होता है लेकिन जब स्त्री पांच से दस बच्चों को जन्म देती है तो वह लाभकारी नहीं रह जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरे बच्चे के बाद प्रसव काल में मृत्यु, मधुमेह और कैंसर के कुछ रूपों का खतरा बढ़ जाता है।

स्त्रियों के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वे अपने परिवारों को नियोजित करना चाहें। गर्भपात निश्चय ही इसका सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई पूरी तरह निर्भरयोग्य गर्भ-निरोधक नहीं है जो हानिकर असर न छोड़ता हो। सोवियत संघ के प्रसूति और स्त्रीरोग अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में सोवियत संघ में हार्मोनों के प्रयोग का अध्ययन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक केन्द्र खोला गया है।

हार्मोनों से वनी दवाओं के प्रति हम सतर्कता का रुख अपनाते हैं और इस कारण हम उनका विज्ञापन नहीं करते क्योंकि वे स्त्री-शरीर को कुछ इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि उसे निरापद नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि हम आमतौर पर गर्भनिरोधकों के विरुद्ध हैं। ऐसी अनेक विधियां निकाली गयीं है जो अवांछित गर्भाधान रोकती हैं। हालांकि वे शतप्रतिशत भरोसेमंद नहीं हैं। स्त्रियों को इन विधियों के प्रयोग का तरीका सिखाना ही गर्भपातों की संख्या कम करने का सही रास्ता है।

किसी स्त्री को गर्भस्राव कराने को मजबूर करने वाले वस्तुगत हेतुओं को दूर करना भी इसमें सहायक होगा। इनमें मधुमेह, गुर्दे और दिल की बीमारियों जैसे गंभीर जीर्ण रोग शामिल हैं जो आसन्नप्रसवा माता के जीवन को संकट में डाल देते हैं तथा प्रसव में इतनी जटिलताएं पैदा कर देते हैं कि अक्सर डाक्टर स्वयं गर्भस्राव की सिफारिश कर देते हैं। यह सच है कि आजकल ऐसे मामले अधिकाधिक दुर्लभ होते जा रहे हैं। जिन स्त्रियों को विशेष चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता होती है, उनके लिए सोवियत संघ में विशेष आरोग्य केन्द्र और प्रसूतिगृह हैं जिनमें स्त्रियों को प्रसव के लिए तैयार करने के निमित्त कार्यक्रमों की व्यवस्था होती है।

कभी-कभी गर्भपात का निर्णय किसी वस्तुतः गंभीर कारण के बिना ही अकस्मात ले लिया जाता है। इसलिए डाक्टर किसी स्त्री को अस्पताल भेजने के पहले हमेशा उससे पूछताछ करता है, क्योंकि सोवियत संघ में गर्भपात केवल निदानगृहों और अस्पतालों में ही किया जाता है और वह भी उन्हीं परिस्थितियों में जिनमें शल्य-क्रिया की जाती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

६. शिक्षा
और कला

सोवियत नौजवान को
किस प्रकार की शिक्षा मिलती है?

एक माध्यमिक सार्वजनीन दस-वर्षीय शिक्षा प्रणाली १६७६ में लागू की गयी थी जो अब सभी नगरों और ग्रामों दोनों के लिए अनिवार्य हैं। इस बात का चुनाव हर कोई कर सकता है कि वह किस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा संस्था में दाखिल हो—सामान्य शिक्षा के स्कूल में, अथवा व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल में। उन सभी के पाठयक्रम में माध्यमिक स्कूल कार्यक्रम सम्मिलित होता है जिससे इनके स्नातक चाहें तो उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं।

सोवियत संघ में १ जनवरी, १६७७ तक २५.८ करोड़ की आबादी हो गयी। सामान्य शिक्षा स्कूलों में ४.६५ करोड़ की उपस्थिति रही, व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों तथा अन्य विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में क्रमशः १५ लाख और ४६ लाख तथा उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं में ५० लाख रही।

सोवियत इतिहास की सर्वोत्तम शिक्षित पीढ़ी इस समय अपने कार्य-जीवन में प्रवेश कर रही है।

सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा हैसियत का प्रतीक है
या वस्तुगत आवश्यकता ?

एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता।

आर्थिक दृष्टि से वर्तमान वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के लिए, यह न केवल

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आवश्यक है, बल्कि उनकी मांग भी है, क्योंकि जब तक उसकी उपलब्धियों को प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति पर्याप्त शिक्षित न हो, तब तक उनका कारगर उपयोग नहीं हो सकता। यह एक हकीकत है कि माध्यमिक स्कूली शिक्षा वाले कारखाना मजदूर उन लोगों की उपेक्षा नये उपकरणों में पारंगत होने में आधा समय लेते हैं जिन्हें केवल सात वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त होती है।

फिर भी, आज के उत्पादन में पूरी माध्यमिक दसवर्षीय स्कूली शिक्षा से प्राप्त ज्ञान की हर किसी को आवश्यकता नहीं होती, बहुत से लोग इसके बगैर भी अपना कार्य निभा सकते हैं। अतः इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने सार्वभौम माध्यमिक शिक्षा क्यों लागू की?

कार्य का चरित्र तेजी के साथ बदलता जा रहा है तथा ऐसे काम कम होते जा रहे हैं जिनके लिए अपेक्षाकृत निम्न शैक्षिक स्तर अपेक्षित होता है। किसी मजदूर ने जितना सीख रखा है, अगर आज वह अपने काम में इस सबका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है तो कल करेगा।

यही एक मात्र मुद्दा नहीं है। हमने शिक्षा को कभी शुद्ध उपभोक्ता-दृष्टिकोण से नहीं देखा है या यह नहीं माना है कि मनुष्य केवल उत्पादन का एक भागीदार है। हम सामाजिक पहलू को, इस तथ्य को समानतः महत्वपूर्ण मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य के क्षितिजों का विस्तार करती है, उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्रिय बनाती है, प्रबन्ध और प्रशासन में भाग लेने के उसके अवसरों का विस्तार करती है, उसे सही कार्य जीवन के चयन में सहायता पहुँचाती है, तथा कार्य के प्रति सर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। हम व्यक्ति के समस्त विकास के लिए यत्नशील हैं और व्यापक सामान्य शिक्षा के बगैर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

"सामूहिक संस्कृति" के बारे में आप क्या सोचते हैं?

हम "चुनिंदा" और "आम" या जन साधारण" जैसी कोटियों में जनता का विभाजन करने और उसके आधार पर संस्कृति को "आम" या "सामूहिक" और "खास" या "संभ्रांत" में बांटने के विरुद्ध हैं। समाजवादी संस्कृति एक अविकल इकाई है, और इस दृष्टि से यह सचमुच जनता की और जनता के लिए है।

जैसा कि हम देखते हैं, पूंजीवादी समाज में बहुत प्रचलित 'सामूहिक संस्कृति" बाहरी तौर पर तो जनतांत्रिक प्रतीत होती है किंतु सौंदर्यात्मक स्तर पर उसका गंभीर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है, तथा अपनी पिटी-पिटायी कलात्मक

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Va...
Acc. No. ...2283
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रीतियों से वह कला का सारा कार्य मात्र बुद्धिहीन मनोरंजन बनाकर छोड़ देती है।

सारतः "सामूहिक संस्कृति" ऐसी सांस्कृतिक पण्यवस्तु बन गयी है जिसमें हिंसा और मौन तत्व का भारी पुट रहता हो। इस प्रकार की "संस्कृति" न केवल किसी भी व्यक्ति का ध्यान सच्ची कला की सराहना करने तथा समाज के सामने पेश नाजुक सवालों का समाधान खोजने से हटा देती है, बल्कि साथ ही किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध कर देती है।

कला अराजनीतिक क्यों नहीं हो सकती ?

हालांकि कुछ कलाकारों ने राजनीति से "बच निकलने" की कोशिश की है और शायद वे आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक कोई सफल नहीं हो सका है।

कोई कलाकार अलबत्ता अपनी कला को अराजनीतिक समझ सकता है। लेकिन वह भ्रम मात्र है क्योंकि वह जब कभी पाठक, दर्शक या श्रोता से बात करता है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाता है। अगर वह ईमानदारी से भी यह कहता है कि उसे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तो उस समय भी वह राजनीति से जुड़ा होता है, क्योंकि वस्तुगत तौर पर वह उन लोगों के पक्ष में खड़ा होता है जो वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उनके विरुद्ध होता है जो उसे बदलना चाहते हैं।

कला और राजनीति के अंतस्संबंध का हम किस प्रकार आकलन करते है ? लेनिन कलाकार के लिए यह महत्वपूर्ण मानते थे कि वह अपने समय के प्रगतिशील विश्व दृष्टिकोण को आत्मसात करे जिससे मानव में, सामाजिक विषमता और दुर्गुण के उन्मूलन की संभावना में, अच्छाई और सच्चाई की विजय में, क्रांति के महान ध्येय में आस्था उसकी निष्ठा और विश्वास बन जाये। सारतः कला में पक्षधरता के लेनिनवादी सिद्धांत का यही अर्थ है।

पाठक और प्रेक्षक विधेयात्मक चरितनायक से मिलना चाहते हैं जो जीवन में सक्रिय भूमिका अदा करता हो, जो निर्भीकता के साथ उत्तरदायित्व का वहन करता हो, जो स्वयं को इतिहास का निर्माता महसूस करता हो। यह चरितनायक जीवन की, नये यथार्थ की देन है।

आइजेंस्ताइन की फिल्म *युद्धपोत पोत्योम्किन* रूसी क्रांति से संबंधित एक प्रखर राजनीतिक फिल्म है जिसे संसार के अग्रणी अधिकारी लोगों ने "आज तक की

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ग्रौर सभी राष्ट्रों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म" कहा है ग्रौर ग्राज वह लगभग ग्राधी सदी पुरानी हो चुकी है। अथवा शोलोखोव की जाज्वल्यमान गाथा *धीरे बहे दोन रे* को ही लीजिए जो अपने सामाजिक ग्रौर राजनीतिक सामान्यकरणों की शक्ति तथा अपने गूढ़गामी मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से चमत्कृत कर देती है, या मायकोव्स्की के चुनौती से भरे, ग्राग्नेय, प्रचारात्मक काव्य को लीजिए; या दार्शनिक अंतर्वस्तु से सपन्न प्रोकोफिएव ग्रौर शोस्ताकोविच के सुरीले संगीत को लीजिए। वे सबके सब सच्चे अर्थों में नूतनता की सृष्टि करने वाली कला हैं जो अपने ग्रौर अपने इर्द-गिर्द के संसार के सत्य से मानव का साक्षात्कार कराती हैं।

जीवन के प्रति विवेयात्मक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की भावना का जितना उन्नयन करता है, उतना ग्रौर कोई चीज नहीं करती। मानव को इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता देना कला का भी कर्त्तव्य ग्रौर ध्येय है।

समाजवादी यथार्थवाद क्या है ?

समाजवादी यथार्थवाद साहित्य ग्रौर कला की वह सर्जनात्मक पद्धति है जिसका सारतत्व है यथार्थ के क्रांतिकारी विकास के संदर्भ में उसकी ऐतिहासिक दृष्टि से मूर्त व्याख्या प्रस्तुत करना। वह समाजवादी क्रांति, नये समाजवादी समाज की विजय ग्रौर प्रतिष्ठापना, तथा इस समाज में साहित्य ग्रौर कला द्वारा अदा की जाने वाली नयी जीवन-प्रतिष्ठापक भूमिका से सामाजिक संबंधों के ढांचे में जबर्दस्त परिवर्तनों की परिस्थितियों में साहित्य ग्रौर कला की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों की स्वाभाविक अगली कड़ी ग्रौर उसके विकास के रूप में ग्रविर्भूत हुग्रा।

पश्चिम के हमारे अहितचिंतक इस पद्धति की क्रांतिकारी भूमिका के ही कारण इसे स्वीकार करने से इंकार करते हैं तथा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वे मखौल उड़ाते हुए इसे "स्वीकृत" विधाओं ग्रौर विषयों का पंचमेल नमूना तथा लेखकों ग्रौर कलाकारों की कलाई में बंधी "हथकड़ी" करार देते हैं। "समाजवादी यथार्थवाद" की अवधारणा पर कीचड़ उछालने के क्रम में वे इस अवधारणा के पीछे छिपे कला के क्रांतिकारी मिशन को दूषित करने का प्रयास करते हैं।

समाजवादी यथार्थवाद सर्जनात्मक संभावनाओं में बाधा नहीं बनता उल्टे, वह लेखकों ग्रौर कलाकारों के जीवन में, ग्रौर भी सक्रियता ग्रौर गहनता के साथ जुड़ने, अपनी सर्जनात्मक वैयक्तिकता की रक्षा करने में सहायता पहुंचाता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अगर ऐसा न होता तो विश्व कला के उन अग्रणी प्रकाशस्तंभों के उदय की कैसे व्याख्या की जा सकती है जिनके उदाहरण हैं सिनेमा में आइसेंस्ताइन और पुदोव्किन, संगीत में प्रोकोफिएव और शोस्ताकोविच, चित्रकला में देइनेका और सार्यान, नाट्य कला में ओब्राज्त्सोव और तोव्स्तोनोगोव, विविध कला में उत्योसोव और राइकिन तथा बैले में उलानोवा और मोइसेयेव। और इस प्रकार के सैकड़ों और हैं। ये सबके सब ज्वलंत व्यक्तित्व हैं और उनमें से प्रत्येक पश्चिम के किसी भी देश की शोभा बढ़ा सकता है।

इसी में समाजवादी यथार्थवाद की प्रामाणिक शक्ति सन्निहित है।

अवां-गार्द कलाकार अपनी मर्जी से
सृजन कार्य करने को कितने स्वतंत्र हैं ?
क्या वे प्रदर्शनी कर सकते है ?

पश्चिम में जिन्हें अवां-गार्द या अगतानुगतिक (नान-कान्फ़ार्मिस्ट) पुकारा जाता है, उनकी १९७४ से १९७६ के बीच छह प्रदर्शनियां हुईं। शुरू में उनके प्रति जो दिलचस्पी देखने में आयी, वह बाद में स्पष्ट रूप में कम हो गयी। जैसा कि दर्शक पुस्तिका की टिप्पणियों से पता चलता है, प्रदर्शनियों के अधिकांश कलाकार दर्शकों की दृष्टि में "सनसनीखेज यश के भूखे", "ध्यान आकृष्ट करने को लालायित" "कांदिस्की सल्वादोर दाली या चगाल का अमफल और अंध अनुकरण करने वाले" थे। अलबत्ता, अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की गयीं।

इन चित्रकारों में से कुछ में वास्तविक प्रतिभा दिखाई पड़ती है लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनमें से स्वयं अपनी शैली और शिक्षा की खोज में लगे कलाकार हैं दिमत्री प्लाविंस्की, व्लादीमिर नेमुखिन, व्याचेस्लाव कालिनिन, दिमत्री क्रास्नोपेव्त्सेव, अलेक्सांदर खारितोनोव और निकोलाइ वेचेतोमोव, जिनमें से प्रत्येक की स्वयं अपनी पद्धति है। इनकी कुछ कृतियों को सोवियत संघ के संस्कृति मंत्रालय ने खरीदा है।

सोवियत कला में स्तर की परिभाषा कौन
करता है और यह कैसे किया जाता है ?

कलात्मक सर्जनात्मकता को शामिल करने या किसी एक कलाकार या लेखक की कृति को निकष के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास मे साहित्य या कला के विकास

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। बाल्ज़ाक को स्वीकार और स्टेंड्हाल को अस्वीकार कर देना, मायकोव्स्की की तारीफ करना और ब्लोक को नजरअंदाज कर देना गलत है। बल्कि यह संभव और वांछनीय है कि साहित्य और कला की सर्वश्रेष्ठ कृतियों की टोह रखी जाये और यह पता करने की कोशिश की जाये कि उसकी श्रेष्ठता के क्या कारण हैं।

इस देश में साहित्य और कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियों के लिए सालाना लेनिन और राज्य पुरस्कार दिये जाते हैं। इन रचनाओं को समाजवादी यथार्थवाद की कला का नमूना माना जा सकता है। उन्हें सृजन-कर्मियों के व्यावसायिक संघ, अर्थात लेखकों, वास्तुकारों, या संगीतकारों की यूनियनें, विविध प्रकाशनगृहों के संपादकमंडल, नाट्य संस्थाएं या प्रकाशनगृहों और पुस्तकालयों के कर्मीदल जमा करते हैं। उसके बाद उन रचनाओं पर समाचारपत्रों में बहस चलती है जिसमें जनता भी सक्रिय रूप में भाग लेती है। लेनिन और राज्य पुरस्कार समितियों को विविध रचनाओं के गुणों की चर्चा करते हुए हजारों पत्र मिलते हैं। समिति के सदस्य, जो विश्रुत लेखक और कलाकार होते हैं, सारे सुझावों पर विचार-विमर्श करने और स्वयं अपनी राय बनाने के बाद पुरस्कारों के लिए सुयोग्यतम प्रत्याशियों को चुनते हैं। किंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं कि पुरस्कार-जयी कृतियां ऐसा मानदंड प्रस्तुत करती हैं जिनका अनुसरण करना आवश्यक हो।

आर्थिक दृष्टि से सोवियत कलाकार की क्या स्थिति होती है?

पेशेवर कलाकार अपनी कलाकृतियों से आजीविका चलाता है। इसके लिए वह अपने चित्र संग्रहालयों और कला वीथिकाओं को बेचता है, या कारखानों और कार्यालयों के लिए कार्य करता है। उसकी आमदनी सोवियत कला कोष पर भी निर्भर होती है जिसके लाभार्जन करने वाले १६० उद्यमों में २६,००० से अधिक कलाकार कार्य करते हैं।

अपने प्रभावशाली वित्तीय संसाधनों की बदौलत कला कोष वित्तीय सहायता के जरूरतमंद सदस्यों को सहायता दे सकने तथा जब कभी वे अस्थायी तौर पर कार्य करने में अक्षम हों तो उन्हें स्थायी ऋण दे सकने की स्थिति में है। वृद्धों और कलाकारों की विधवाओं को भी इसी प्रकार के ऋण दिये जाते हैं, कला कोष स्टूडियो के निर्माण, आवास सहकारों, विशेष जयंती समारोहों के आयोजन आदि के लिए बिना ब्याज के ऋण देता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कला कोष ने कलाकार संघ के सदस्यों के विश्राम और कार्य के लिए सारी सुविधाओं से सम्पन्न ग्यारह केन्द्र बना रखे हैं। संघ के सदस्य आवास और खानपान, चिकित्सा, स्टुडियो स्थल और कलाकारों की आवश्यक सामग्रियों समेत दो मास वहां टिकने के लिए अधिकृत हैं। यात्रा व्यय भी चुकता किया जाता है। कलाकार अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी ले जा सकते है।

कला कोष प्रदर्शनियों, कलाकृतियों की खरीद, प्रदर्शनी कक्षों के निर्माण तथा सौंपे गये कार्य के लिए पृष्ठभूमि सामग्री के संचय के लिए यात्राओं के व्यय में सहायतार्थ बड़ी राशियां आवंटित करता ह। और अंत में, कला कोष १२० कक्षों के एक तानें-बाने और एक ऐसे विशेष निर्माण कक्ष के जरिए जो विदेशी ग्राहकों को सोवियत कलाकारों की कृतियों की बिक्री करने वाला देश का एक मात्र वितरक है, चित्रकारों मूर्तिकारों, ग्राफिक कलाकारों तथा प्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में काम करने वाले शिल्पियों की कृतियों की बिक्री आयोजित करता है।

क्या कोई सोवियत कवि अपनी कविता मात्र से आजीविका चला सकता है?

जी हां। कविता के लिए पंक्ति हिसाब से ०.७ से २ रूबल (०.९३ से २.७ अमरीकी डालर) भुगतान किया जाता हैं। दर किसी रचना के गुण, प्रतिभा और कवि की ख्याति पर निर्भर होती है।

किसी भी काव्य-पुस्तक का संस्करण आमतौर पर १०,००० प्रतियों का होता हैं। लेकिन अगर संस्करण इससे अधिक प्रतियों का हो तो लेखक को दूसरे संस्करण के बतौर अतिरिक्त राशि दी जायेगी। जैसे अगर संस्करण ५०,००० प्रतियों का हो जो प्रसंगवश बता दिया जाये कि आम बात है, तो रचनाकार को दूसरी १०,००० प्रतियों के लिए पूरी दर का ६० प्रतिशत, तीसरी १०,००० प्रतियों के लिए और भी ६० प्रतिशत, चौथी १०,००० प्रतियों के लिए ४० प्रतिशत तथा पांचवीं १०,००० प्रतियों के लिए ३५ प्रतिशत मिलेगा।

अगर संस्करण सामान्य १०,००० प्रतियों से कम का हो जैसाकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की भाषाओं की कविता के साथ होता है तो भी लेखक को १०,००० प्रति के संस्करण की ही दर से भुगतान किया जायेगा।

जब तक किसी कवि की एक संग्रह के लिए पर्याप्त कविताएं न हो जायें, तब तक वह आमतौर पर उन्हें किसी पत्रिका या समाचारपत्र में अलग-अलग या एक

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

श्रृंखला में प्रकाशित करवाता है जिसके लिए उसे पंक्ति के हिसाब से भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर कोई कवि बीमार पड़ जाये तो क्या होता है ? सोवियत लेखक संघ के पास एक साहित्यिक कोष है—बहुत कुछ कलाकार संघ के कला कोष की ही भांति—जिसकी मर्जी पर करोड़ों रूबल होते हैं। प्रकाशनगृहों के लाभों में से कटौतियां करके इस राशि की लगातार पूर्ति की जाती रहती है। ये संसाधन ही किसी लेखक या कवि को अस्थायी या स्थायी ऋण देते हैं।

साहित्यिक कोष के पास लेखक संघ और साहित्यिक कोष के सदस्यों के विश्राम और कार्य के लिए १७ केन्द्र तथा शहरों के बाहर दर्जनों अतिथिगृह हैं जहां निःशुल्क या ५० प्रतिशत छूट पर रहने की व्यवस्था की जाती है। लेखक या कवि को साल भर में वहां रहने के दो वाउचर का अधिकार होता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

७. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

निरस्त्रीकरण की समस्या के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ?

हम प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में सार्वभौम और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए दीर्घकाल से दृढ़तापूर्वक लड़ते रहे हैं। हम इसे शांति और जनगण की सुरक्षा की चिरस्थाई गारंटी मानते हैं और अन्य तमाम बातों के अलावा इससे अपार धन की बचत होगी जिसे उपयोग में लाकर मानवजाति लाभान्वित हो सकती है।

किंतु हम इसे "सब कुछ या कुछ भी नहीं" का प्रस्ताव बनाने का आग्रह कतई नहीं करते। सोवियत संघ हथियारों की होड़ को सीमित और समाप्त करने तथा शस्त्रास्त्रों में कटौती करने क लिए लाभकारी हर कदम के लिए समान दृढ़-निष्ठता से आह्वान करता है। अलबत्ता, ऐसे कदमों से एक पक्ष को दूसरे की कीमत पर लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिए। यह एक तथ्य है कि पिछले १०-१५ वर्षों में इस क्षेत्र में हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते सोवियत पहलकदमी का परिणाम रहे हैं।

हाल में सोवियत संघ ने इस क्षेत्र में नयी महत्वपूर्ण पहलकदमियों का एक पूरा-का-पूरा सिलसिला पेश किया है। हमने सुझाया कि रणनीतिक आक्रमणास्त्रों के परिसीमन के संबंध में एक नये समझौते के लिए प्रयासों में तेजी लायी जानी चाहिए। और हालांकि जैसाकि अमरीकी विदेश मंत्री सायरस वांस के साथ मार्च १९७७ में मास्को की वार्ता में हुआ, नये अमरीकी प्रशासन द्वारा अपनायी गयी स्थिति एकदम रचनात्मक न थी, फिर भी सोवियत संघ का यही विचार है कि दोनों पक्षों को सकारात्मक परिणामों के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हथियारों की होड़ को रोकना परम आवश्यक है। हमने सैनिक बजटों में कटौती का अपना प्रस्ताव दुहराया है। हम रासायनिक हथियारों की मनाही और उन्हें नष्ट किये

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जाने के लिए तथा सामूहिक विनाश के अस्त्रों के नये प्रकारों और प्रणालियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए यत्नशील हैं; हमारा प्रस्ताव है कि समस्त नाभिकीय अस्त्र-परीक्षणों की पूर्ण और सार्वभौम मनाही के संबंध में तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल-प्रयोग के परित्याग के लिए एक विश्व संधि करने के संबंध में समझौता कर लिया जाना चाहिए। हम मध्य यूरोप में सशस्त्र सेनाओं और शस्त्रास्त्रों में कटौती के लिए यत्नशील हैं, तथा वारसा संधि के अपने साझीदारों के साथ मिलकर यूरोपीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों से अपील करते हैं कि वे एक समझौता करके इस बात के लिए प्रतिश्रुत हों कि एक-दूसरे के खिलाफ़ नाभिकीय अस्त्र के प्रयोग में वे प्रथम नहीं रहेंगे।

यह एक व्यापक और विशिष्ट कार्यक्रम है। सोवियत संघ द्वारा सुझाये गये उपाय सार्वभौम और पूर्ण निरस्त्रीकरण का स्थान वाकई नहीं ले सकते किंतु इसके फलीभूत होने के लिए वे बेहतर परिस्थितियां अवश्य निर्मित करते हैं।

पश्चिम में यह दावा करते हुए बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि सोवियत नागरिक प्रतिरक्षा प्रणाली "रणनीतिक शक्ति-संतुलन को अस्त-व्यस्त कर के" शांति के लिए खतरा पैदा कर रही है। क्या यह शिकायत जायज है?

नहीं, इसमें कोई सार नहीं। हमारी नागरिक प्रतिरक्षा सेवा ने न तो किसी के लिए खतरा पैदा किया है, न कर सकती है। इसके उद्देश्य हैं: युद्ध की दशा में आबादी की रक्षा करना, युद्ध के समय आर्थिक सुस्थिरता की व्यवस्था करना, तथा किसी आक्रमणकारी के हमले से हुई क्षति से निबटना।

कुछ अमरीकी लेखक यह आरोप लगाते हैं कि खास तौर पर १९७२ के मध्य से हमारे नागरिक प्रतिरक्षा संगठन को बहुत सुदृढ़ किया गया है। इस विचार के लिए प्रेरणा निश्चय ही इस बात से मिली है कि १९७२ में सूखे के लंबे दौर के बाद कई इलाकों में गंभीर दावाग्नि फैल गयी थी। कई स्थानों में उससे आबाद क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो गया था। ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों के लिए आपातिक उपाय जरूरी हैं, और फलतः अग्नि-शमन के लिए आबादी से सहायता प्राप्त करना और जनता को संगठित करना आवश्यक हो जाता है। नागरिक प्रतिरक्षा संगठन का उपयोग विराट दावाग्नि को काबू में लाने और बाद में सफ़ाई की कार्रवाइयां पूरी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

करने के लिए किया गया। प्राकृतिक विपत्ति का मुकाबला करने के लिए नागरिक प्रतिरक्षा के ऐसे "सुदृढ़ीकरण" से सचमुच किसी के लिए कोई खतरा नहीं पैदा होता।

हमारे नागरिक प्रतिरक्षा के संगठन तथा संभावित हवाई हमले से जनसंख्या की रक्षा करने की विधियों और प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला करने की विधियों में निरंतर सुधार लाया जा रहा है। प्रेक्षपास्त्र-निरोधी प्रतिरक्षा के संबंध में सोवियत-अमरीकी समझौते के समय भी यह बात विदित थी। इससे उस समझौते के हस्ताक्षरित किये जाने में कोई बाधा न पड़ी और १९७६ तक, जब तक अमरीका में कई वर्ष आगे तक के अमरीकी सैनिक बजट के सिलसिले में संघर्ष नहीं छिड़ा था, इसे लेकर कोई चिंता भी नहीं पैदा हुई। हम जानते हैं कि अमरीका विशाल नागरिक प्रतिरक्षा कार्यक्रमों में लगा है, लेकिन हमने यह कभी दावा नहीं किया कि इसमे शांति और अन्य जनगण की सुरक्षा के लिए खतरा है तथा हथियारों की होड़ के समाप्त किये जाने के खिलाफ या सार्वभौम निरस्त्रीकरण के खिलाफ दलील के रूप में इसका इस्तेमाल करने की कभी कोशिश नहीं की।

क्या सोवियत संघ कबूल करता है कि पश्चिम के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान में वह अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है ?

वह ऐसी बात कैसे कबूल कर सकता है जबकि स्थिति इससे बिलकुल उल्टी है।

सोवियत संघ से पश्चिमी देश जितने प्रकाशन खरीदते हैं, उससे कई गुने का वह उनसे नियमित रूप में आयात करता है। १९७५ में हमने पश्चिमी देशों से कुल ६२,८९,००० रूबल के प्रकाशनों का आयात किया, जबकि सोवियत संघ से इन देशों को प्रकाशनों का निर्यात २६,४४,००० रूबल का रहा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रकाशनों के विनिमय के संबंध में १९७५ के लिए निम्नलिखित सरकारी आंकड़े (हजार रूबलों में) अपने ढंग का नमूना पेश कर देते हैं :

देश	सोवियत संघ से निर्यात	सोवियत संघ द्वारा आयात
अमरीका	६८१	१९५५
ब्रिटेन	२१०	११९१
फ्रांस	३७०	९७२
जर्मन संघ गणराज्य	३४४	५९६
स्विट्जरलैंड	३५	१८१
आस्ट्रिया	४४	९६
हालैंड	८४	४३१

सोवियत संगठनों और पुस्तकों की दुकानों की ओर से अखिल-संघीय संगठन "मेझ्दुनारोद्नाया क्नीगा" हर साल २०,००० से अधिक विभिन्न पत्रिकाओं और ७०,००० पुस्तकों की खरीद करता है। विदेशी प्रकाशनों के क्रयादेश देते समय हम मौलिक कृतियों को तरजीह देते हैं जो विज्ञान, प्रविधि, साहित्य और कला के क्षेत्रों में विभिन्न देशों की उपलब्धियों को यथासंभव पूर्ण से पूर्ण रूप में प्रतिबिंबित करती हैं।

सोवियत संघ विदेशों से आयातित प्रकाशनों का दायरा लगातार विस्तृत करता जा रहा है। १९७६ से आरंभ कर के उसने फुटकर व्यापार के लिए और भी एक दर्जन पश्चिमी समाचारपत्र खरीदे जिनमें *दि फिनेंशियल टाइम्स*, *फ्रैंकफुर्टर अल्गेमिएन डाइ प्रेसे*, *ले प्यूप्ल्*, *हेल्सिंगिन सान्नमात*, *लेस इकोस*, *ल' यूनिते*, *डागेन्स निहेटेर*, और *माइनिच शिम्बुन* शामिल हैं।

यह खेद की बात है कि हेल्सिंकी सम्मेलन के बाद भी पश्चिम के साथ सूचना विनिमय संबंधी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। "मेझ्दुनारोद्नाया क्नीगा" अभी भी कुछ ऐसे खास पश्चिमी प्रकाशनों को नहीं खरीद सकता "जिन्हें लौह आवरण के देशों में नहीं भेजा जाता"। *यू. एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट* और *टाइम इंटरनेशनल* जैसे अमरीकी राजनीतिक साप्ताहिकों के लिए सोवियत क्रयादेशों पर हमेशा मांग से कम सप्लाई की जाती है।

पश्चिमी प्रकाशनों की भारी कीमतें सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के विस्तार में एक भीषण बाधा उपस्थित करती हैं। उदाहरण के लिए विमान सेवा से *न्यूयार्क टाइम्स* की सप्लाई के लिए सालाना चंदा २,९८२

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

डालर होता है जिससे वह व्यवहारतः पहुंच के बाहर हो जाता है। साधारण डाक से (२२० डालर) *न्यूयार्क टाइम्स* एक महीने बाद सोवियत संघ पहुंचता है जिससे समाचार की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। उल्लेखनीय है कि किसी भी पश्चिमी देश में *प्रावदा* और *इज्वेस्तिया* का सालाना चंदा क्रमशः १४·४० और १२ डालर होता है, तथा लोकप्रिय सोवियत साप्ताहिकों *लितरेतुर्नाया गजेता* (साहित्यिक गजट) और *ज़ा रुबेझोम* (विदेश) का क्रमशः १४·४० और १८ डालर।

सोवियत संघ की तुलना में पश्चिम में पुस्तकें भी कहीं ज्यादा महंगी है।

सोवियत संघ में १९४६ और १९७२ के बीच अमरीकी लेखकों की ६,००० से अधिक कृतियां, फ्रेंच लेखकों की तकरीबन ६,००० कृतियां ब्रिटिश लेखकों की ४,००० कृतियां और इटालियन लेखकों की लगभग १,००० कृतियां प्रकाशित हुईं।

इसी अवधि में अमरीका और ब्रिटेन में सोवियत लेखकों की पांच-पांच सौ कृतियां, फ्रांस में ६०० और इटली में ४०० प्रकाशित हुईं। साथ ही उनके संस्करण विदेशी लेखकों के सोवियत संस्करणों से कहीं अधिक छोटे थे।

सिनेमा और थियेटर के क्षेत्र में भी सोवियत संघ पर अनिच्छा का आरोप नहीं लगाया जा सकता। १९६६ और १९७५ के बीच हमने २१ अमरीकी फिल्में खरीदीं जिनका व्यापक रूप में वितरण किया गया। इसी अवधि में अमरीकियों ने २५ सोवियत फिल्में खरीदीं लेकिन उनमें से कुछेक को ही प्रदर्शित किया।

सोवियत थियेटर अमरीकी लेखकों के ३५ नाटक प्रस्तुत कर चुके जबकि अमरीका में दो सोवियत नाटक प्रस्तुत किये गये। हम १४ ब्रिटिश, २१ फ्रेंच और १५ इटालियन नाटक भी मंचित कर चुके। ब्रिटेन में थियेटर प्रेमी केवल एक सोवियत नाटककार अलेक्सेइ अर्बुज़ोव से परिचित हैं। फ्रांस और इटली में सोवियत नाटक को बिलकुल प्रतिनिधित्व ही प्राप्त नही है।

यह है आपके सामने सच्ची स्थिति।

क्या सोवियत संघ पश्चिमी प्रविधि और उपकरणों के बगैर काम चला सकता है?

अंतरिक्ष के क्षेत्र की हमारी उपलब्धियां ही इस सवाल का जवाब देने को पर्याप्त हैं।

पिछले पंचवर्षीय काल (१९७१-७५) में सोवियत संघ ने २९ अरब रूबल (मोटे तौर पर ३८ अरब डालर) की मशीनों, उपकरणों और यातायात साधनों का

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आयात किया । १९७४-७५ के वर्षों में समाजवादी देशों से इन वस्तुओं के आयात का मूल्य ९·५ अरब डालर से अधिक रहा तथा पूंजीवादी देशों से ५.६ अरब डालर के आस पास। आमतौर पर सोवियत संघ के आयात का परिमाण अन्य उद्योगीकृत देशों के आयात के परिमाण से कम रहता है और जैसा कि ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है, इन आयातों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा पूंजीवादी देशों से होता है। पूंजीवादी देशों से सोवियत संघ का आयात कुल सोवियत राष्ट्रीय उत्पाद के १·५ प्रतिशत से कम होता है।

सोवियत संघ की योजना १९७६-८० की अवधि में समाजवादी देशों के साथ व्यापार प्रतिशत बढ़ाने की है। दूसरे शब्दों में, १९८० तक आशा की जाती है कि अमरीका, कनाडा पश्चिमी यूरोप और जापान के साथ व्यापार संभवतः लगभग २० अरब रूबल होगा। आयात संभवत: इसकी लगभग आधी राशि अर्थात १० अरब के होंगे जिसमें ३-४ अरब रूबल की मशीनरी का आयात शामिल है जो सोवियत संघ के वर्तमान पंचवर्षीय काल में पूंजीगत निवेश की राशि को, जो ६२१ अरब रूबल होगी, तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को देखते हुए जो ९१ अरब रूबल होगी, बड़ी रकम नहीं है।

एक और भी बात उल्लेखनीय है। पश्चिमी इजारेदारियां सोवियत क्रया देशों के लिए होड़ कर रही हैं तथा सोवियत उपकरणों और विशेषज्ञता का अधिकाधिक उपयोग कर रही हैं। वे इसे लाभकारी पाती है। किंतु सोवियत संघ के साथ आर्थिक सम्बन्धों से कोई तभी लाभान्वित हो सकता है जबकि ये संबंध सोवियत संघ के लिए भी लाभकारी हों।

सोवियत संघ की प्राविधिक क्षमताएं और उपलब्धियां ऐसी हैं कि वह स्वतः क्षिप्र गति से आगे बढ़ते रहने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरी ओर कभी-कभी आवश्यकता की किसी चीज को बनाने से ज्यादा सस्ता उसे खरीद लेना होता है। अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन से लाभ न उठाएं तो हमारे लिए यह मूर्खता होगी।

सोवियत-अमरीकी व्यापार में
कौन-सी चीज बाधक बन रही है।

जवाब बहुत ही सीधा-सादा है—सोवियत माल के प्रति अमरीका द्वारा टैरिफ में भेदभाव।

अमरीका में विदेशी पूंजीगत मालों पर लगायी गयी औसत चुंगी उनके मूल्य का ४.८ प्रतिशत होती है, किंतु उसी के समतुल्य सोवियत माल का ३८ प्रति-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शत होती है। विद्युत उपकरणों, के मामलों में यह क्रमशः ९.७ और ४२ प्रतिशत और परिवहन साधनों के मामले में ५.२ और ३० प्रतिशत है।

इस घोर भेदभाव को समाप्त करने के लिए अर्थात सोवियत संघ को भी व्यापार की वही शर्तें प्रदान करने के लिए जो १४० अन्य देशों के साथ लागू हैं, १९७२ में ही समझौता हो गया था, किंतु अमरीकी पक्ष उसे अभी भी लागू नहीं कर रहा है।

इसके अलावा सोवियत संघ को अमरीकी मालों के निर्यात पर *प्रशासनिक बंदिशें* भी थोप रखी गयी हैं। बहुत-सी वस्तुएं अमरीकी अधिकारियों द्वारा जारी किये गये पृथक निर्यात लाइसेंस के तहत ही बेची जा सकती हैं। और ऐसे निर्यातों पर लागू होने वाले विनियम इतने अस्पष्ट है कि निर्यातकर्ता को पहले यह पता ही नहीं चल पाता कि उसे लाइसेंस दिया जायेगा या नहीं। इससे अंतहीन विलंब होता है। उदाहरणार्थ, १९७३ में सोवियत "इनटूरिस्ट" संगठन ने आइबीएम से अपने होटलों के लिए स्वचालित नियंत्रण-उपकरणों के लिए एक करार किया। इसके लिए लाइसेंस के जारी किए जाने में तीन साल से अधिक समय लग गया।

या एक अन्य उदाहरण लीजिए। सोवियत संघ ने अमरीकियों से यह प्रस्ताव किया कि दोनों पक्ष ऐसे मालों के स्वरूप के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करें जिन्हें किन्हीं कारणों से दो में से एक भी देश दूसरे को नहीं बेचना चाहता। इसका उद्देश्य था संदिग्धता और आपसी समझदारी की कमी को समाप्त कर देना। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

सोवियत-अमरीकी व्यापार के बढ़ने में एक और अड़चन है अमरीकी कांग्रेस द्वारा थोपी गयी *ऋण संबंधी पाबंदियां* जिनसे सोवियत संघ को अमरीकी निर्यात की संभावना सीमित हो जाती है। फलतः अमरीकी कंपनियां प्रतियोगिता में टिक नहीं पातीं और ऐसे सोवियत क्रयादेशों से हाथ धो बैठती हैं जिन्हें अन्यथा वे प्राप्त कर सकती थीं।

सोवियत पक्ष से अमरीका के साथ व्यापार के विकास में कोई रुकावट नहीं है।

पश्चिमी देशों से सोवियत आयातों का क्या स्वरूप है?

हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि सोवियत संघ पश्चिम से मशीनरी, उपकरण और यातायात के साधन खरीदता है। ये माल कुल निर्यात के एक-तिहाई से कुछ

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अधिक होते हैं । आयात का एक खासा बड़ा हिस्सा (मोटे तौर पर ४० प्रतिशत) लौह धातुओं, लौह धातुओं की चद्दरों और पाइपों का होता है । पश्चिम से की जाने वाली शेष सोवियत खरीद में उपभोक्ता वस्तुएं और उनसे उत्पादन के लिए कच्चे माल, खाद्य पदार्थ और अनाज शामिल होते हैं ।

सोवियत संघ पश्चिम को तेल, गैस और अन्य कच्चे मालों के अतिरिक्त किस चीज की पेशकश कर सकता है ?

विदेशी साझीदारों ने १६७१-७५ की अवधि में सोवियत संघ से ११,५०,००० मोटर कारें, १,७०,००० ट्रैक्टर, ८,५०० बुलडोजर, ७२,००० धातु कटाई मशीनी औजार, १३,००० एक्सकैवेटर तथा ऐसी ही अन्य चीजें खरीदीं । परमाणु बिजलीघरों के उपकरणों, इलेक्ट्रानिक यंत्रों, विमानों और विमानन उपकरणों, हायड्रोफायल जहाजों तथा कार्यक्रम-नियन्त्रित मशीनी औजारों का अधिकाधिक मात्रा में निर्यात हो रहा है ।

सोवियत मशीनरी और उपकरणों का निर्यात १६७० में २.५ अरब रूबल (३.२५ अरब डालर) का और १६७५ में ४.५ अरब रूबल (लगभग ६ अरब डालर) का था ।

सोवियत संघ में निर्मित बिजली के मोटर जर्मन संघ गणराज्य, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया, डेनमार्क और अन्य अनेक देशों ने खरीदे हैं । रेलों की संपर्क-झलाई की सोवियत मशीनों का अमरीका, जापान, इटली, आस्ट्रिया और ग्रीस में उपयोग किया जा रहा है । उद्योगीकृत पूंजीवादी देश विद्युत-स्लैग झलाई की सोवियत प्रविधि का उपयोग करते हैं । ऐसी मशीनें फ्रांस, स्वेडन और जापान अर्थात ऐसे देशों को बेची जा चुकी हैं जो विश्व में धातुकर्म के क्षेत्र में अगली पांत में है ।

फ्रेंच फर्मों ने सोवियत वात-प्रोसेसिंग उपकरण खरीदे हैं, इटली और फिनलैंड ने स्थिर वायु-कंप्रेसर और वस्त्र उद्योग के उपकरण, तथा ब्रिटेन और जर्मन संघ गणराज्य ने छपाई के और रासायनिक संयंत्र खरीदे हैं ।

आज ८० से अधिक देशों के खेतों और निर्माण स्थलों में लगभग ४,००,००० सोवियत ट्रैक्टर, ७०,००० अनाज हार्वेस्टर कंबाइन और ४०,००० से अधिक सड़क-निर्माण मशीनें काम करते देखी जा सकती हैं । स्वेडन के किसान सोवियत ट्रैक्टरों से बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि ये मजबूत और चीमड़ होते हैं, इनकी डिजाइन सरल और सुविधाजनक होती है तथा शून्य से भी कम तापमानों में आसानी से चालू हो जाता है । कनाडा और अन्य देशों में भी उनकी प्रशंसा होती है ।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एबरहार्ड हीश्श कंपनी (जर्मन संघ गणराज्य) सोवियत लाइसेंस के तहत निर्मित फिल्टर प्रेसों की अनेक देशों में बिक्री करती है। जर्मन संघ गणराज्य के अनेक मशीन-निर्माण संयंत्र सोवियत लाइसेंस के ही तहत अति कठोर इस्पात पर काम करने के लिए अति कठोर कटाई औजारों का इस्तेमाल करते है।

धमन भट्टियों के वाष्प-प्रशीतन की सोवियत प्रविधि का जर्मन संघ गणराज्य और दस अन्य देशों में प्रयोग होता है।

संक्षेप में, पश्चिम को सोवियत संयंत्रों, उपकरणों और प्रविधि की खरीद के लिए सुलभ अवसरों के प्रमाणों की कोई कमी नहीं है।

तब आखिर इन संभावनाओं का और भी पूर्ण रूप में उपयोग क्यों नहीं होता? विश्व के औद्योगिक उत्पादन में एक-पांचवें की भागीदार संसार की दूसरी औद्योगिक शक्ति को पश्चिमी प्राविधिक मंडियों में अभी भी बहुत ही कम प्रतिनिधित्व क्यों प्राप्त है?

कुछ वस्तुगत बातें अवश्य हैं जैसे बाजार में इन वस्तुओं की प्रचुरता, कठोर प्रतियोगिता और परंपरागत सप्लाईकर्ताओं के प्रति वफादारी जिनमें अक्सर सोवियत संघ शामिल नहीं होता।

फिर भी उल्लेखनीय है कि सोवियत मशीनों और अन्य मालों की क्वालिटी को घटिया बताने और उन्हें प्रतियोगिता में अक्षम घोषित करने के साथ-साथ पश्चिम भेदभावपूर्ण किस्म के अतिरिक्त बाधाएं भी खड़ी करता है। सीधे-सादे तर्क से उसका स्पष्टतः कोई मेल नही बैठता। अगर कोई पूंजीवादी कंपनी किसी चीज को खरीदना न चाहती हो तो उसे खरीदने को कौन मजबूर कर सकता है? कोई नहीं। तब ब्रिटेन को सोवियत रंगीन टेलिविजन सेटों के निर्यात पर बंदिश क्यों लगायी जाये और रेडियोग्रामों के लिए आयात कोटे क्यों निर्धारित किये जायें? अमरीका को किये जाने वाले सोवियत निर्यातों पर अतिरिक्त चुंगी क्यों लगायी जाये?

जाहिर है, ऐसे कदमों से उद्योगीकृत पूंजीवादी देशों को सोवियत पक्के मालों के निर्यात में रुकावट होती है तथा साथ ही सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी मशीनरी और उपकरणों की पारस्परिक खरीद कम हो जाती हैं। सोवियत संघ इन भेदभावपूर्ण व्यवहारों के कारण जो कुछ पश्चिम को नहीं बेच पाता, उसका स्वदेश में सफलतापूर्वक उपयोग हो जाता है। लेकिन साथ ही सोवियत क्रयादेशों से हाथ धोकर पश्चिमी निर्यात कंपनियां ही नुकसान में रहती हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ अपना विदेश व्यापार क्यों पश्चिम की छोटी कंपनियों की उपेक्षा करके मुख्यतः बड़ी कंपनियों के साथ चलाता है ?

सोवियत क्रयादेश पाने में ऊंची क्वालिटी और प्रतियोगी कीमतें महत्व रखती हैं। जो कोई सबसे अच्छे मालों और शर्तों की पेशकश करेगा, उसी के पक्ष में फैसला लिया जायेगा। हमारे लिए न तो किसी कंपनी का आकार और न राष्ट्र का निर्णायक महत्व है।

फिर भी पश्चिम में यह आरोप प्रचारित किया जाता है कि हमारा देश बड़े से बड़े निगमों के साथ ही कारोबार को तरजीह देता है। उन बड़ी सोवियत परियोजनाओं का हवाला दिया जाता है जिनमें पश्चिमी कंपनियों ने साझीदारी की है या वे साझीदारी कर रही हैं—जैसे तोग्लियाती और नाबेरेझन्ये में मोटर कारखानों, पाइपलाइनों, कुछ खनिज उर्वरक संयंत्रों आदि का निर्माण।

अलबत्ता कुछ मामलों में हर कंपनी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। इसीलिए फिएट जैसे बड़े साझीदारों का चुनाव किया जाता है। लेकिन इन परियोजनाओं में अनेक छोटी कंपनियों ने भाग लिया है या ले रही हैं बशर्ते ऐसा कर सकना उनकी क्षमता में हो। कुछ मामलों में वे सबसे प्रमुख भूमिका भी अदा करती हैं।

पश्चिम के साथ अपने आर्थिक संबंधों में सोवियत संघ ने व्यापार में घाटा कैसे जुटा लिया ?

पश्चिम के साथ व्यापार में १९७५ में ३·६ अरब रूबल का घाटा था। अंशतः इसका कारण यह था कि सोवियत संघ ने भयंकर सूखे और उससे फसल के चौपट हो जाने के कारण बड़ी मात्रा में गल्ले की खरीद की।

किंतु १९७६ में ही यह घाटा काफी कम हो चुका था। यहां हम तुलना के लिए यह लक्षित कर सकते हैं कि १९७४ में अमरीका के पास ९·९ अरब डालर का व्यापार का घाटा था और जापान के पास ६·५ अरब डालर का।

स्मरणीय है कि हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों ने स्वयं अपने निर्यातों में वृद्धि करने के लिए तथा अपनी जरूरत की वस्तुओं की भावी सप्लाई के लिए ऋण की विशाल रकमें मंजूर की हैं। खासतौर पर बड़े पैमाने के प्रतिपूर्ति के सौदों के मामले में ऋण संबंधी बंदोबस्तों का पूरा निचोड़ यही है। उल्लेखनीय है कि मुख्य ऋण

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दाताओं (फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और कनाडा) के संदर्भ में सोवियत व्यापारिक घाटा स्वयं ऋण की रकमों से काफी कम है और उसे "सर चकरा देने वाला", "अप्रत्याशित" या "गलत फहमियां पैदा करने वाला" नहीं माना जा सकता, जैसा कि पश्चिमी समाचार माध्यम कहते हैं।

जाहिर है, किसी देश के व्यापार संतुलन पर जो विचार किया जाये, उसे आम आर्थिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। अन्यथा १९७५ के वर्ष को जो पश्चिम में उत्पादन में महान मंदी का निम्नतम बिंदु था और जिसके साथ मन्दी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी भी जुड़ी थी, सबसे अनुकूल वर्ष कहा जा सकता है। क्योंकि जहां १९७४ में पश्चिम का कुल घाटा २७ अरब डालर का था, वहीं १९७५ का साल ६.७ अरब डालर लाभ के साथ समाप्त हुआ।

उद्योगीकृत देशों ने मांग गिर जाने पर स्वयं अपने उत्पादन की रक्षा करने के लिए आयात में कटौती कर के अपनी कठिनाइयों का उपशमन कर लिया। अर्थात उन्होंने दूसरों को मंदी का मुख्य भार ढोने को मजबूर कर देने की कोशिश की।

सोवियत अर्थतंत्र संकट और मंदी से मुक्त होने के नाते आयात में कटौती करने को मजबूर नहीं होता। बाजार में माल के किसी तरह की भरमार से या "अतिरिक्त" उत्पादन क्षमताओं के प्रकट हो जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं।

सोवियत संघ को जो ऋण दिये जाते हैं उनसे इस देश को पश्चिम से किये जाने वाले निर्यात को बढ़ावा मिला है और इसलिए सोवियत संघ और पश्चिम के बीच व्यापार के इस पक्ष को लाभ पहुँचता है। जहां तक किसी देश के व्यापार में घाटे का सवाल है, उसमें आयात से कटौती करके या निर्यात बढ़ा कर ही कमी लायी जा सकती है।

अमरीका ने १९७६ के पूर्वार्ध में सोवियत संघ को १२१ करोड़ रूबल का माल बेचा जबकि उसने खरीद केवल ८.९ करोड़ रूबल की की। बेल्जियम ने हमसे इसकी दुगुनी और ब्रिटेन ने पांच गुनी खरीद की। इस प्रकटतः असामान्य वस्तुस्थिति का कारण यह नहीं है कि सोवियत संघ के पास बेचने को कुछ नहीं है, बल्कि यह कि सोवियत संघ से किये जाने वाले चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर भेदभावपूर्ण बंदियां लगा रखी गयी हैं।

सोवियत संघ और अमरीका के बीच व्यापार में परस्पर लाभकारी सहयोग का और आगे विकास बहुत अंशों में इस बात पर निर्भर है कि उद्योगीकृत पूंजीवादी देशों के बाजारों में सोवियत मालों को पहुँचाने से रोकने वाली कृत्रिम बाधाएं कितनी जल्द और पूर्ण रूप में हटायी जाती हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सोवियत संघ ऋण देने में किन हितों को ध्यान में रखता है ?

पूंजीवादी देशों के विपरीत जहां स्वतंत्र पूंजी और निकम्मी उत्पादन क्षमता पायी जा सकती है, सोवियत अर्थतंत्र के नियोजित स्वरूप में अतिरिक्त संसाधनों के पाये जाने और फलतः उनके निर्यात की आवश्यकता की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

हमारे देश को सारे सुलभ साधनों की आवश्यकता राष्ट्रीय अर्थतंत्र के गतिशील विकास के लिए (१६७१-७५ की अवधि में औद्योगिक उत्पादन की औसत सालाना वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत रही जबकि अमरीका में ०.३ प्रतिशत थी) तथा अभूतपूर्व पैमाने पर सामाजिक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए होती है।

तब क्यों सोवियत संघ विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण देता है ?

क्या वाणिज्यिक हित से प्रेरित होकर ? नहीं इस दृष्टि से यह लाभप्रद नहीं होता। हम ८-१२ साल के लिए (कभी-कभी इससे भी ज्यादा मियाद के लिए) ब्याज की ऐसी दर पर ऋण देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंडी में ऐसी ही परिस्थितियों में वसूल की जाने वाली दर की आधी है। सोवियत अर्थतंत्र में लगाये गये धन से उससे अधिक लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, हम विकासशील देशों को ब्याज की ऐसी दरों पर ऋण देते हैं जो सोवियत संघ द्वारा पूंजीवादी देशों को अदा की जाने वाली दर की केवल आधी है।

क्या यह दुर्लभ मुद्रा प्राप्त करने का साधन है ? मुश्किल से ही। हम विकासशील देशों से इस बात का आग्रह नहीं करते कि वे ऋणों को परिवर्तनीय मुद्रा में चुकता करें—हम भुगतान के रूप में परंपरागत निर्यातों तथा सोवियत सहायता से बने कारखानों के उत्पाद के एक अंश को स्वीकार कर लेते हैं।

राजनीतिक शर्तें क्या होती हैं ? कोई भी नहीं, क्योंकि वह तो समाजवादी विदेश नीति के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा। क्या सोवियत संघ के पास ऐसे अतिरिक्त माल होते हैं जिन्हें सहायता के रूप में बेचना सुविधाजनक होगा ? हमारे पास यह समस्या ही नहीं है। उदाहरणार्थ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस में विद्युत इंजीनियरी और विद्युतीकरण मंत्री प्योत्र नेपोरोझ्नी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से विद्युत और इंधन ऊर्जा की आवश्यकता बिजली पैदा करने की क्षमता से ज्यादा तेज गति से बढ़ती रही है। हालांकि सोवियत संघ तेल और कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तथा ब्रिटेन, जर्मन संघ गणराज्य और फ्रांस मिलकर जितनी बिजली पैदा करते हैं उससे ज्यादा बिजली पैदा करता है, फिर भी उसके पास न तो इसमें बचत की कोई क्षमता है और न हो सकती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस तथ्य के बावजूद सोवियत संघ विकासशील देशों को कुल ११६ लाख किलोवाट क्षमता के बिजलीघरों के निर्माण में सहायता दे रहा है। दूसरे शब्दों में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के बिजलीघरों में जो टर्बाईन लगाये जा रहे हैं, वे बेखूबी स्वदेश में प्रयुक्त हो सकते हैं। विकासशील देशों के उत्पादन की अन्य शाखाओं के बारे में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि ६० प्रतिशत सोवियत ऋण अर्थतंत्र के इसी क्षेत्र को जाता है।

अंत में, क्या सोवियत संघ विकासशील देशों के अर्थतंत्रों में पांव जमाना चाहता है जिससे वह बाद में लाभान्वित हो सके? सोवियत संघ अपनी सहायता से विदेशों में निर्मित एक भी परियोजना पर न तो स्वामित्व रखता है और न नियंत्रण, न ही वह ऐसे नियंत्रण का प्रयास करता है। उन पर संबद्ध देश का ही एकमात्र और पूर्ण स्वामित्व होता है। यही नहीं, सोवियत विशेषज्ञ सोवियत नीति के अनुरूप स्थानीय आबादी के लोगों के बीच से विशेषज्ञों को यथासंभव शीघ्र से शीघ्र प्रशिक्षित कर देता है जिससे वे स्वतः परियोजनाओं को चला सकें।

तब आखिर सोवियत संघ किस लिए ऋण देता है?

सबसे पहले तो हम खैरात संबंधी किसी भी सुझाव को अस्वीकार कर दे सकते हैं। अल्जीरिया की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष होअरी बूमेदिएन ने कुछ साल पहले यह ठीक ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आज खैरात जैसी कोई चीज नहीं है और इसकी सारी चर्चा कथित खैरात पाने वालों के लिए अपमानजनक है।

सोवियत संघ विकासशील देशों को जो ऋण देता है तथा अन्य प्रकार के इमदाद पहुँचाता है, उसका कारण यह है कि वस्तुगत तौर पर उनके हित हमारे हितों तथा अंतर्राष्ट्रीयतावादी कर्त्तव्य सम्बन्धी हमारे विचार के अनुरूप हैं। सोवियत संघ जिस नीति का अनुसरण करता है वह उसके इस विश्वास से उद्भूत है कि शांति को सुदृढ़ करने, साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की एक न्याय-व्यवस्था की स्थापना करने का कर्त्तव्य विकासशील देशों के भागीदार बने बगैर तथा उनके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त किये बगैर सम्पन्न नहीं किया जा सकता।

क्या समाजवादी देशों के बीच व्यापार में आपसी हितों का पालन किया जाता है?

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के ढांचे के भीतर किसी सदस्य देश से सम्बन्धित एक भी फैसला उसकी सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्यों का आर्थिक साहचर्य तथा उनके सहयोग का अनवरत विस्तार राष्ट्रीय हितों पर ही निर्भर है। ऐसे सहयोग के अन्तर्गत उनकी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का सामंजस्य, उत्पादन के क्षेत्र में विशेषीकरण और सहयोग, पारस्परिक व्यापार का विकास आदि समाविष्ट होते हैं।

इस समय पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देश समाजवादी आर्थिक एकीकरण के सांगोपांग कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिससे असमान विनिमय, या दुसरे या दूसरों की कीमत पर किसी एक के लाभ की संभावना न रह जाये, तथा उनके आर्थिक विकास के स्तर को समान बनाने में मदद मिले। अन्य बातों के साथ-साथ पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों के बीच व्यापार में कीमतें सम्बद्ध पक्षों की आम सहमति से निर्धारित की जाती हैं, तथा अगर तालमेल की आवश्यकता होती है तो उसके बारे में भी ठीक इसी तरह सहमति पर पहुंचा जाता है।

समाजवादी बाजार की कीमतें वर्तमान विश्व बाजार की कीमतों से भिन्न होती हैं। एक तो वे अपेक्षाकृत कम हैं (उदाहरण के लिए सोवियत तेल की कीमत); दूसरे उनमें आकस्मिक उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं होती। पांच वर्ष की अवधि विश्व की मुख्य माल मंडियों में जो औसत कीमतें होती हैं, वे उन पर आधारित होती हैं। वे एक निर्धारित अवधि तक सुस्थिर रहती हैं, चाहे पूंजीवादी विश्व मंडी में जो कुछ घटित हो।

SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR LIBRARY Jangamawadi Math, Varanasi Acc. No. ......

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हमने सोवियत संघ से सम्बन्धित १०० प्रश्नों के उत्तर इस आशा के साथ प्रस्तुत किये हैं कि यह अपने पाठकों के साथ हमारे संवाद का आरंभ मात्र है। इस विषय का वाकई कोई आखरी छोर नहीं है। हम बाद के संस्करणों में आपके और आगे के प्रश्नों के उत्तर देंगे।

आप अपने पत्र इस पते पर भेजें :

नोवोस्ती प्रेस एजेंसी प्रकाशन गृह
"प्रश्न और उत्तर"
१३/५ पोद्कोलोकोल्नी पेरेउलोक
मास्को १०६०२८,
सोवियत संघ

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 3283

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative